श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: वह विदड्रॉ किया।...(**व्यवधान**)... उसके बारे में क्यों भूल जाते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: देखिए, please co-operate with me ...(*Interruptions*)... Statutory Resolution Dr. Murli Manohar Joshi ...(*Interruptions*)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: सर, यह तो मेरे साथ अन्याय है।...(**व्यवधान**)... आपने बिना नोटिस वाले को बोलने की परमीशन दी और मुझे नहीं दे रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Murli Manohar Joshi to move the Resolution .....(*Interruptions*).

प्रो॰ राम देव भंडारी: सर, मेरी बात सुन लीजिए।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: मैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप बैठिए।...(**व्यवधान**)... नहीं, आप बैठिए।

No, no. This is not the time ...(*Interruptions*)... Now, Dr. Murli Manohar Joshi to move the Resolution.

Statutory Resolution Seeking Disapproval of National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Ordinance, 2006 (No. 1 of 2006).

and

The National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill, 2005.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प उपस्थित कर रहा हूं कि: —

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 23 जनवरी, 2006 को प्रख्यापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

उपसभापति जी, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, जिसको एक अध्यादेश के द्वारा जल्दबाजी में लाकर कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं, जो मेरी दृष्टि से देश के, शिक्षा के, अल्पसंख्यक सभी समुदायों के लिए हानिकारक है। इसमें पहली बात तो यह समझ में नहीं आती है सात महीने के अंदर ही ऐसी क्या घटनाएं हो गई थीं, जिनके कारण यह अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी। जनवरी, 2005 में एक विधेयक पास होकर अधिनियम बना था और फिर जुलाई, 2005 में आप उसके लिए एक संशोधन ले आए और वह भी सारी चीजों को पलटने वाला

संशोधन। इस संशोधन को लाते समय यह कहा गया कि क्योंकि संविधान में एक संशोधन हो गया है, इसलिए अब जरूरी हो गया है कि एक अध्यादेश के द्वारा हम वह संशोधन विधेयक द्वारा लागू कर दें।

उपसभापति जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें यह कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में यह विधेयक लाया जा रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक की परिभाषा इस अध्यादेश के अंदर नहीं दी गई है। कौन अल्पसंख्यक है? पुराने संविधान के संशोधन में कहा गया था कि वे अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें संविधान में उसके अनुच्छेद 30 के अंतर्गत माना गया है। इसमें ये भाषाई और पांथिक दोनों प्रकार के अल्पसंख्यक हैं। अब इस सारे अध्यादेश को पढ़ने से यह पता नहीं चलता कि इसमें भाषाई और पांथिक, दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों के बारे में क्या अधिकार हैं। क्या भाषाई लोगों का निर्णय करने का अधिकार भी केन्द्र सरकार को होगा और इस आयोग को होगा? भाषाई अल्पसंख्यक, यह तो राज्य सरकारों का विषय है, वही इस पर निर्णय करते हैं, उनके बारे में संज्ञान लेना उनका काम है। लेकिन, कोई भी बात इसमें साफ-साफ नहीं की गई है कि भाषाई अल्पसंख्यकों का क्या होगा और धार्मिक अल्पसंख्यकों का क्या होगा? इस प्रकार से यह संघीय स्वरूप पर आघात करता है, पूरे फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर आघात करता है। यह भी बात गौर-तलब है कि किसी संस्था के बारे में जारकारी देने का काम, इकट्ठा करने का काम, खासतौर पर शिक्षा संस्थाओं के लिए उनका कौन प्रबंध कर रहा है, वित्तीय स्रोत कहाँ से आ रहे हैं, फाइनेन्सियल रिसोर्सेस कहाँ से आ रहे हैं, उनके बाकी जो कुछ कायदे-कानून, जिसके मुताबिक वह संस्था बननी चाहिए, वे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसकी पहले राज्य सरकार अच्छी तरह छानबीन करती है, लेकिन आपने उसके जो सारे अधिकार हैं उनको निलंबित कर दिया है, समाप्त कर दिया है। किसी भी संस्था की जांच के लिए, उच्च संस्था के लिए, उच्च शैक्षिक संस्थाओं के लिए अनेक संस्थाएं मौजूद हैं, जैसे यूजीसी मौजूद है, एआईसीटीई मौजूद है, आईएमसी मौजूद है और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भी एक संस्था मौजूद है, जो बार-बार बताता रहता है, उसका जो रजिस्ट्रार है, वह बताता रहता है कि कहां भाषाई अल्पसंख्यक हैं या कहां नहीं हैं, इन सब का आपने कोई अधिकार रखा ही नहीं, सबको समाप्त कर दिया है और वह सारा अधिकार आपने उठाकर एक आयोग को दे दिया है, जिसके पास शैक्षिक और बाकी जानकारियां प्राप्त करने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। जो पहले से ही देश में अल्पसंख्यकों का आयोग मौजूद है, उसके अधिकार का भी आपने अतिक्रमण कर दिया है। तो एक प्रकार से जितनी भी संस्थाएं बनी हुई हैं, जो शिक्षा के स्तर का और शिक्षा की उच्चतर क्वालिटी का, इन सब का निर्धारण करती हैं, उन सब को आपने समाप्त कर दिया। फिर इस बारे में इसमें कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है कि जो भी संस्था अल्पसंख्यक के रूप में आएगी, उसकी शिक्षा का स्तर कौन निर्धारित करेगा? उसमें अगर शिक्षा का स्तर गिर गया

तो अल्पसंख्यकों के साथ भी आप एक बड़ा भारी अपराध करेंगे और उनकी सारी शिक्षा को आप निम्नतर दर्जे पर स्थापित कर देंगे, कहेंगे कि यह सेकेंड ग्रेड है। तो उनके साथ आपने ऐसा किया है। विश्वविद्यालयों के अधिकारों का भी आपने अतिक्रमण कर दिया है। उनके स्टेच्यूट्स हैं, जिनके मुताबिक वे ऐफिलिएशंस देते हैं, संबद्धता देते हैं, लेकिन आपने उनके अधिनियम, परिनियम, इन सबको भी ताक पर रख दिया है। तो यह एक सवाल इसमें बहुत गहरा है।

दूसरे, आप इसमें केवल ऐफिलिएशन की समस्या क्यों लेते हैं? ऐफिलिएशन कोई समस्या नहीं है। मैंने 6 साल तक इस विभाग को संभाला है, ऐफिलिएशन कोई समस्या नहीं है, समस्या आती है छब्ब .छव व्हरमबजपवद ब्मतजपपिबंजम में और उसका अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक से कोई ताल्लुक नहीं है,? वह सबके लिए समान है। मेरे पास जितनी शिकायतें आती थीं, उनमें से अधिकांश बहुसंख्यक लोग, जिन्हें मेजारिटी इंस्टिट्यूशंस कहा जाता है, उनकी आती थी छब्ब की। छब्ब की जो व्यवस्था है, उसमें अपने आप में कुछ कठिनाइयां हैं। आप उनको देखें। उसको सरल किया जाना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं, उसमें भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, इससे मैं सहमत हूं, लेकिन छब्ब ही एक सबसे बड़ी चीज है कि जो सबसे पहले आपकी संस्था की गुणवत्ता और उसके रख-रखाव को निर्धारित करेगीउसके पास जमीन है या नहीं, वित्तीय साधन हैं या नहीं, अगर हैं तो कहां से आए हैं, कौन उनको दे रहा है, ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या फॉरेन मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसमें ये सारी बातें देखनी जरूरी होती हैं। तो छब्ब इसमें थोड़ा समय लगता है, इसको हम भी मानते हैं, हमने भी देखा है। इसलिए इसमें ज्यादा समय न लगे, इसके नियम साफ हों, उसमें पारदर्शिता हो, यह बात सारी संस्थाओं के लिए जरूरी है। इसमें आप यह क्यों कहना चाहते हैं कि छब्ब जल्दी सिर्फ अल्पसंख्यक संस्थाओं को ही मिले और बाकी को देर में मिलता रहे? यह तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि छब्ब मिलने की कठिनाइयां सारी संस्थाओं के लिए दूर होनी चाहिए, उसमें केवल 1अल्पसंख्यक का ही सवाल नहीं है। ऐफिलिएशन के बारे में भी यह आयोग करने की जरूरत नहीं है। आप देश में यह बातें क्यों पैदा करना चाहते हैं कि उच्च शिक्षा में भी अल्पसंख्यक अलग है, बहुसंख्यक अलग है? इस तरह से धीरे-धीरे आप न केवल शिक्षा के सैकुलर करैक्टर पर, बल्कि संविधान के सैकुलर करैक्टर पर भी आघात कर रहे हैं। जो फेडरल करैक्टर है, उस पर भी आप आघात कर रहे हैं और जो बेसिक फीचर्स का दूसरा हमारा सिद्धान्त है कि यह संविधान सैकुलर है, देश सैकुलर करैक्टर का है, उस पर भी आप आघात कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप जिन अल्पसंख्यकों के नाम पर यहां पर विधेयक लेकर आए हैं, आप उनके साथ भी अन्याय कर रहे हैं कि उन्हें आप एक अलग स्ट्रीम में जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह अलगाववाद को बढ़ावा देगोंशिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देगा, और क्षेत्रों में तो पहले से ही बढ़ावा दिया हुआ है।

मेरा अनुरोध यह है कि इस विधेयक का निरनुमोदन किया जाए और सदन इस पर गंभीरता से विचार करे। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो इसी सदन ने पास की है, उसके अंतर्गत उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, वह मेरे जमाने में पास नहीं हुई थी, वह श्री राजीव गांधी जी के जमाने में पास हुई थी, उसके अंदर जो सिद्धान्त हैं, आप उनका भी उल्लंघन कर रहे हैंशिक्षा समान हो, शिक्षा का स्तर अच्छा हो, शिक्षा में एक्सैसिब्लिटी हो, उस तरफ ध्यान दीजिए और उसके लिए आप अगर एक कम्प्रिहेंसिव विधेयक लाएं तो सदन उसका स्वागत करेगा, उसकी जरूरत है।

फिर आप कहते हैं कि यह इसलिए आप कर रहे हैं कि शैक्षिक सत्र शुरू होने वाला है और उस सत्र में आपको कोटा फिक्स करने के लिए इसकी आवश्यकता है। देखिए, सत्र जो शुरू होगा, उसके लिए कोई नई संस्था नहीं बन सकती क्योंकि सत्र शुरू हो रहा है जून, जुलाई या अगस्त में और इतनी जल्दी कोई नई माइनॉरिटी संस्था नहीं आ सकती। अगर आएगी भी तो 90603150 दिन यानी पांच महीने तो ऐसे ही लग जाएंगे और फिर उसमें कोई झगड़ा भी हो सकता है। अत: अभी कोई यह जरूरी नहीं कि चूंकि यह सत्र शुरू होने वाला है, इसलिए यह अध्यादेश लाना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मेरा सुझाव यह होगा कि आप इस पर गहराई से विचार कीजिए और उसमें जो कुछ आवश्यकता है, जिन संस्थाओं की बात आप कर रहे हैं। प्रोफैशनल संस्थाओं की, उनमें जहां जिस सहायता की जरूरत है, उसकी बात कीजिए। अल्पसंख्यकों की संस्थाएं आगे बढ़ें, वे अगर आगे मेन स्ट्रीम में आना चाहती हैं, उसके लिए जो कुछ करना हो, आप उस बारे में एक कम्प्रिहेंसिव बिल लेकर आएं तो सदन को कोई ऐतराज नहीं होगा, परन्तु इस तरह से आप अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश न करें।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं, सदन से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक का, इस अध्यादेश का इस समय निरनुमोदन किया जाए और इस पर एक बहुत अच्छा बिल सोच-समझकर लाया जाए, जो सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बने। देश की सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था, अल्पसंख्यकों की शिक्षा की वर्तमान अवस्था, इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप कुछ लाएंगे तो शायद उसका देश को ज्यादा लाभ होगा, अन्यथा यह विधेयक कोई काम नहीं करेगा। मेरा जितना अनुभव है इस मामले में, उसके आधार पर मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के लिए कोई सहायता नहीं देगा, इससे और झगड़े बढ़ेंगे और भाषायी तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के सवाल अलग से खड़े होंगे। इसलिए कृपा करके आप इसे वापिस ले लें, यही सबसे अच्छा होगा। धन्यवाद।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MD. ALI ASHRAF FATMI): Mr. Deputy Chairman, Sir, I beg to move:

> That the Bill further to amend the Naitonal Commission for Minority Educaitonal Institutions Act, 2004, be taken into consideration.

श्री उपसभापति: क्या आप इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: नहीं, सर, जब इसके ऊपर डिस्कशन होगी, तब ही श्री मुरली मनोहर जोशी जी ने जो कहा है—चूंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस को वापस लेने के लिए अपना प्रस्ताव दिया है, इसलिए डिस्कशन में जब और चीज़ें भी सामने आएंगी, जैसे आपने एनओसी के बारे में या ऐफिलिएशन के बारे में सवाल उठाए हैं या दूसरी अन्य जो भी आशंकाएं हैं, उन सभी पर हम यहां पर बात करेंगे।

The questions were proposed.

SHRI BALAVANT *ALIAS* BALAPTE (Maharashtra): Sir, if you are going to adjourn the House for lunch at one o'clock...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You speak for ten minutes. Then you can continue after lunch. Your party has 42 minutes. Two speakers are there. So, adjust your timings.

SHRI BALAVANT *ALIAS* BAL APTE: Sir, earlier, when the original National Commission for Minority Educational Institutions Bill was moved and discussed in this House, it was necessary for me to rise and oppose the said Bill for various reasons. Now, an amendment has come to the same Bill. It is almost in a pattern, which the present ruling party has followed throughout—using the law to upturn the law. They have been doing it right from the 42nd Amendment when a judicial decision of the Allahabad High Court was to be upturned by even amending the Constitution. Sir, this has happened again and again. When the question of maintenance to the destitute women came up, simply udner section 125 of the Code of Criminal Procedure, the Supreme Court said something --it did not rule—it only said something in the case of Shah Bano, and you changed the law to bring in a new legislation to control, by way of protection, the rights of the Muslim women. Sir, when the Supreme Court declared that the Aligarh Muslim University cannot be a minority institution, you went ahead and changed the law, taking it upon yourselves to decide which a minority institution is, when the Constitution mandates that it is for the people of the minority to establish it. When the IMDT Act was invalidated by the Supreme Court saying that it is permitting an invasion of this country, you subverted that decision by promulgating an order, whereby, again, a privilege was granted to the infiltrators in Assam—which is not available to the rest of the country—to protect the infiltrators, so that they will vote for you. Sir, the Supreme Court has said that in so far as establishing and running educaitonal institutions is concerned, it is a right

equally available to the citizens of this country, irrespective of whether they belong to minority or majority. In spite of that, in the teeth of the observations of the Supreme Court that such a kind of special treatment will be in the nature of reverse discrimination which is contrary to article 14, you brought this legislation, with an ulterior motive, and that legislation is now being further amended to suit certain immediate needs for, again, convenience of your vote bank politics. Therefore, Sir, this House has to think whether promulgation of laws should be permitted to subvert the basic tenets of laws, and in the circumstances whether to permit this Bill to be passed.

Sir, the problems of this Bill begin with a reference to the minority which, incidentally, is not defined in the Constitution or in this Bill. The Supreme Court has expressly held that the concept of 'minority', whether religious or linguistic, is necessarily State-specific. But, here, the Central Government wants to usurp that power, which hits directly at the federal structure of this country, and decide who is a minority in what State, or who is a minority at the all-India level, because, this law expressly provides that the question of minority will be decided by the Central Government.

Sir, the question arises as to what this concept of 'minority' is. In our country, this concept needs to be examined today, because the very protection, which was necessary for minorities in various countries, is being used to be converted into a privilege when a sizeable section of the population claims that status. The concept of 'minority' socially, is not the concept of fifty-one versus forty-nine. But we have failed to appreciate this.

Sometimes, I ask a question to myself whether the French can be treated as minority in Canada. Are they so treated? Or whether the Scots are treated as minority in England or the Germans are treated as minority in Switzerland or the French in Switzerland. Therefore, I believe that this concept of 'minority', which the Central Government has taken upon itself to decide according to the exigencies of its political convenience, ought to be debated. Until then, all this pandering in the name of minorities ought to be halted.

Sir, when the new Ministry was established for minorities, the Minister-in-charge said that 'this is not a question of only religious minorities. I am concerned with linguistic minorities also and I am concerned with the fact

that there are several States in this country where the Hindus are also a minority.'

Sir, the question is, whether at the all-India level, the privileges available under this enactment will be available to the Hindus because they are a minority in some areas. In such a situation, therefore, the Central Government, trying to use the word 'minority' to protect certain sections for the purposes of its vote-bank politics, is regretable. This Bill is permitting that, and, therefore, I am opposing this Bill.

Now, Sir, coming to the Bill proper, I find that every time thre is an unholy haste and with such unholy haste follows repentance in leisure. They promulgated an Ordinance, when it was not necessary, in November, 2004. Immediately, the same Bill was passed. So, the Bill could have been directly passed in the Lok Sabha and Rajya Sabha in December, 2004, which we did. Within six months, you moved an amendment. That amendment was referred to a Standing Committee. That Standing Committee took its decision within three months. But you didn't have time to wait for that report also. The Standing Committee Report came on the 6th of December, and yet, you promulgated an Ordinance before that. What was the need? It is said that before the next academic year, we should have a smooth procedure. One month would have made some difference when the academic year begins somewhere in July-August. These days, in professional colleges, the session starts in September. So the whole gamut is for the purpose of permitting professional colleges, run by minority institutions, to make money. This is not in the interest of minorities, not in the interest of minority students.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Member, you have spoken for nine minutes. You can continue your speech after lunch. The House is adjourned to meet at 2 o'clock.

The House then adjourned for lunch at one of the Clock.

The House re-assembled after lunch at two minutes past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Bal Apte.

SHRI BALAVANT *ALIAS* BAL APTE : Thank you, Sir, for permitting me to resume my speech and, therefore, I believe that when there is a break, there is always a joining time which I should get. Sir, I was mentioning about this Bill which is before this House for consideration

and there I have already said that it proceeds giving an untrammelled power to the Central Government to decide who is a minority. Sir, this question has bogged us for the last fifty years and everybody, in a way, has avoided giving a clear-cut answer. Sir, when the question of admissions to these medical and engineering colleges came and when the Supreme Court tried to control the matters of merit and fees, the question of minority institutions and their rights came. Therefore, the Supreme Court expressly referred the question as to who should be considered a minority apart from other questions to a larger Bench. Initially, they referred it to a constitutional Bench, then to seven judges, then to nine judges and then to eleven judges. Then we have those three well-known judgements-one by 11 judges T.M.A. Pai, then the second explaining judgement in the Islamic Institute by 5 judges and then the third judgement in A.P. Inamdar by 7 judges. They did everything else and created new problems for education, but they avoided deciding the basic question which was raised in the beginning as to what is a minority. That question still remains undecided somewhere in the records of the Supreme Court, and here we are presuming something and going ahead without either statutory or a constitutional authority. Sir, I have already said that this kind or reverse discrimination is impermissible in law. And, which we are blatantly doing for narrow partisan ends which are not in the interest of the nation. Sir, as I said, the Bill itself has several infirmities which again strike at the existing law. Earlier, you had a Schedule of the Universities any of which could be chosen by a minority institution and the chosen universities were very significant—the University of Nagaland, the University of Mizoram, the NEHU, that is, North Eastern Hill University—as if they were the premier Universities of this country to which a minority institution would like to affiliate itself. But, if the creation of that Schedule was arbitrary and *mala fide*, the removal of that Schedule is not only totally arbitrary but is also unconstitutional.

Sir, we are aware that all these institutions seek affiliation to universities and it is and the Act, at least, in its letter, that the affiliations by the universities will depend upon their own statutes, regulations and controls. But, here, while giving an uncontrolled right to the minority institutions to get affiliated to any university, the Central Government has forgotten that

these universities are established by statutes, are controlled by statutes, and the University Acts are codes in themselves. They provide for affiliation, for dis-affiliation; they provide for grievance; they provide for an appeal by the aggrieved party to an appellate authority, ultimately, which is either the Chancellor, who also happens to be the Governor or the Visitor who also happens to be the President. A higher authority is already provided there and appeal is provided already there, and this complete code in so far as the State universities are concerned, is a code enacted by the State laws. Now, while giving an appellate power to the Central Commission above the authority established by the States, by law within the laws of the State, is clearly contrary to the federal principle, is clearly illegal, is clearly unconstitutional because it hurts the basic structure of the Constitution. Technically, the Commission will be enjoying authority, possibly above the President. Because in Central universities , if the President is the highest authority, then, the Commission will sit in judgement over what the President decides. This is not only anomalous, this is improper, indecent and, obiously, unconstitutional. You cannot abrogate State laws under the Constitution without following the Constitutional requirements. We have a structure where the Central Legislature has larger powers, yes. But, those powers are to be used; they cannot be usurped and they cannot be used only by enacting a law here. The Constitution provides for an elaborate arrangement where there is a conflict between the two laws, were there is a State a law already occupying the field. But, you don't care to do that because you are not bothered about law; you are bothered about your votes. That is why, you include a definition of 'minority'. You include a definition of the educational rights of minorities in the Act. And the wording of that is identical with the provisions of article 30. If article 30 is there guiding, controlling fundamentally, why do you need to repeat that as a matter of definition in your enactment? It caters to what need, to what requirement? The need is to state something , which is abvious, saying that I am doing it for you. The malice, therefore, in this legislation us apparent by these very small incidents. The Rajya Sabha had referred this Bill to the Standing Committee and it had made very vaild, very reasonable suggestions. There is a rule of 60 days ceiling, which says that if an application is made and if it is not responded within the period, you should assume that your application is granted, such a

rule is always misused. We have innumerable examples in the town planning laws where a similar provision is there that you give your plan of development, and, if the authority does not decided within a particular number of days, then it will be assumed that your plan in approved, and, the authority which wants to favour has to do nonthing but to sit on that plan for those sixty days. Same thing can happen here. Therefore, the Standing Committee gave a very reasonable suggestion. It suggested that instead of sixty days, make it a little longer; instead of two months, make it three months. But you did not accept such a reasonable suggestion because you don't want to be reasonable.

The Second suggestion is about restrictions. A privilege is granted to get yourself affiliated to any university of the country. Now, there are obviously geographical constraints that really don't permit an institution in Kerala to be affiliated to a university in Nagaland. Therefore, a very fair suggestion was there that you can get affiliated to any university, but it should be within geographically contiguous limits. That would have been legal also. The present provision which is unreasonable, and, which ignores the Standing Committee's recommendation is incidentally illegal, which I have already pointed out. You cannot go beyond that region; you cannot go beyond the geographical limits of the State. But they maintained that Section 10A, as it is.

Then, there is one more dangerous provision in the present enactment, namely, that the Commission can intervene in any proceeding in any court of law in the country. Such a right will give the Commission such a power and such a temptation to misuse that the Commission will run from one court to another intervening; to do something convenient to the institutions, not for universities. This will not yield fair results. This will not yield fair treatment to the minority. This will support mismanagement, maladministration and wrongdoing in the name of intervention. Therefore, there are suggestions about it. Where such a power is given, that power is that you can intervene on the invitation of the court where the litigation is pending. And, a court would certainly call a Commission to assist it in certain basic conflicting issues. But, no, you want to go and intervene everywhere so that you can, in a way, interrupt the course of justice.

Now, an all India authority intervening in such a manner with a right governed by the statute will make the concept of judicial review for what it is not. You will be interfering with the judicial review, which really is the right of the citizens. A citizen has a right to intervene in any proceeding,

with the permission of the court, again, if he believes that the litigation is going to affect his rights. But, not without permission of the court, not without invitation of the court. You are going there without invitation.

Then, Sir, there are no safeguards in the legislation to prevent misuse of this concept of minority status. Minority status has been largely misused in the States where engineering and medical colleges have flourished during the last ten years. You claim to be a minority in Andhra Pradesh, you come from the adjacent Karnataka, you claim to be a minority in Mumbai, and, in your college, with a minority status, 95 per cent students don't belong to your community because it is really established there. It is not a minority institution at all. I had mentioned last time also that in places like Mumbai, minority institutions are 70 per cent of the total institutions. The very concept of minority is stood on its head. and, therefore, that is misused. They are given powers to admit 50 per cent students of their own community and 50 per cent students from the general list. If you don't have 50 per cent students of your own community, you have only 20 per cent or 10 per cent or sometimes you ignore your own community, because if you preserve those seats, you earn money. So, 40 per cent seats, which are reserved for the minority community, are used by the minority institutions for non-minority and non-merit students, and money is earned. Several such cases are there in Maharashtra, in Andhra Pradesh and in karnataka. Therefore, there has to be a safeguard provided by the statute to prevent such kind of a misuse of the status which will disentitle you, if the misuse is proved, to be a minority institution, because you are not helping the minority community.

Lastly, I would repeat what I had said earlier that this legislation is not for the benefit of minorities. This legislation is for the benefit of those who are running these institutions to earn money. They are a money-making project. We have now, as we had sugar *samraats* in Maharashtra and in Andhra Pradesh, *Shikshan samraats*. So, you are working for them in the name of minorities you are defrauding the people, you are defrauding the minorities. Please don't do it. Please stop this legislation. Thank you, Sir.

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी, 11 नवंबर, 2004 को National Commission for Minority Educational Institutions Bill अमल में आया था। मैं इस बिल की हिमायत के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्ष 2004 में कौमी कमीशन बराए अक्किल्लियती तालीमी इदारा कानून पास हुआ था, लेकिन इस कानून के निफाज़ के बाद जो हालात सामने आए, जो तजुर्बात सामने आए, उनके पेशे-नज़र इस कानून का मैं मज़ीद इस्लाह

की जरूरत महसूस की गई थी। यह जरूरत भी महसूस की गई कि इस कानून का स्कोप और बढ़ा दिया जाए और जहां-जहां कुछ कमियां वाकी हैं, उन कमियों और खामियों को दूर कर दिया जाए। इससे पहले एक चीज यह थी कि 2004 के कानून में अक्किल्लियती तालीमी इदारों को सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज़ का हक दिया गया था और उन 6 यूनिवर्सिटीज़ में से 4 यूनिवर्सिटीज़ नॉर्थ-ईस्ट में थीं। जहां तक मुस्लिम और सिख माइनॉरिटीज़ का ताल्लुक है, उनकी बड़ी तादाद शिमाली हिंदुस्तान में आबाद है और शिमाली हिंदुस्तान में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको इलहाक का हक दिया गया था। चूंकि अक्किल्लियतें पूरे मुल्क में फैली हुई हैं, इसलिए इन इलाकों की मुस्लिम और सिख अक्किल्लियतों को इस एक यूनिवर्सिटी के इलहाक के सिलसिले में दुश्वारी पेश आ रही थी। इसी वजह से अब इस तरमीमी बिल में, जो इस वक्त हमारे सामने है, 6 यूनिवर्सिटीज़ की बजाय मुल्क की हर युनिवर्सिटी के साथ इलहाक का हक देकर इस कमी को दूर किया गया है।

सर, जहां तक तालीम का सवाल है, हाउस मुकम्मल तौर पर इस बात पर सहमत है कि तालीम हर हिन्दुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए और तालीम के बगैर न मुल्क तरक्की कर सकता है, न मुल्क के आवाम तरक्की की राह पर चल सकते हैं, इस मुत्तफिका फैसले के बाद इस बिल पर यह बहस हो रही है कि यह बिल माइनोरिटीज़ को कितना फायदा पहुंचाएगा या माइनोरिटीज़ के साथ कितना विश्वासघात किया जा रहा है। सही मायने में ऑपोजीशन के लोग भी यह चाहते हैं और हुकूमत के लोग भी यह चाहते हैं कि माइनोरिटीज़, जो तालीमे एतबार से मुकम्मल तौर पर पसमान्दा हो चुकी हैं, उनकी पसमान्दगी को दूर करके कौमी मुख्यधारा में माइनोरिटीज़ को भी मेजोरिटी के साथ शाना-बशाना खड़ा कर दिया जाए। यह है वह उद्देश्य, जिसकी बुनियाद पर हाउस में दोनों साइड से अपनी-अपनी चिन्ताएं भी व्यक्त की जा रही हैं और अपने-अपने सुझाव भी दिए जा रहे हैं। मैं डा॰ मुरली मनोहर जोशी जी को बहुत ही गौर से सुन रहा था और उनकी चिन्ताओं के पीछे भी यही बात साफ तौर पर जाहिर हो रही थी कि वे भी ईमानदारी के साथ मुल्क में माइनोरिटीज़ का तालीमी भला चाहते हैं और तालीमी भलाई के लिए उन्होंने गवर्नमेंट के सामने अपने कुछ सुझाव रखें हैं। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि कश्मीर की वादी से लेकर कन्याकुमारी की सरहदों तक पूरा हिन्दुस्तान एक रंग में दिखलाई दे, तरक्की की नहरें मुल्क की हर कौम के दरवाजे तक पहुंचे, तभी हम हिन्दुस्तान का एक खुबसूरत सपना देख सकते हैं। उन्होंने अपने बयान में इस बात पर तशबीश जाहिर की कि यह बिल मुल्क में लोगों के बीच दरार पैदा कर सकता है और अकलियत और अकसीरियत में मजीद खाइयां पैदा होंगी और इससे लोगों की तशवीश में इज़ाफा होगा।

जहां तक मुल्क के संविधान का सवाल है, तो मुल्क का संविधान और देश का दस्तूर इतना महान है कि इसने देश में रहने वाली किसी कौम को, चाहे वह किसी मजहब से ताल्लुक रखती हो या किसी लिसानी अकलियतों-अकसीरियत का दर्जा रखती हो, सबके घर तक मसावात की रौशनी पहुंचाने का इन्तजाम किया है। मगर इस हकीकत के बावजूद शायद हमारा हाउस इस

हकीकत से इनकार न कर सके कि जब हम अमल में उसी दस्तूर को देखते हैं, तो वह दस्तूर अमली तौर पर जब नाफिज होता है, तो एक बहुत बड़े तबके को, जिसको माइनोरिटी के नाम से याद किया जाता है, हम महरूम देखते हैं। इसलिए कि नफाज मुल्क की आजादी के बाद से ही दस्तूरे हिन्द का हो रहा है और तालीमी एतबार से मुल्क की माइनोरिटीज, बिलखुसुस मुल्क की सबसे बड़ी माइनोरिटी, जिसे हम मुस्लिम माइनोरिटी कहते हैं, तालीमी एतबार से जिस हद तक पसमान्दा हो गई है, अगर मुल्क के दस्तूर की रौशनी में जिन हाथों में हुक्मरानी का पॉवर था और जिन हाथों से इस दस्तूर को नाफिज होना, आलमे अमल में आना मुमकिन था, शायद उनसे कहीं-न-कहीं ऐसी गफलत जरूर हुई है, जिसके नतीजे में आज माइनोरिटीज़ की पसमान्दगी को दूर करने के लिए अज़-सरे-नौ हाउस में यह बहस हो रही है। अगर माइनोरिटीज़ के साथ भी वही सलूक किया गया होता, तालीमी इदारों में बाधाएं रोकने के लिए, जिस तरह दूसरे सेक्शन में किया गया है, तो शायद न आज इस बिल की जरूरत पड़ती, न इस चिन्ता की जरूरत पड़ती। यह बिल अपने आप में खुद इस बात को दर्शाता है कि मुल्क की आजादी के बाद से लेकर अब तक मुल्क की माइनोरिटीज़ के साथ कहीं-न-कहीं कजरवी अपनाई गई है, बिलखुसुस तालीमी मैदान में। इसलिए आज सबकी चिन्ताएं इस बात पर मरकूज होकर रह गई हैं कि माइनोरिटीज़ की तालीमी पसमान्दगी को दूर करने के लिए ऐसे दस्तूरी उसूल लाए जाएं, बिल की शक्ल में, जो माइनोरिटीज़ की तालीमी पोजीशन को महफूज़ करते हुए इन्हें भी मुल्क की मेजोरिटी के साथ तालीमी मैदान में शाना-बशाना खड़ा होने का मौका दे सके। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इसी सिलसिले में जो यह बिल आया है, इसे गवर्नमेंट का अहम फैसला अकलियतों के तालीमी फरोग के लिए हम मानते हैं। मगर इस तरह के और भी फैसले इस से पहले आए हैं, इस से इंकार नहीं किया जा सकता। ''मरीजे इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की।'' बहुत अच्छे-अच्छे फैसले आए, बहुत अच्छे-अच्छे कमीशन बने, मगर बात वहीं आकर रुक जाती है कि अमल कौन करेगा? काश, अमल हो गया होता तो आज इस तरह की न चर्चा करने की जरूरत थी, न इस तरह का बिल लाने की जरूरत थी। आज मैं हुकूमते हिंद से यह कहना चाहूंगा कि आप यह बिल लाए हैं, मुबारक कदम है, नेकनीयती नजर आ रही है, मगर इस बिल के पास हो जाने के बाद आप को इस का भी जतन करना पड़ेगा कि जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को ईमानदारी के साथ दूर किया जाए। मैं समझता हूं कि यह जो कमीशन बना है, इस कमीशन के जो अख्तियारात हैं, शायद उन अख्तियारात की रुह और मंशा यही है कि जो बाधाएं आती थीं, उन बाधाओं का निष्कासन नहीं होता था। अब अगर वे बाधाएं आती हैं और लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं तो उन शिकायतों पर ईमानदारी के साथ गौर किया जाएगा व उन शिकायतों को दूर कर के मुख्य धारा में मुल्क की बड़ी अकल्लियत को भी लाया जाएगा। इस से अच्छी बात क्या हो सकती है कि अगर सब को समान दर्जा अमली तौर पर दिया जाए। मैं दस्तूरी तौर पर नहीं कह रहा हूं। जानबूझकर यह जुमला बोल रहा हूं, इसलिए कि दस्तूर ने कहीं कोई भेदभाव नहीं किया है, मगर तालीम का इतना अप-डाउन मुख्तलिफ समुदाय में यह बतला रहा है कि कहीं-न-कहीं तास्सुबाना रविश अख्तियार कर के लोगों ने एक बहुत

बड़े तबके को तालीम से महरूम कर दिया है। बकिया इस में जितने भी सेक्शंस हैं, सब पर मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। हरेक सेक्शन और दफा में इस बात की कोशिश की गयी है कि तालीमी अकल्लियती इदारों को तहफ्फुज देने में किसी तरह की कोई कमी वाकयी न होने पाए। मगर एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जिन इदारों को आप मंजरी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप दीजिए और लोगों को उत्साहित कीजिए कि लोग ज्यादा-से ज्यादा इदारे खोलें। मैं तो इस से पहले भी कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं कि मुस्लिम इलाकों में खुसुसी तौर पर थाने खोलने पर ज़ोर दिए जाते है, तालीम के इदारे खोलने पर जोर नहीं दिए जाते। काश, तालीमी इदारे खोलने पर जोर सर्फ किया गया होता तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे उन मुजरिमाना हरकतों पर कदगन लगता जो मुजरिमाना हरकतें सिर्फ मुसलमानों में नहीं, नॉन-मुस्लिमों में भी पाई जाती हैं और उस की वजह सिर्फ और सिर्फ तालीम की रोशनी से महरुमी है। आदमी जब तालीम हासिल कर लेता है तो इज्जत और बेइज्जती की परिभाषा को पहचानता है, गद्दारी और वफादारी की परिभाषा को पहचानता है, हकूक देना और दिलवाने की परिभाषा को पहचानता है।

आज तालीम के फरोग के सिलसिले में यह जो कदम उठाया जा रहा है, अगर इस पर ईमानदाराना अमल हो गया, मैं इस बात को बार-बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि परेशानी बिल लाने में हमारे लिए नहीं है, परेशानी ऑर्डिनेंस पास करने में हमारे लिए नहीं है, परेशानी तो आलमे अमल में लाने की है। जब तक आलमे अमल में यह बिल नहीं आएगा तब तक कितना ही खूबसूरत बिल और कितने ही हुकूक की दुहाई देकर कोई ऑर्डिनेंस पास किया जाए, मैं समझता हूं कि उस का नतीजा पोजिटिव निकलने वाला नहीं है। पोजिटिव निकलने के लिए मैं इस बिल पर अपनी आखिरी बात अर्ज करना चाहूंगा कि तालीमी इदारे तो हम खोल देंगे, मगर तालीमी इदारे नाम जमीन के एलॉटमेंट का नहीं है, बिल्डिंग की खूबसूरती का नहीं है, चैयर और डैस्क का नहीं है बल्कि उस में पढ़ने वालों के जरिए से तालीमी इदारा पहचाना जाता है। आज खुसूसियत से मैं मुल्क की सब से बड़ी मायनोरिटी, मुस्लिम मायनोरिटी की बात कहना चाहूंगा, यह देखकर हमें निदामत भी होती है और अफसोस भी कि मुल्क में मुस्लिम मायनोरिटी का तनासुब तालीमी एतबार से बहुत ही पिछड़े बल्कि अति पिछड़े लोगों से भी ज्यादा गिरती चली जा रही है। इस ही वजह क्या है, क्यों है? मायनोरिटी खुद तालीम हासिल करना नहीं चाहती है या उन को तालीम के मवाके नहीं दिए जाते, इस बात को ईमानदारी के साथ लेना होगा। कुछ तो ऐसा है कि लोग अपनी गुरबतो अफलास की बुनियाद पर तालीम के इदारों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। सब से बड़ी बात यह है कि जब तक गुरबत का खात्मा नहीं होगा आदमी तालीम की बात क्या सोचेगा? आज जिन-जिन इलाकों में सनअती इदारे हैं, इंडस्ट्रियल इदारे हैं जैसे अलीगढ़ वहां ताला बनता है, मुरादाबाद वहां पीतल बनती है और मुबारकपुर, आजमगढ़, पूर्वांचल, बनारस-इन एरियाज में बुनाई का काम

होता है, साड़ियां बुनी जाती हैं। मिर्जापुर और भदोही में कारपेट बनते हैं। हम देखते हैं कि और आप भी देखते हैं कि इसमें छोटे-छोटे बच्चों, 10-10, 12-12 साल के बच्चों का इस्तेमाल होता हैं। वे बच्चे सौ, दो सौ या तीन सौ रुपए महीने पाते हैं। मां-बाप पेट की आग बुझाने के लिए उन तमाम बच्चों को उन इदारों में डाल देते हैं।

अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 10 साल का हिन्दुस्तानी बच्चा कालीन बुनने के लिए पैदा हुआ है या स्कूल जाने के लिए पैदा हुआ है, इसलिए कि यह 10 साल का बच्चा एक मजदूर की शक्ल में दिखलाई दे रहा है? अगर मजदूर भी हो, मगर पढ़ा-लिखा हो, तो हिन्दुस्तान की तस्वीर बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे सामने आएगी। आज हम इस बात पर बेपनाह रुपया-पैसा खर्च करते हैं कि हम मेजंइसपीमक हों, हम आगे बढ़ें। नतीजे में हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। मगर, यही पैसा अगर हम इन गरीबों की तालीम पर खर्च कर दें और इन गरीबों को तालीमयाफ्ता हिन्दुस्तानी बनाकर खड़ा कर दें, तो मेरा यह मानना है कि वह तालीमयाफ्ता हिन्दुस्तानी जितनी रकम उसके ऊपर मुल्क की नेशनल प्रॉपर्टी के तौर पर लगी है, वह बच्चा खुद नेशनल प्रॉपर्टी बनकर अपने शुल्क के इज्जत-ओ-वक़ार के आसमान तक पहुंचाएगा। वे बच्चे, जो कालीन बुन रहे हैं, बुनकरी कर रहे हैं या पीतल और ताले का कंाम रहे है, भट्ठियों में काम कर रहे हैं या मजदूर बन कर भ्ज पर काम कर रहे हैं, आखिर उन बच्चों को कैसे स्कूल भेजने के लिए उत्साहित किया जाए, मेरे सामने यह एक बड़ा, बुनियादी और अहम सवाल है, इसलिए कि तालीम अज़हद जरूरी है। गवर्नमेंट ने आठवीं क्लास तक बिना फीस की तालीम कर दी है। गवर्नमेंट ने दोपहर के खाने का इन्तज़ाम भी कर दिया है। उसमें न तो माइनॉरिटी का कोई सवाल है और न ही मेजॉरिटी का सवाल है। मगर सबसे पहला सवाल उस गुरबत-ओ-अफलास का है कि जिसे एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा हो, वह तालीम की रोशनी कहां से हासिल करेगा, स्कूल कैसे पहुंचेगा? आपने तो स्कूल खोलने का अधिकार दे कर यकीनन एक बड़े काम की तरफ अपना हौसला दिखलाया है, मगर जब तक आप स्कूल जाने वालों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे, उनको स्कूल तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो स्कूल खोलने के बाद क्या हम उनमें इंसानों के बजाए जिन्नातों और भूतों का बसेरा करना चाहते हैं?

हम आपसे अर्ज करना चाहते है कि ये बच्चे, जो दो सौ या तीन सौ रुपए महीने पर काम कर रहे हैं, इनके लिए एक तरीक़ा और उपाय यह हो सकता है कि मरक़ज़ी हुकूमत और सुबाई हुकूमतें इस पर ग़ौर करें कि जितना पैसा उन बच्चों को सिर्फ पेट भरने के लिए दिया जाता है कि या तो वे पढ़ें या अपना पेट भरें। अगर से दोनों हुकूमत आधा-आधा पैसा अपने ज़िम्में करके उन बच्चों के लिए वज़ायफ मुकर्रर कर दें, तो ऐसी सूरत में वह नन्हा-सा बालक तालीम हासिल करके एक अच्छा हिन्दुस्तानी भी बन सकता है और तीन वक्त, दो वक्त की रोटी, जो उसे नहीं

मिल रही है, जिसकी वजह से वह स्कूल नहीं जा पर रहा है, उसके पेट की आग भी बुझ सकती है।

मैं तो अक्सर यह कहा करता हूं कि हमारे मुल्क में गांधी जी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू और इस तरह की जितनी शख्सियतें, चाहे इधर से मुल्क की खिदमत के लिए पैदा हुई हों या उस साइड से मुल्क की खिदमत के लिए पैदा हुई हों, इन शख्सियतों के पेट में अन्न और पानी गया था, सुविधाएं थी, जिनकी बुनियाद पे वे तरक्की करके मुल्क का निशान और मुल्क का स्लोगन बन गए थे। आज के ये बच्चे, जो मारे-मारे फिर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि इन बच्चों में कौन गांधी जैसा ज़ेहन रखता है, कौन नेहरू जी जैसा ज़ेहन रखता है और कौन मौलाना आज़ाद जैसा ज़ेहन रखता है। मगर हम यह जानते हैं कि भारत के ज़मीर-ओ-ख़मीर से पैदा होने वाला हर हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तान को इज़्जत के आसमान तक जरूर पहुँचा देगा, इसलिए कि उसके जिंस में यह बात शामिल है, उसके खून में यह बात शामिल है। शर्त यह है कि उसको मौका मिले और उसे मौक़ा देने के लिए सिर्फ स्कूल खोलना ही जालमी नहीं होगा, स्कूल तक पहुँचाने के लिए उन्हें वे लाज़मी सुविधाएं भी देना जरूरी होंगी, जिनकी बुनिसाद पर गरीबों को उत्साहित करके स्कूलों तक पहुँचाया जाए। तब यही गरीब जिसके हाथ और पैर की कमाई के जरिए आज हिन्दुस्तान की फसलें लहलहा रही हैं, उसके तामीर-ओ-तरक्की के नक्शे से हिन्दुस्तान मज़बूत होता जा रहा है, अगर उसके पास ईल्म का भी हुनर हो जाएगा, अगर उसके पास तमद्दुन और कल्चर भी आ जाएगा, तो इतना बड़ा मुल्क, जो अपनी संस्कृति में विशाल है, जो अपनी तहज़ीब में लासानी है, जिस मुल्क का नेचर ही उस मुल्क के ईल्म और अमल को दुनिया में उजागर करता है, अगर इन बच्चों पर थोड़ी-सी मेहनत हो जाती है और इन बच्चों को स्कूल का मुंह इस तरह से दिखाया जाता है कि उनके पेट भी भरें और वे तालीम भी हासिल करें, तो मै समझता हूं कि यह बिल भी कार-आमद होगा और हुकूमत की पॉलिसी भी कार-आमद होगी।

मैं आख़िरी जुमला अर्ज करके अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूं। मैं ऐसी सूरत में इस बात पर फिर बल दूंगा कि उनको दो सौ या तीन सौ रुपए महीने में मिलते हैं। जब उनके घर पर जाकर कहा जाए कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो, तो वे कहते हैं कि साहब पेट की आग बुझाएँ या स्कूल जाएँ और भी परेशानियां और बाधाएं हैं। ऐसे गरीबों को हमने देखा है कि रात-रात भर रिक्शा चलाते हैं और उस कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं।

सर, मैं अपना ही एक वाकया आपके सामने रखना चाहूंगा। बरसात का समय था, झारखंड में एक शहर है हजारीबाग, मैं वहां बस स्टैंड पर उतरा और वहां से दो किलोमीटर पर महल्ला मटवानी जाने के लिए रात के दो बजे मैंने एक रिक्शा किया। उस जमाने में रिक्शा वाला डेढ़ रुपया लिया करता था। इतनी झमाझम बारिश हो रही थी और वह आदमी रिक्शा चला रहा था। जब मैं घर पर पहुंचा, तो मैंने उससे पूछा कि आप और क्या करते हो? उसने कहा कि बाबू जी, मैं रात में, दिन में रिक्शा चलाता हूँ और अपने बच्चों को, बड़ी ख्वाहिश है मेरे दिल में, कि अच्छी से अच्छी तालीम दिलवा कर उनको मुल्क का सेवक और इल्मो-अदब के मैदान में उनकी जिंदगी को निखारूं। मैंने

उसको डेढ़ रुपये के बजाय दस रुपये दिए, मगर ये दस रुपए उसके मुस्तकबिल को तो नहीं संवार सकते थे। अलबता उसकी ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि कितने लोग हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, मगर हाय रे, पेट की मार कि भूख की आग से तड़पता हुआ बचपन बेहतर जवानी के लिए महरूम हो जाता है। अगर हम कुछ ऐसा कर सकें कि जिन बच्चों को ऐसी छोटी-छोटी जगहों पर सौ रुपए, दो सौ रुपए हासिल करने के लिए पेट की आग बुझानी पड़ती है और इल्म जैसी महान शक्ति से वे बच्चे वंचित रह जाते हैं, अगर यही रकम सेंट्रल गवर्नमेंट और शुबाही गवर्नमेंट आधी-आधी अपनी साइड से मुहैया करवा दें ऐसे बच्चों के लिए, तो उनके पेट की आग भी बुझ जाएगी और आप जो इल्म का सपना अपना बनाना चाहते हैं, वह भी साकार हो जाएगा।

सर, इस बिल की हिमायत करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई ऐसा माहौल पैदा कीजिए कि जन-जन में यह नारा गूंजे-''पढ़ो, लिखो, इंसान बनो, भारत की पहचान बनो''। थैंक यू, शुक्रिया।

مولانا عبیداللہ خان اعظمی ''مدھیہ پردیش'' : اُپ سبھاپتی جی، ۱۱رنومبر، ۲۰۰۴ کو National Commission for Minority Educational Institutions Bill عمل میں آیا تھا۔ میں اس بل کی حمایت کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ سال ۲۰۰۴ میں قومی کمیشن برائے اقلیتی تعلیمی ادارے قانون پاس ہوا تھا، لیکن اس قانون کے نفاذ کے بعد جو حالات سامنے آئے، جو تجربات سامنے آئے، ان کے پیش نظر اس قانون میں مزید اصلاح کی ضرورت محسوس کی گئی تھی۔ یہ ضرورت بھی محسوس کی گئی کہ اس قانون کا اسکوپ اور بڑھا دیا جائے اور جہاں جہاں کچھ کمیاں واقع ہیں، ان کمیوں اور خامیوں کو دور کر دیا جائے۔ اس سے پہلے ایک چیز یہ تھی کہ ۲۰۰۴ کے قانون میں اقلیتی تعلیمی اداروں کو صرف ۶ یونیورسٹیز کا حق دیا گیا تھا اور ان چھ یونیورسٹیوں میں سے چار یونیورسٹیاں ٹارتھ ایسٹ میں تھیں۔ جہاں تک مسلم اور سکھ مائناریٹیز کا تعلق ہے، ان کی بڑی تعداد شمالی ہندستان میں آباد ہے اور شمالی ہندستان میں صرف ایک یونیورسٹی، دہلی یونیورسٹی میں ان کو الحاق کا حق دیا گیا تھا۔ چونکہ اقلیتیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں، اس لئے ان علاقوں کی مسلم اور سکھ اقلیتوں کو اس ایک یونیورسٹی کے الحاق کے سلسلے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اسی وجہ سے اب اس ترمیمی بل میں، جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، چھ یونیورسٹیوں کے بجائے ملک کی

+[ ]Transtiteration in Urdu Script.

ہر یونیورسٹی کے ساتھ الحاق کا حق دیکر اس کمی کو دور کیا گیا ہے۔

سر، جہاں تک تعلیم کا سوال ہے، ہاؤس مکمل طور پر اس بات پر سہمت ہے کہ تعلیم ہر ہندستانی تک پہنچنی چاہئے اور تعلیم کے بغیر نہ ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ ملک کے عوام ترقی کی راہ پر چل سکتے ہیں۔ اس متفقہ فیصلے کے بعد اس بل پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ بل مائنارٹیز کو کتنا فائدہ پہنچائے گا یا مائنارٹیز کے ساتھ کتنا وشواس گھات کیا جا رہا ہے۔ صحیح معنوں میں اپوزیشن کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں اور حکومت کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مائنارٹیز، جو تعلیمی اعتبار سے مکمل طور پر پسماندہ ہو چکی ہے، ان کی پسماندگی کو دور کر کے قومی مکھیہ دھارا میں مائنارٹیز کو بھی میجارٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ اڈیش، جس کی بنیاد پر ہاؤس میں دونوں سائیڈ سے اپنی اپنی چنتائیں بھی ویکت کی جا رہی ہیں اور اپنے اپنے سجاؤ بھی دیئے جا رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی جی کو بہت ہی غور سے سن رہا تھا اور ان کی چنتاؤں کے پیچھے بھی یہی بات صاف طور پر ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ بھی ایمانداری کے ساتھ ملک میں مائنارٹیز کا تعلیمی بھلا چاہتے ہیں اور تعلیمی بھلائی کے لئے انہوں نے گورنمنٹ کے سامنے اپنے کچھ بچھاؤ رکھے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی وادی سے لیکر کنیا کماری کی سرحدوں تک پورا ہندستان ایک رنگ میں دکھائی دے، ترقی کی نہریں ملک کی ہر قوم کے دروازے تک پہنچے، تبھی ہم ہندستان کا ایک خوبصورت سپنا دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ یہ بل ملک میں لوگوں کے بیچ دراڑ پیدا کر سکتا ہے اور اقلیت اور اکثریت میں مزید کھائیاں پیدا ہونگی اور اس سے لوگوں کی تشویش میں اضافہ ہوگا۔

جہاں تک ملک کے سمودھان کا سوال ہے، تو ملک کا سمودھان اور دیش کا دستور اتنا مہان ہے کہ اس نے دیش میں رہنے والی کسی قوم کو، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہو یا کسی لسانی اقلیت و اکثریت کا درجہ رکھتی ہو، سب کے گھر تک مساوات کی روشنی پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ مگر اس حقیقت کے باوجود شاید ہمارا ہاؤس اس حقیقت سے انکار نہ کر سکے کہ جب ہم عمل میں اسی دستور کو دیکھتے ہیں تو وہ دستور عملی طور پر جب نافذ ہوتا ہے، تو ایک بہت بڑے طبقے کو، جس کو مائنارٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہم محروم

دیکھتے ہیں۔ اس لئے کہ نفاذ ملک کی آزادی کے بعد سے ہی دستور ہند کا ہو رہا ہے اور تعلیمی اعتبار سے ملک کی مائنارٹی، بلخصوص ملک کی سب سے بڑی مائنارٹی، جسے ہم مسلم مائنارٹی کہتے ہیں، تعلیمی اعتبار سے جس حد تک پسماندہ ہوگئی ہے، اگر ملک کے دستور کی روشنی میں جن ہاتھوں میں حکمرانی کا پاور تھا اور جن ہاتھوں سے اس دستور کو نافذ ہونا، عالم عمل میں آنا ممکن تھا، شاید ان سے کہیں نہ کہیں ایسی غفلت ضرور ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں آج مائنارٹیز کی پسماندگی کو دور کرنے کے لئے از سر نو ہاؤس میں یہ بحث ہو رہی ہے۔ اگر مائنارٹیز کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا ہوتا، تعلیمی اداروں میں بادھائیں روکنے کے لئے، جس طرح دوسرے سیکشن میں کیا گیا ہے، تو شاید نہ آج اس بل کی ضرورت پڑتی نہ اس چنتا کی ضرورت پڑتی۔ یہ بل اپنے آپ میں خود اس بات کو درشاتا ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد سے لیکر اب تک ملک کی مائنارٹیز کے ساتھ کہیں نہ کہیں کجروی اپنائی گئی ہے، بالخصوص تعلیمی میدان میں۔ اس لئے آج سب کی چنتائیں اس بات پر مرکوز ہو کر رہ گئی ہیں کہ مائنارٹیز کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لئے ایسے دستور نفاذ میں لائے جائیں، بل کی شکل میں، جو مائنارٹیز کی تعلیمی پوزیشن کو محفوظ کرتے ہوئے انہیں بھی ملک کی میجارٹی کے ساتھ تعلیمی میدان میں شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا موقعہ دے سکے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے میں جو یہ بل آیا ہے، اسے گورنمنٹ کا اہم فیصلہ اقلیتوں کے تعلیمی فروغ کے لئے اہم مانتے ہیں۔ مگر اس طرح کے اور بھی فیصلے اس سے پہلے آئے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ۔

مریض عشق پر رحمت خدا کی
مرض بڑھتا گیا جیوں جیوں دوا کی

بہت اچھے اچھے فیصلے آئے، بہت اچھے اچھے کمیشن بنے، مگر بات وہیں آ کر رک جاتی ہے کہ عمل کون کریگا؟ کاش عمل ہو گیا ہوتا تو آج اس طرح کی نہ چرچہ کرنے کی ضرورت تھی، نہ اس طرح کا بل لانے کی ضرورت تھی۔ آج میں حکومت ہند سے یہ کہنا چاہونگا کہ آپ یہ بل لائے ہیں، مبارک قدم ہے، نیک نیتی نظر آ رہی ہے، مگر اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد آپ کو اس کا بھی جتن کرنا پڑیگا کہ جو بادھائیں آتی

ہیں، ان بادھاؤں کو ایمانداری کے ساتھ دور کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیشن بنا ہے، اس کمیشن کے جو اختیارات ہیں، شاید ان اختیارات کی روح اور منشا یہی ہے کہ جو بادھائیں آتی تھیں، ان بادھاؤں کا نشکا سن نہیں ہوتا تھا۔ اب اگر وہ بادھائیں آتی ہیں اور لوگ اپنی شکایتیں لیکر پہنچتے ہیں تو ان شکایتوں پر ایمانداری کے ساتھ غور کیا جائے گا اور ان شکایتوں کو دور کر کے مکھیہ دھارا میں ملک کی بڑی اقلیت کو بھی لیا جائے گا۔ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر سب کو یکساں درجہ عملی طور پر دیا جائے۔ میں دستوری طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کر یہ جملہ بول رہا ہوں۔ اس لئے کہ دستور نے کہیں کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا ہے، مگر تعلیم کا اتنا اپ ڈاؤن مختلف سمودائے میں یہ بتلا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں تعصبانہ روش اختیار کر کے لوگوں نے ایک بہت بڑے طبقے کو تعلیم سے محروم کر دیا ہے۔ بقیہ اس میں جتنے بھی سیکشن ہیں، سب پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ہر ایک سیکشن اور دفعہ میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے تعلیمی اقلیتی اداروں میں تحفظ دینے میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہ ہونے پائے۔ مگر ایک بات میں عرض کرنا چاہونگا کہ جن اداروں کو آپ منظوری دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ دیجئے اور لوگوں کو اتساہت کیجئے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ادارے کھولیں۔ میں تو اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ مسلم علاقوں میں خصوصی طور پر تھانے کھولنے پر جو زور دیئے جاتے ہیں، تعلیم کے ادارے کھولنے پر زور نہیں دیئے جاتے۔ کاش تعلیمی ادارے کھولنے پر زور صرف کیا گیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ان مجرمانہ حرکتوں پر قدغن لگتا جو مجرمانہ حرکتیں صرف مسلمانوں میں نہیں، نان مسلموں میں بھی پائی جاتی ہیں اور اس کی وجہ صرف اور صرف تعلیم کی روشنی سے محرومی ہے۔ آدمی جب تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو عزت اور بے عزتی کی پری بھاشا کو پہچانتا ہے، غداری اور وفاداری کی پری بھاشا کو پہچانتا ہے، حقوق دینا اور دلوانے کی پری بھاشا کو پہچانتا ہے۔

آج تعلیم کے فروغ کے سلسلے میں یہ جو قدم اٹھایا جا رہا ہے، اگر اس پر ایماندارانہ عمل ہو گیا، میں اس بات کو بار بار اس لئے دہرا رہا ہوں کیونکہ پریشانی بل لانے میں ہمارے لئے نہیں ہے، پریشانی

آرڈننس پاس کرنے میں ہمارے لئے نہیں ہے، پریشانی تو عالم عمل میں لانے کی ہے۔ جب تک عالم عمل میں یہ بل نہیں آئے گا تب تک کتنا ہی خوبصورت بل اور کتنے ہی حقوق کی دہائی دیکر کوئی آرڈننس پاس کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نتیجہ پوزیٹیو نکلنے والا نہیں ہے۔؛ پوزیٹیو نکلنے کے لئے میں اس بل پر اپنی آخری بات عرض کرنا چاہونگا کہ تعلیمی ادارے تو ہم کھول دیں گے، مگر تعلیمی ادارے نام، زمین کے الاٹمنٹ کا نہیں ہے، بلڈنگ کی خوبصورتی کا نہیں ہے، چیئر اور ڈیسک کا نہیں ہے بلکہ اس میں پڑھنے والوں کے ذریعہ سے تعلیمی ادارہ پہچانا جاتا ہے۔ آج خصوصیت سے میں ملک کی سب سے بڑی مائنارٹی، مسلم مائنارٹی کی بات کہنا چاہونگا، تو یہ دیکھ کر ہمیں ندامت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی کہ ملک میں مسلم مائنارٹی کا تناسب تعلیمی اعتبار سے بہت ہی پچھڑے بلکہ اتی پچھڑے لوگوں سے بھی زیادہ گرتی چلی جارہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہے؟ مائنارٹی خود تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتی ہے یا ان کو تعلیم کے مواقع نہیں دئے جاتے۔ اس بات کو ایمانداری کے ساتھ لینا ہوگا۔ کچھ تو ایسا ہے کہ لوگ اپنی غربت و افلاس کی بنیاد پر تعلیم کے اداروں میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا آدمی تعلیم کی بات کیا سوچے گا؟ آج جن جن علاقوں میں صنعتی ادارے ہیں، انڈسٹریل ادارے ہیں جیسے علیگڑھ وہاں تالہ بنتا ہے، مراد آباد وہاں پیتل بنتی ہے اور مبارک پور، اعظم گڑھ، پوروانچل، بنارس۔ ان ایریاز میں بُنائی کا کام ہوتا ہے، ساڑیاں بُنی جاتی ہیں۔

مرزا پور اور بھدوہی میں کارپیٹ بنتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں، دس دس، بارہ بارہ سال کے بچوں کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ بچے سو، دو سو یا تین سو روپے مہینہ پاتے ہیں۔ ماں باپ پیٹ کی آگ بجھانے کے لئے ان تمام بچوں کو ان اداروں میں ڈال دیتے ہیں۔

اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ۱۰ سال کا ہندوستانی بچہ قالین بُننے کے لئے پیدا ہوا ہے یا اسکول جانے کے لئے پیدا ہوا ہے، اس لئے کہ یہ ۱۰ سال کا بچہ ایک مزدور کی شکل میں دکھلائی دے رہا ہے؟

اگر مزدور بھی ہو، مگر پڑھا لکھا ہو، تو ہندوستان کی تصویر بہت خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے آئے گی۔ آج ہم اس بات پر بے پناہ روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ ہم ایسٹیبلشڈ ہوں، ہم آگے بڑھیں۔ نتیجے میں ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ مگر، یہی پیسہ اگر ہم ان غریبوں کی تعلیم پر خرچ کر دیں اور ان غریبوں کو تعلیم یافتہ ہندوستانی بنا کر کھڑا کر دیں، تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ تعلیم یافتہ ہندوستانی جتنی رقم اس کے اوپر ملک کی نیشنل پراپرٹی کے طور پر لگی ہے، وہ بچہ خود نیشنل پراپرٹی بن کر اپنے ملک کو عزت و وقار کے آسمان تک پہنچائے گا۔ وہ بچے، جو قالین بُن رہے ہیں، بُنکری کر رہے ہیں یا پیتل اور تالے کا کام کر رہے ہیں، بھٹیوں میں کام کر رہے ہیں یا مزدور بن کر بھٹوں کا کام کر رہے ہیں، آخر ان بچوں کو کیسے اسکول بھیجنے کے لئے اتساہت کیا جائے، میرے سامنے یہ ایک بڑا، بنیادی اور اہم سوال ہے۔ اس لئے کہ تعلیم از حد ضروری ہے۔ گورنمنٹ نے آٹھویں کلاس تک بلا فیس کی تعلیم کر دی ہے۔ گورنمنٹ نے دوپہر کے کھانے کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ اس میں نہ تو مائنارٹی کا کوئی سوال ہے اور نہ ہی میجورٹی کا سوال ہے۔ مگر سب سے پہلا سوال اس غربت و افلاس کا ہے کہ جسے ایک وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہو، وہ تعلیم کی روشنی کہاں سے حاصل کرے گا، اسکول کیسے پہنچے گا؟ آپ نے تو اسکول کھولنے کا ادھیکار دے کر یقیناً ایک بڑے کام کی طرف اپنا حوصلہ دکھلایا ہے، مگر جب تک آپ اسکول جانے والوں کے لئے کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے، ان کو اسکول تک پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو اسکول کھولنے کے بعد کیا ہم ان میں انسانوں کے بجائے جناتوں اور بھوتوں کا بسیرا کرنا چاہتے ہیں؟

ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بچے، جو دو سو یا تین سو روپے مہینے پر کام کر رہے ہیں، ان کے لئے ایک طریقہ اور اُپائے یہ ہو سکتا ہے کہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتیں اس پر غور کریں کہ جتنا پیسہ ان بچوں کو صرف پیٹ بھرنے کے لئے دیا جاتا ہے کہ یا تو وہ پڑھیں یا اپنا پیٹ بھریں۔ اگر یہ دونوں حکومتیں آدھا آدھا پیسہ اپنے ذمہ کر کے ان بچوں کے لئے وظائف مقرر کر دیں تو ایسی صورت میں وہ ننھا بالک تعلیم حاصل کر کے ایک اچھا ہندستانی بھی بن سکتا ہے، اور تین وقت، دو وقت کی روٹی، جو اسے نہیں مل رہی ہے،

جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا پا رہا ہے، اس کے پیٹ کی آگ بھی بجھ سکتی ہے۔

میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں گاندھی جی، مولانا آزاد، جواہر لال نہرو اور اس طرح کی جتنی بھی شخصیتیں، چاہے ادھر سے ملک کی خدمت کے لئے پیدا ہوئی ہوں یا اس سائڈ سے ملک کی خدمت کے لئے پیدا ہوئی ہوں، ان شخصیتوں کے پیٹ میں انّ اور پانی گیا تھا، سویدھائیں تھیں، جن کی بنیاد پر وہ ترقی کر کے ملک کا نشان اور ملک کا سلوگن بن گئے تھے۔ آج کے یہ بچے، جو مارے مارے پھر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ان بچوں میں کون گاندھی جیسا ذہن رکھتا ہے، کون نہرو جی جیسا ذہن رکھتا ہے اور کون مولانا آزاد جیسا ذہن رکھتا ہے۔ مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ بھارت کے ضمیر و خمیر سے پیدا ہونے والا ہر ہندوستانی ہندوستان کو عزت کے آسمان تک ضرور پہنچا دے گا، اس لئے کہ اس کے جنس میں یہ بات شامل ہے، اس کے خون میں یہ بات شامل ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو موقع ملے اور اسے موقع دینے کے لئے صرف اسکول کھولنا ہی لازمی نہیں ہوگا، اسکول تک پہنچانے کے لئے انہیں وہ لازمی سویدھائیں بھی دینی ضروری ہوں گی، جن کی بنیاد پر غریبوں کو اتساہت کر کے اسکولوں تک پہنچایا جائے۔ تب یہی غریب جس کے ہاتھ اور پیر کی کمائی کے ذریعے آج ہندوستان کی فصلیں لہلہا رہی ہیں، اس کے تعمیر و ترقی کے نقشے سے ہندوستان مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اگر اس کے پاس علم کا بھی ہنر ہو جائے گا، اگر اس کے پاس تمدن اور کلچر بھی آ جائے گا، تو اتنا بڑا ملک جو اپنی سنسکرتی میں وشال ہے، جو اپنی تہذیب میں لاثانی ہے، جس ملک کا نیچر ہی اس ملک کے علم و عمل کو دنیا میں اجاگر کرتا ہے، اگر ان بچوں پر تھوڑی سی محنت ہو جاتی ہے اور ان بچوں کو اسکول کا منھ اس طرح سے دکھائی جائے یا جانے کہ ان کے پیٹ بھی بھریں اور وہ تعلیم بھی حاصل کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل بھی کارآمد ہوگا اور حکومت کی پالیسی بھی کارآمد ہوگی۔

میں آخری جملہ عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایسی صورت میں اس بات پر پھر بل دوں گا کہ ان کو دو سو یا تین سو روپے مہینہ میں ملتے ہیں۔ جب ان کے گھر پر جا کر کہا جائے کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجو، تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب پیٹ کی آگ بجھا دیں یا اسکول جائیں۔

اور بھی پریشانیاں اور بادھائیں ہیں۔ ایسے غریبوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ رات رات بھر رکشہ چلاتے ہیں اور اس کمائی سے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔

سر، میں اپنا ہی ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ برسات کا وقت تھا، جھارکھنڈ میں ایک شہر ہے ہزاری باغ، میں وہاں بس اسٹینڈ پر اترا اور وہاں سے دو کلومیٹر پر محلہ متواری جانے کے لئے رات کے دو بجے میں نے ایک رکشہ کیا۔ اس زمانے میں رکشہ والا ڈیڑھ روپیہ لیا کرتا تھا۔ اتنی جھم جھم بارش ہو رہی تھی اور وہ آدمی رکشہ چلا رہا تھا۔ جب میں گھر پر پہنچا، تو میں اس سے پوچھا کہ آپ اور کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ بابو جی، میں رات میں دن میں رکشہ چلاتا ہوں اور اپنے بچوں کو بڑی خواہش ہے میرے دل میں، کہ اچھی سے اچھی تعلیم دلوا کر ان کو ملک کا سیوک اور علم و ادب کے میدان میں ان کی زندگی کو نکھاروں۔ میں نے اس کو ڈیڑھ روپے کے بجائے دس روپے دئے، مگر یہ دس روپے اس کے مستقبل کو تو نہیں سنوار سکتے تھے۔ البتہ اس کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے میں کہنا چاہونگا کہ کتنے لوگ ہیں، جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، مگر ہائے رے، پیٹ کی مار کہ بھوک کی آگ سے تڑپتا ہوا بچپن بہتر جوانی کے لئے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کچھ ایسا کر سکیں کہ جن بچوں کو ایسی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر سو روپے، دو سو روپے حاصل کرنے کے لئے پیٹ کی آگ بجھانی پڑتی ہے اور علم جیسی مہان شکتی سے وہ بچے ونچت رہ جاتے ہیں، اگر یہی رقم سینٹرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ آدھی آدھی اپنی سائیڈ سے مہیا کروا دیں ایسے بچوں کے لئے، تو ان کے پیٹ کی آگ بھی بجھ جائے گی اور آپ جو علم کا سپنا اپنا بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی ساکار ہو جائے گا۔

سر، اس بل کی حمایت کرتے ہوئے میں یہی کہنا چاہونگا کہ کوئی ایسا ماحول پیدا کیجئے کہ جن جن میں یہ نعرہ گونجے ''پڑھو لکھو، انسان بنو، بھارت کی پہچان بنو''۔ تھینک یو، شکریہ۔

''ختم شد''

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, I support this Bill which would give more chances to the minorities in higher education. However, I have my apprehensions about this Bill, if the provisions of this Bill are implemented without caution. The Bill has been closely scrutinised by the Standing Committee. In its Report the Committee has emphasised and I quote:

> "The Committee feels that the Bill must provide adequate safeguards for preventing the misuse of the minority status by an institution."

This apprehension was mentioned in the Standing Committee Report. I am not supporting the viewpoints raised by my BJP colleagues in this House.

Sir, the minority communities, especially, the Muslim community, are lagging behind socially, economically and educationally. The minorities in this country are suffering from mental agony because of the hardcore Hindutva line pursued by the previous Government. Fortunately, due to the initiative taken by the majority in the country, by the secular-minded people in our country, now the minority communities have the added confidence to live as citizens of this country. In that direction this Bill will help the minority to gain more confidence.

At the same time, Sir, I would like to mention that whenever we passed this kind of a legislation, we had certain bitter experiences. There is every possibility of misusing the scope of this Bill. There are richer sections in our society. As per the Bill, an individual from a minority community can start a minority institution. If he has the money to purchase the land and construct the building, he can go ahead and start a minority institution. So, utmost caution should be taken in this regard. This right to start a minority educational institution should not be reserved only for the economically privileged minority among the minorities. That is the issue. The Government should give an assurance to this House that the benefit would not go to the rich minority, the so called economic minority among the minorities. So, utmost caution should be taken to avoid its misuse while implementing this bill. Any individual can go and say that he is from a minority community. That is the problem. This is my apprehension so far as this Bill is concerned. Similarly, we have the experience of Kerala. Shri A.K. Antony is the hon. Member of this House. The Government of Kerala gave permission to start unaided colleges and a majority of them

have been given to the minority communities. What was the net result? An assurance was given that 50 per cent of the seats would be given to the socially and economically backward sections of the society. But after they got NOC and started these institutions, none of the institutions fulfilled the promise which they had given. The Chief Minister of Kerala said publicly: that private institutions, self-financed institutions have played a mischief; they have betrayed the people; they have not fulfilled the promise which they had made to the State and to the people. This is what was said by Shri A.K. Antony in public. They have cheated the people. So the same thing can happen here also. What is the safeguard? After the judgement of the Supreme Court with regard to the fee structure, the meritorious students, the poor students are afraid whether they would get a chance for higher education or not. That chance is missing here. There is a proposal before the Government. The Government must come forward with a legislation to ensure that the meritorious student in this country would get a chance in these colleges for higher education. There is no such provision in this Bill. Before coming forward with such an enactment, we are discussing this bill in this august House. I am not opposing it, but, simultaneously, I would request the Government to assure the house that poor and meritorious students in this country would be supported by a legislation which would provide them opportunities for higher education. When the hon. Minister replies to the debate, he must answer the points which I am raising.

Sir, there is another problem. Once we start these minority institutions, a stipulated number of seats should be reserved for the minorities. I would like to know whether it would serve the interests of the poorer sections in the minority as such. That is the doubt which I would like to express in this House. Will they get a chance? My hon. friend, Azmiji, was enunciating details about the condition of the Muslim minority in our country. Among the agriculture workers, they are in a majority. After the Scheduled Castes, Muslims are in a majority, Among the child labour, whether it is in Moradabad or in Banaras or in Aligarh, most of them are Muslim children. They are the deprived section in the society. Will their interests be served by this piece of legislation? This is the question which I want to put. The Government must ensure that 50 per cent of the seats in these minority institutions would be reserved for the most deprived sections, the poorest people among the minorities. Their interests should

be served. I would like to know whether their interests would be served by this piece of legislation. The Government must give an assurance to this house that the interests of the poorest among the minorities would be served by this piece of legislation. Are we going to safeguard the interests of the poorer sections among the minorities? that is the issue on which I would like to have an assurance from the Government. Now the BJP has voiced its opposition with regard to this Bill. There is a 'Dissenting Note' in the Report of the Standing Committee. They are trying to divert the whole issue by saying that it would give rise to terrorism, this or that thing. It means they are against the interests of the minorities. This is what is reflecting in their opposition. I have my own apprehension with regard to this Bill. There is a specific point relating to the Centre-State relation.

Sir, when we were amending this legislation, there was a discussion in this august House as to how we should safeguard the interest of the States. In a country like India, we have diversity; the socio-economic conditions of minorities, say, in Uttar Pradesh, are not the same as that of Kerala or West Bengal. We have to analyse issues in a different viewpoint. In those States where we have social changes through land reforms, the benefits have been given to all sections of the society. Naturally if we look at the educational institutions in Kerala or West Bengal or in those States where we have adopted land reforms, a good number of minority students are there is these educational institutions. We cannot take it in the same way in all States of the country; the differences are there. So, with regard to this Bill also, I would say that the States should be made to discharge their own responsibilities, and differences prevailing in various States have to be taken note of. It was pointed out in this august House, when we took up this discussion, that there were sufficient provisions whereby States were in a position to make their own legislation. In order to protect the autonomy of the States, that is, the federal nature of the States, the State legislation should be given an equal position as that of the Central legislation. There is a lacuna in this piece of legislation. It is that in case there is a difference of opinion between the state Commission and the Central Commission, the Central Commission will have an upper hand. A feeling should not go that this National Commission has super power over the States. the State Governments are there. The Governments, in their respective States, know the reality at the ground level. For example, in my State, 80 per cent of these institutions are run

by the minority community. But I want to make one thing clear that only one engineering college has a minority status; the remaining institutions do not have a Minority status. So, the minority community is running these colleges. An institution is meant for all the students. A minority institution does not mean that it is for minorities alone; it is for meritorious students. At the same time, minority institutions should be there, and it should aim to enhance the educational quality of the minorities. There is no doubt on that. But looking at the experiences that we have in Kerala, I would request this Government to make necessary amendments because if you look at clause 12(b), (iv), it would give an impression that the National Commission has a power much higher than the State Governments. Maybe it has more powers than the State Commission. That is a different thing. But it can't be more than the State Governments' powers. Again, on the question of taking a decision about an appeal against the decision of the State Government, what will be the stand of the State Government? That should be properly ascertained. That should be ensured because it is the State Government concerned which knows the reality better than the Central Government. So, I have an apprehension with regard to this point. But, Sir, I would say that I am not standing in support of the viewpoints raised by the BJP. I won't say that the Bill is meant to appease the minority community. But, Sir, the apprehensions are there, and the interests of the poorer sections of the minority community...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: you have said all the things which we have said...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: I have a copy of the dissenting note...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vijayaraghavan, please conclude.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: ...wherein it is mentioned that this kind of institutions will be misused for terrorist activities. I am not talking of the viewpoint of the BJP here. I have my own apprehensions...(*Interruptions*)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar): Sir, I have given the note, and I have said that. I will handle it.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: My point is that considering the federal nature of our Constitution, considering the autonomy and the power of the States, the State Governments fully know the reality in their respective States. On the basis of that, the State Governments will make their legislation. So, whenever you are making some amendments or are taking decisions contrary to the decisions of the State Commissions, you have to ensure that there is proper consultation with the respective Governments.

And, I have full faith in this Government that they would accept such a suggestion from our side because it is a suggestion for safeguarding the interests of the minority, especially, the backward and the poorer sections in the minority community.

With these words, I conclude. Thank you, Sir.

श्री उपसभापति: श्री शाहिद सिद्दिकी, आपकी पार्टी के दो वक्ता हैं और ग्यारह मिनट हैं।

श्री शाहिद सिद्दिकी: महोदय, मैं इस हाउस को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह का एक कंसेंसस पिछली बार हुआ जब यह बिल डिसकस हुआ था, उस वक्त भी और आज भी एक कंसेंसस है, इस बात पर सब पार्टियां इस बात को समझती हैं कि देश के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए मॉयनोरिटीज का खास तौर पर मुस्लिम मॉयनोरिटीज का शिक्षा के मैदान में आगे आना आवश्यक है। इस पर कोई मतभेद नहीं और इससे मैं समझता हूं कि बहुत तकलियत मिलती है मुल्क के मॉयनोरिटीज को और उनको अहसास होता है कि पूरा मुल्क इस पर जाग रहा है और उनके मसले को समझ रहा है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राघवन जी ने जो बात कही है, मैं उससे बहुत सहमत हूं कि आप जब मॉयनोरिटीज इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं, बना रहे हैं हर एजुकेशन में, तो इस बात का ख्याल रखिए कि मुसलमानों में, खास तौर पर 90 प्रतिशत जो पिछड़े हुए हैं वे दस्तकार हैं, वे गरीब हैं। वे लोग हैं जिनकी पहली जेनरेशन आज शिक्षा में आ रही है, जिनकी पिछली सात-दस पीढ़ियों ने शिक्षा हासिल नहीं की। वे जब आ रहे हैं तो इस कम्पटीशन में हिस्सा नहीं ले पाते। उनके लिए इन मॉयनोरिटीज इंस्टीट्यूशन में मेरा अपना तर्जुबा है कि कोई जगह नहीं है। बंगलौर के कॉलेजेज में, साउथ के कॉलेजेज में, यहां जो कॉलेज खुल रहे हैं वहां जब हम गरीब मुसलमान बच्चों को एडमिशन के लिए भेजते हैं तो उनको इंकार मिलता है, उनको दाखिला नहीं मिलता है। तो मैं सरकार से खास तौर पर यह कहना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि सदन मेरा साथ दे इसमें कि ये जो मॉयनोरिटीज इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें उनको बाध्य किया जाए कि वे कम से कम 25 प्रतिशत रिजर्वेशन पिछड़े मुसलमान बच्चों के लिए रखें, इकॉनोमिकली बैकवॉर्ड मुसलमान बच्चों के लिए रखें और उनके लिए इसमें स्कॉलरशिप रखी जाए, उनको वहां पर जगह दी जाए। इसके लिए उनको बाध्य करना पड़ेगा। अगर आप बाध्य नहीं करेंगे तो उनको जगह नहीं मिलेगी। मैं इससे भी सहमत हूं कि जहां ये मॉयनोरिटीज इंस्टीट्यूशंस मॉयनोरिटीज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो दुकानें बन गई हैं, जो कॉमर्शियल इस्तेमाल में आ रही हैं। चूंकि मॉयनोरिटीज इंस्टीट्यूशंस हर तरह के हैं, तरह-तरह के, इसके कॉमर्शियलाइजेशन को रोकने के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा कि ये कॉमर्शियल परपज के लिए मॉयनोरिटीज के नाम पर इस्तेमाल न हों। क्योंकि बदनामी फिर मॉयनोरिटीज की होती है, बदनामी मुसलमानों की होती है लेकिन होता यह है कि कुछ लोग अपने खास मकसद के लिए इंस्टीट्यूशन को कॉमर्शियलाइज करते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। वह चीज रुकनी चाहिए। तीसरी बात, जो हमारे मौलाना ने कही कि–मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मर्ज जैसे-जैसे आपने मसले को हल करने की कोशिश की है पिछले 55 साल में मर्ज बढ़ता गया, चूंकि शायद मैं गलती

पर हूं, ईमानदारी से कोशिशें नहीं हुईं। हुआ यह कि मैं क्या सियासी फायदा उठा सकता हूं टोकनिज्म होता रहा, आप क्या कदम उठा सकते हैं, आपका विरोध इसलिए हुआ कि आपकी राजनीति कुछ कहती है, आपने कोई मामला रखा कि आपकी राजनीति कुछ कहती है। मैंने मॉयनोरिटी की बात इसलिए की कि मुझे वोट लेने थे। यह जो वोट की राजनीति मॉयनोरिटी के साथ हुई है यह देश के हित में भी नहीं है और मॉयनोरिटी के हित में भी नहीं है, इसलिए इससे हमें उठना पड़ेगा, खास तौर से इस सदन में इस माहौल को बनाना पड़ेगा। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो आपने मर्ज को हल करने की कोशिश की है इससे मर्ज का इलाज मुमकिन नहीं है। क्योंकि मुसलमानों में खास तौर पर जो बैकवर्डनैस है, वह प्राइमरी एजुकेशन में है, वह सेकेंडरी एजुकेशन में है। वहां पर जब तक आपका ध्यान नहीं होगा हायर इंस्टीट्यूशन में आप उनको अच्छे कम्पटीशन के साथ नहीं ला सकते, देश की सेवा में जो उनका योगदान है, वह नहीं हो सकता। उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम सर्वशिक्षा अभियान की बात कर रहे हैं, तो हम सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, वे चाहे पिछड़े बच्चे हैं, वे चाहे एबल बच्चे हैं, वे किसी धर्म से हैं, किसी जाति से हैं, ट्राइबल हैं, मुसलमान हैं, यानी देश के हर बच्चे को हम शिक्षा देंगे। यह हमने फैसला किया है, हमारी सरकार ने फैसला किया है, इस देश ने फैसला किया है। उसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि जो ज्यादा पिछड़े हैं किसी भी कारण से उनके लिए जब सर्वशिक्षा अभियान में आप अलग से आबंटन नहीं करेंगे, अलग से कोई स्कीम नहीं बनाएंगे, आबंटन मत कीजिए, लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा कि जहां ज्यादा बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां ज्यादा फोकस की जरूरत है। तो मॉयनोरिटीज के जो बच्चे हैं, खास तौर पर जैसा मौलाना ने कहा कि जो हमारे दस्तकार बच्चे हैं, सर, मैं दस्तकार बच्चों के बारे में कहना चाहता हूं, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरिएंसेज़ हैं, इन बच्चों के साथ। होता यह है कि मां-बाप पढ़ाना भी चाहते हैं, पेट काटकर, पेट पर पत्थर बांधकर बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन वह बच्चा जो पहली बार स्कूल में आ रहा है, जिसके यहां सात पीढ़ियों में कभी पढ़ाई नहीं हुई, उसको पता नहीं कि स्कूल का होम वर्क क्या होता है, जिसको पता नहीं कि स्कूल का व्यवहार क्या होता है, वह स्कूल में कम्पीट नहीं करता। यह वह बच्चा आ रहा है, जो आज से पहले बुनकर बनता था, सीखता था, उससे रोटी खाता था, आज वह भी चाहता है कि उसका बच्चा भी पढ़े, वह भी जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़े, वह भी इस देश को अब्दुल कलाम दे, उसकी भी हर बात की ख्वाहिश है, मैं जानता हूं कि हर माइनॉरिटी के बाप की ख्वाहिश यह है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर अब्दुल कलाम बने, अब्दुल हमीद बने, वह अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी बने, हर हिन्दुस्तान के मुसलमान के मन में यह ख्वाहिश है। वह अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजता है, लेकिन होता क्या है, एक तो उसकी जुबान यानी जुबान चली गई, उर्दू में शिक्षा ले नहीं सकता, अंग्रेजी वह जानता नहीं, हिन्दी में उतना कम्पीटेंट नहीं है जिसकी वजह से कम्पटीशन में वह दूसरे बच्चों से पीछे रह जाता है। वह दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार में, जिंदगी के कपड़ों में, चलने में, होम वर्क में पीछे रह जाता है, इसका नतीजा यह है कि ड्राप-आउट रेट बहुत ज्यादा हाई है मुसलमान बच्चों का। इसको दूर करने के लिए आपको सेंसेटिवली मामले को समझकर इसके लिए फोकस्ड प्रोग्राम बनाने होंगे। जब तक आप फोकस्ड प्रोग्राम नहीं करेंगे, आप नीचे से नींव लेकर काम नहीं करेंगे, हवा में किले बनायेंगे,

तो मुझे माफ करें, उससे माइनॉरिटीज़ को फायदा होने वाला नहीं है, माइनॉरिटीज़ से जुड़े हुए कुछ अफराद जिनके पास पैसा है, जिनमें सलाहियत है, उनको फायदा हो जायेगा, इंस्टीट्यूशन्स बना लेंगे पैसा कमा लेंगे, करोड़ों कमायेंगे, उनको फायदा होगा, माइनॉरिटीज़ को फायदा नहीं होगा। अगर आप माइनॉरिटीज को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और इस देश को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो उसका तरीका यही है कि इस काम को लेकर चलें और जो राष्ट्रीय अभियान शिक्षा का है, उसमें आप उनके लिए अलग से फोकस्ड प्रोग्राम तैयार करें, यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं।

सर, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब आप पिछली बार बिल लेकर यहां आये थे, उस वक्त भी हमने बहस की थी और उसकी खामियां गिनाईं थीं। उस वक्त भी हमने कहा था कि अमल जो है वह सबसे अहम चीज है, इस पर अमल कैसे होगा? पिछली बार आपने कुछ यूनिवर्सिटयां नार्थ-ईस्ट की और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी रख दी थी। यहां भी मुझे पर्सनली एक्सपीयरेंस हुआ है कि जिन इंस्टीट्युशन्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एप्लाई किया, माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन्स जिन्होंने सारी तैयारियां मुकम्मल करके, बिल्डिंग बनाकर के, फर्नीचर खरीद कर के, सामान खरीद करके, जितनी जरूरतें हैं, सब पूरी कर लीं, कहीं से पैसा इकट्ठा करके, मेहनत करके, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनओसी के लिए एप्लाई किया, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से आज तक किसी भी इंस्टीट्यूशन को जवाब नहीं मिला। एक जवाब नहीं मिला और हमारे लोग जब वाइस चांसलर से मिलने गये, उनसे रिक्वेस्ट की कि इसके बारे में कोई जवाब दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मशीनरी नहीं है। यह देखने की, आपके यहां आकर इन्सपैक्शन करने की, समझने की और उस के लिए एनओसी देने की मेरे पास मशीनरी नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने यूनिवर्सिटियों को कह तो दिया, लेकिन क्या उन यूनिवर्सिटीज़ को इन्स्ट्रक्शन्स दी हैं कि माइनॉरिटीज़ के जब आपके पास एफिलियेशन के लिए आयें, तो आप उनको एफिलियेशन दें। आप इसके लिए एक समय-सीमा निश्चित कीजिए कि तीन महीने के अंदर या छह महीने के अंदर आपको एफिलियेशन देना है नहीं तो जवाब देना है कि क्यों नहीं दिया आपने अफिलियेशन। यह बहुत आवश्यक है, वरना यह कागज पर ही रहेगा, जैसा हमने पीछे देखा है। आप ऑर्डिनेंस लाये कि बहुत जल्दी है, बहुत इमरजेंसी है, आप तो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, लेकिन वहां पर चिट्ठी का जवाब देने के लिए कोई यूनिवर्सिटी तैयार नहीं है कि आपने एफिलियेशन के लिए एप्लाई किया है तो एफिलियेशन दें कि नहीं दें। मंत्री जी, इसके लिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें, तब हां, हम समझेंगे कि आपकी नीयत ठीक है और आप वाकई चाहते हैं। नीयत तो आपकी ठीक है, नीयत आपकी ठीक रही है, लेकिन अमल आपका पिछले 55 साल में खराब रहा है और उसके बारे में, मैं इस बात को ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि अमल में पार्टियों का कोई रोल नहीं होता है। मैं मानता हूं कि माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक किसी की नीयत में खोट नहीं है, न जोशी जी, आपकी नीयत में खोट है, न इनकी नीयत में खोट है।..(व्यवधान)..

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: हमारी नीयत में खोट नहीं है, यह तो हमने साबित कर दिया है। ...(व्यवधान)...

श्री शाहिद सिद्दिकी: वह एक अलग बहस है।

श्री उपसभापति: आप कुछ टाइम अपने साथी के लिए छोड़ना चाहते हैं या नहीं?

श्री शाहिद सिद्दिकी: असल बात यह है कि जब अमल का वक्त आता है, तो हमारा सिस्टम जिस तरह से काम करता है, वहां हम भी उस काम को नहीं करा पाते हैं। इसलिए आपको सिस्टम पर ध्यान देना होगा और उन्हें बाध्य करना होगा कि यूनिवर्सिटीज़ उनको एफिलियेशन दें। सर, मैं आखिर में, यह कहना चाहूंगा कि आज दुनिया में जहां भी हम जाते हैं। हम किसी भी लैवल पर बात करते हैं–चाहे वह हैड ऑफ दी स्टेट से बात करते हों, चाहे आम आदमी से बात करते हों–एक बात हमें सुनने को मिलती है कि क्या वजह है कि हिन्दुस्तान का मुसलमान, जो इतनी बड़ी तादाद है, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा है या दूसरे नम्बर पर है, वहां पर आतंकवाद उनके बीच कभी जड़ नहीं बना सका, एक-आध कोई इनडिविजुअल निकल आया हो, लेकिन जड़ नहीं बना सका? क्यों हिन्दुस्तान के मुसलमान आतंकवाद से नहीं जुड़े हैं? यहां तक कि कश्मीर के मामले में भी, हिन्दुस्तान के जो बाकी हिस्सों के मुसलमान हैं, उन्होंने कभी भी उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया, उसका साथ नहीं दिया और हम फख्र के साथ हर जगह कहते हैं कि उसका कारण हमारे मुल्क का कल्चर है, हमारी सभ्यता है, हमारी परम्परा है और हमारे मुल्क का लोकतंत्र है जिसने एक अलग माहौल दिया है, जिसकी वजह से हिन्दुस्तान का मुसलमान एक युनीक मुसलमान बनकर निकला है। मैं कहना चाहता हूं कि आज दुनिया में, दुनिया के मुसलमानों की लीडरशिप का रोल जो है, रोल मॉडल का जो रोल है, वह हिन्दुस्तान का मुसलमान दे रहा है और आने वाले वक्त में देगा। आज दुनिया में जो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं, वह हिन्दुस्तान का मुसलमान दे रहा है और हमें, सिर्फ हिन्दुस्तान को दुनिया की लीडरशिप का रोल नहीं करना है, हिन्दुस्तान के मुसलमान को भी मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप का रोल करना है और उनको रास्ता दिखाना है तथा वे आज जिस खाई में हैं, जिस अंधेरे में हैं, उससे निकालकर उन्हें रोशनी की तरफ लाना है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हिन्दुस्तान का मुसलमान भी उसी तरह से नेशनल कैपिटल बने, हमारी लेबर फोर्स जो है, हमारी पॉपूलेशन आज हमारी सबसे बड़ी कैपीटल है लेकिन यह कैपिटल तब है, जब हमारे पास शिक्षा हो, हमारे पास स्वास्थ्य हो और हमारे यहां सोशल पीस हो। इस सोशल पीस को बनाने के लिए आवश्यक है कि हर सैक्शन में यह एहसास आए कि इस स्टेट में, इस पाई में मेरा भी एक हिस्सा है और वह एहसास देने का काम आपका भी है, मेरा भी है और इनका भी है। वह एहसास अगर हम देंगे तो आने वाले वक्त में हिन्दुस्तान दुनिया को लीड करेगा, हिन्दुस्तान से अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा होंगे जो हिन्दुस्तान की भी शान बनेंगे और मुसलमान की भी शान बनेंगे तथा दुनिया में एक पैगाम देंगे। इसके लिए मैं अपने साथियों से यह कहना चाहूंगा कि मन से

3. P.M.

यह बात निकाल दीजिए कि कोई आतंकवाद का खतरा पैदा हो जाएगा। अरे, आतंकवाद तो हमने गुजरात में नहीं पनपने दिया। मुझे याद है, मैं और कुलदीप नैयर जी जमशेदपुर गए थे। जमशेदपुर में दंगा हुआ था। एक एम्बुलेस के अंदर सवा सौ लोग जिंदा जला दिए गए थे, जिसमें बच्चे और औरतें थीं। एम्बुलेंस को बंद करके, पैट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी और कुलदीप नैयर साहब ने वहां के मुसलमानों से पूछा था कि इन हालात में क्या तुम पाकिस्तान जाना चाहोगे, यहां से कहीं महफूज़ जगह जाना चाहोगे? तब वहां के मुसलमानों का जवाब यह था कि क्यों जाना चाहेंगे पाकिस्तान, यह हमारा वतन है, हम यहीं मरेंगे, इसी मिट्टी के अंदर दफन होंगे। मैंने आज तक किसी दंगा पीड़ित इलाके में किसी एक मुसलमान को यह कहते हुए नहीं सुना कि मैं देश छोड़ना चाहता हूं। उसके देश प्रेम में कोई कमी नहीं आती--गुजरात के बावजूद, जमशेदपुर के बावजूद, भिवंडी और जलगांव के बावजूद--तो हम यह कॉलेज खोलकर, यूनिवर्सिटी खोलकर कैसे आतंकवाद की तरफ जा सकते हैं? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का एक-एक मुसलमान मुल्क पर मरने को तैयार है। उसे शिक्षा दे दीजिए, उसे आगे बढ़ने का मौका दे दीजिए, वह इस तरह से सेवा करेगा कि दुनिया देखेगी कि हिन्दुस्तान के मुसलमान ने इस देश की किस तरह से सेवा की है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

†[ ] شری شاہد صدیقی ''اتر پردیش'' : مہودے میں اس ہاؤس کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح کا ایک کنسینسز پچھلی بار ہوا جب یہ بل ڈسکس ہوا تھا، اس وقت بھی اور آج بھی ایک کنسینسز ہے، اس بات پر سب پارٹیاں اس بات کو سمجھتی ہیں کہ دیش کے نرمان کے لئے، دیش کے وکاس کے لئے مائنارٹیز کا خاص طور پر مسلم مائنارٹیز کا شکشا کے میدان میں آگے آنا ضروری ہے۔ اس پر کوئی مدبھید نہیں اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت تقویت ملتی ہے ملک کے مائنارٹیز کو اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ پورا ملک اس پر جاگ رہا ہے اور ان کے مسئلے کو سمجھ رہا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ راگھون جی نے جو بات کہی ہے، میں اس سے بہت سہمت ہوں کہ آپ جب مائنارٹیز انسٹی ٹیوشن دے رہے ہیں، بنا رہے ہیں ہر ایجوکیشن میں، تو اس بات کا خیال رکھئے کہ مسلمانوں میں، خاص طور پر ۹۰ فیصد جو پچھڑے ہوئے ہیں وہ دستکار ہیں، وہ غریب ہیں، وہ لوگ ہیں جن کی پہلی جنریشن آج شکشا میں آ رہی ہے، جن کی پچھلی سات، دس پیڑھیوں نے شکشا حاصل نہیں کی۔ وہ جب آ رہے ہیں تو

†[ ] Transliteration in Urdu Script

اس کمپیٹیشن میں حصہ نہیں لے پاتے۔ ان کے لئے ان مائنارٹیز انسٹی ٹیوشن میں میرا اپنا تجربہ ہے کہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ بنگلور کے کالجوں میں، ساؤتھ کے کالجوں میں، یہاں جو کالج کھل رہے ہیں وہاں جب ہم غریب مسلمان بچوں کو ایڈمیشن کے لئے بھیجتے ہیں تو ان کو انکار ملتا ہے، ان کو داخلہ نہیں ملتا ہے۔ تو میں سرکار سے خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ سدن میرا ساتھ دے۔ اس میں کہ یہ جو مائنارٹی انسٹی ٹیوشنس ہیں ان میں ان کو بادھ کیا جائے کہ کم سے ۲۵ فیصد رزرویشن پچھڑے مسلمان بچوں کے لئے رکھیں، اکانومکلی بیکورڈ مسلمان بچوں کے لئے رکھیں اور ان کے لئے اس میں اسکالرشپ رکھی جائے، ان کو وہاں پر جگہ دی جائے۔ اس کے لئے ان کو بادھ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ بادھ نہیں کریں گے تو ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ میں اس سے بھی سہمت ہوں کہ جہاں یہ مائنارٹی انسٹی ٹیوشن، مائنارٹیز کو آگے لے جانے کا کام کر رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں ایسے انسٹی ٹیوشنس بھی ہیں، جو دکانیں بن گئی ہیں، جو کمرشیل استعمال میں آ رہی ہے۔ چونکہ مائنارٹیز انسٹی ٹیوشنس ہر طرح کے ہیں، طرح طرح کے، اس کے کمرشلائزیشن کو روکنے کے لئے بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا کہ یہ کمرشل پرپز کے لئے مائنارٹیز کے نام پر استعمال نہ ہوں۔ کیوں کہ بدنامی پھر مائنارٹیز کی ہوتی ہے، بدنامی مسلمانوں کی ہوتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے خاص مقصد کے لئے انسٹی ٹیوشن کو کمرشلائز کرتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ چیز رکنی چاہئے۔ تیسری بات، جو ہمارے مولانا نے کہی کہ 'مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی'۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مرض جیسے جیسے آپ نے مسئلے کو حل کرنے کو کوشش کی ہے پچھلے ۵۵ سالوں میں مرض بڑھتا گیا، چونکہ شاید میں غلطی پر ہوں، ایمانداری سے کوششیں نہیں ہوئیں۔ ہوا یہ کہ میں کیا سیاسی فائدہ اٹھا سکتا ہوں، ٹوکنزم ہوتا رہا، آپ کیا اٹھا سکتے ہیں، آپ کا ورودھ اس لئے ہوا کہ آپ کی راجنیتی کچھ کہتی ہے، آپ نے کوئی معاملہ رکھا کہ آپ کی راجنیتی کچھ کہتی ہے۔ میں نے مائنارٹی کی بات اس لئے کی ہے کہ مجھے کچھ ووٹ لینے تھے۔ یہ جو ووٹ کی راجنیتی مائنارٹی کے ساتھ ہوئی ہے یہ دیش کے ہت میں بھی نہیں ہے اور مائنارٹی کے ہت میں بھی نہیں ہے، اس لئے اس سے ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ خاص طور سے اس سدن میں اس ماحول کو بنانا پڑے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے مرض کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اس سے مرض کا علاج ممکن نہیں ہے۔ کیوں مسلمانوں میں خاص طور پر جو بیک ورڈ ہے، وہ پرائمری ایجوکیشن میں ہے، وہ سیکنڈری ایجوکیشن میں ہے۔ وہاں پر جب تک آپ کا دھیان نہیں ہوگا ہائر انسٹی ٹیوشن میں آپ ان کو اچھے کمپیٹیشن کے ساتھ نہیں لا سکتے، دیش کی سیوا

میں جوان کا یوگدان ہے، وہ نہیں ہوسکتا۔ اس کے لئے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جب ہم سروشکشا ابھیان کی بات کررہے ہیں، تو ہم سارے بچوں کی بات کررہے ہیں، وہ چاہے بچھڑے بچے ہوں، وہ چاہے ایبل بچے ہوں، وہ کسی دھرم سے ہوں، کسی ذات سے ہوں، ٹرائبل ہیں، مسلمان ہیں، یعنی دیش کے ہر بچے کو ہم شکشا دیں گے۔ یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہماری سرکار نے فیصلہ کیا ہے، اس دیش نے فیصلہ کیا ہے۔ اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو زیادہ بچھڑے ہیں کسی بھی کارن سے، ان کے لئے جب سروشکشا ابھیان میں آپ الگ سے آوٹن نہیں کریں گے، الگ سے کوئی اسکیم نہیں بنائیں گے، آوٹن مت کیجئے، لیکن آپ کو فوکس کرنا پڑے گا کہ جہاں زیادہ بیک ورڈ ایریے ہیں، وہاں زیادہ فوکس کی ضرورت ہے۔ تو مائنارٹی کے جو بچے ہیں، خاص طور پر جیسا مولانا نے کہا کہ جو ہمارے دستکار بچے ہیں، سر، میں دستکار بچوں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، میرے اپنے پرسنل ایکس پیرینس ہیں، ان بچوں کے ساتھ۔ ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ پڑھانا بھی چاہتے ہیں، پیٹ کاٹ کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر بچے کو پڑھانے کے لئے بھیجتے ہیں، لیکن وہ بچہ جو پہلی بار اسکول میں آرہا ہے، جس کے یہاں سات پیڑھیوں میں کبھی پڑھائی نہیں ہوئی، اس کو پتہ نہیں کہ اسکول کا ہوم ورک کیا ہوتا ہے، جس کو پتہ نہیں کہ اسکول کا ویوہار کیا ہوتا ہے، وہ اسکول میں کمپیٹ نہیں کرتا۔ یہ وہ بچہ آرہا ہے، جو آج سے پہلے بنکر بنتا تھا، سیکھتا تھا، اس سے روٹی کھاتا تھا، آج وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بھی پڑھے، وہ بھی زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھے، وہ بھی اس دیش کو عبدالکلام دے، اس کی بھی ہر بات کی خواہش ہے، میں جانتا ہوں کہ ہر مائنارٹی کے بات کی خواہش یہ ہے کہ میرا بچہ بڑا ہوکر عبدالکلام بنے، عبدالحمید بنے، وہ اچھا کرکٹ کا کھلاڑی بنے، ہر ہندوستان کے مسلمان کے من میں یہ خواہش ہے۔ وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے بھیجتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ایک تو اس کی زبان یعنی زبان چلی گئی، اردو میں شکشا لے نہیں سکتا، انگریزی وہ جانتا نہیں، ہندی میں اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے کمپیٹیشن میں وہ دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ ویوہار میں، زندگی کے کپڑوں میں، چلنے میں، ہوم ورک میں پیچھے رہ جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے مسلمان بچوں کا۔ اس کو دور کرنے کے لئے آپ کو سینسیٹو لی معاملے میں سمجھ کر اس کے لئے فوکسڈ پروگرام بنانے ہوں گے۔ جب تک آپ فوکسڈ پروگرام نہیں کریں گے، آپ نیچے سے نیو لے کر کام نہیں کریں گے، ہوا میں قلعے بنوائیں گے، تو مجھے معاف کریں، اس سے مائنارٹیز کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے، مائنارٹیز سے جڑے کچھ اہم

افراد جن کے پاس پیسہ ہے، جن میں صلاحیت ہے، ان کو فائدہ ہو جائے گا، انسٹی ٹیوشنس بنالیں گے، پیسہ کما لیں گے، کروڑوں کمائیں گے، ان کو فائدہ ہوگا، مائنارٹیز کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ مائنارٹیز کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور اس دیش کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کام کو لے کر چلیں اور جو راشٹریہ ابھیان شکشا کا ہے، اس میں آپ ان کے لئے الگ سے فوکسڈ پروگرام تیار کریں، یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔

سر، میں پھر آپ کے مادھیم سے کہنا چاہوں گا کہ جب آپ پچھلی بار بل لے کر یہاں آئے تھے، اس وقت بھی ہم نے بحث کی تھی اور اس میں خامیاں گنوائی گئی تھیں۔ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ عمل جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ پچھلی بار آپ نے کچھ یونیورسٹیاں نارتھ ایسٹ کی اور ایک دہلی یونیورسٹی رکھ دی تھی۔ یہاں بھی مجھے پرسنلی ایکس پیریئنز ہوا ہے کہ جن انسٹی ٹیوشنز نے دہلی یونیورسٹی میں اپلائی کیا، مائنارٹی کے انسٹی ٹیوشنز جنہوں نے ساری تیاریاں مکمل کر کے، بلڈنگ بنا کر کے، فرنیچر خرید کر کے، سامان خرید کر کے، جتنی ضرورتیں ہیں، سب پوری کر لیں، کہیں سے پیسہ اکٹھا کر کے، محنت کر کے، اس کے دہلی یونیورسٹی میں این.او.سی. کے لئے اپلائی کیا، لیکن دہلی یونیورسٹی سے آج تک کسی بھی انسٹی ٹیوشن کو جواب نہیں ملا۔ ایک جواب نہیں ملا۔ اور ہمارے لوگ جب وائس چانسلر سے ملنے گئے، ان سے رکویسٹ کی، کہ اس کے بارے میں کوئی جواب دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس مشینری نہیں ہے۔ یہ دیکھنے کی، آپ کے یہاں آ کر انسپیکشن کرنے کی، سمجھنے کی اور اس کے لئے این.او.سی. دینے کی میرے پاس مشینری نہیں ہے۔ میں منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یونیورسٹیوں کو کہہ تو دیا، لیکن کیا ان یونیورسیز کو انسٹرکشن دی ہیں کہ مائنارٹیز کے جب آپ کے پاس ایفی لیشن کے لئے آئیں، تو آپ ان کو ایفی لیشن دیں۔ آپ اس کے لئے ایک وقت مقرر کیجئے کہ تین مہینے کے اندر یا چھ مہینے کے اندر آپ کو ایفی لیشن دینا ہے نہیں تو جواب دینا ہے۔ کہ کیوں نہیں دیا آپ نے ایفی لیشن۔ یہ بہت جلدی ہے، ورنہ یہ کاغذ پر ہی رہے گا، جیسا ہم نے پیچھے دیکھا ہے۔ آپ آرڈیننس لائے کہ بہت ضروری ہے، بہت ایمرجنسی ہے، آپ تو آرڈیننس لا رہے ہیں، لیکن وہاں پر چٹھی کا جواب دینے کے لئے کوئی یونیورسٹی تیار نہیں ہے کہ آپ نے ایفی لیشن کے لئے اپلائی کیا ہے تو ایفی لیشن دیں کہ نہیں دیں۔

منتری جی، اس کے لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر دھیان دیں، تب ہاں، ہم سمجھیں

گے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ واقعی چاہتے ہیں۔ نیت تو ٹھیک ہے، نیت آپ کی ٹھیک رہی ہے، لیکن عمل آپ کا پچھلے ۵۵ سالوں میں خراب رہا ہے اور اس کے بارے میں، میں اس بات کو ایمانداری سے کہنا چاہوں گا کہ عمل میں پارٹیوں کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ مائنارٹیز کے تعلق سے کسی کی نیت میں بھی کھوٹ نہیں ہے، نہ جوشی جی، آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، نہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے.....مداخلت.....

ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی : ہماری نیت میں کھوٹ نہیں ہے، یہ تو ہم نے ثابت کر دیا ہے.....مداخلت.....

شری شاہد صدیقی : وہ ایک الگ بحث ہے۔

شری اُپ سبھاپتی : آپ کچھ ٹائم اپنے ساتھی کے لئے چھوڑنا چاہتے ہیں یا نہیں؟

شری شاہد صدیقی : اصل بات یہ ہے یہ جب عمل کا وقت آتا ہے، تو ہمارا سسٹم جس طرح سے کام کرتا ہے، وہاں ہم بھی اس کام کو نہیں کرا پاتے ہیں۔ اس لئے آپ کو سسٹم پر دھیان دینا ہوگا اور انہیں بادھ کرنا ہوگا کہ یونیورسٹیز ان کو ایفی لیشن دیں۔

سر، میں آخر میں، یہ کہنا چاہوں گا کہ آج دنیا میں جہاں بھی ہم جاتے ہیں۔ ہم کسی بھی لیول پر بات کرتے ہیں، چاہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے بات کرتے ہوں، چاہے عام آدمی سے بات کرتے ہوں، ایک بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان، جو اتنی بڑی تعداد ہے، شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہے یا دوسرے نمبر پر ہے، وہاں پر آتنکواد ان کے بیچ کبھی جڑ نہیں بنا سکا، ایک آدھ کوئی انفرادی نکل آیا ہو، لیکن جڑ نہیں بنا سکا؟ کیوں ہندوستان کے مسلمان آتنک واد سے نہیں جڑے ہیں؟ یہاں تک کہ کشمیر کے معاملے میں بھی، ہندوستان کے جو باقی حصوں کے مسلمان ہیں، انہوں نے کبھی بھی اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، اس کا ساتھ نہیں دیا اور ہم فخر کے ساتھ ہر جگہ کہتے ہیں کہ اس کا کارن ہمارے ملک کا کلچر ہے، ہماری سبھیتا ہے، ہماری پرمپرا ہے اور ہمارے ملک کا لوک تنتر ہے جس کے ایک الگ ماحول دیا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کا مسلمان ایک یونک مسلمان بن کر نکلا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں، دنیا کے مسلمانوں کی لیڈر شپ کا رول جو ہے، رول ماڈل کا جو رہل ہے۔ وہ ہندوستان کا مسلمان دے رہا ہے اور آنے والے وقت میں دے گا۔ آج دنیا میں جو زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرس اور انجینئرس پیدا ہو رہے ہیں، وہ ہندوستان کا مسلمان دے رہا ہے اور ہمیں، صرف ہندوستان کو دنیا کی لیڈر شپ کا رول نہیں کرنا ہے، ہندوستان کے مسلمان کو بھی مسلم ورلڈ کی لیڈر شپ کا رول کرنا

ہے، اوران کو راستہ دکھانا ہے اور وہ آج جس کھائی میں ہیں، جس اندھیرے میں ہیں، اس سے نکال کر انہیں روشنی کی طرف لانا ہے۔ اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہندوستان کا مسلمان بھی اسی طرح سے نیشنل کیپٹل بنے، ہماری لیبر فورس جو ہے، ہماری پاپولیشن آج ہماری سب سے بڑی کیپٹل ہے لیکن یہ کیپٹل تب ہے، جب ہمارے پاس شکشا ہو، ہمارے پاس سواستھ ہو اور ہمارے یہاں سوشل پیس ہو۔ اس سوشل پیس کو بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ہر سیکشن میں یہ احساس آئے کہ اس اسٹیٹ میں، اس پائی میں میرا بھی ایک حصہ ہے اور وہ احساس دینے کا کام آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے اور ان کا بھی ہے۔ وہ احساس اگر ہم دیں گے تو آنے والے وقت میں ہندوستان دنیا کو لیڈ کرے گا، ہندوستان سے عبدالکلام جیسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہندوستان کی شان بھی ہوں گے اور مسلمان کی بھی شان بنیں گے اور دنیا میں ایک پیغام دیں گے۔ اس کے لئے میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ من سے یہ بات نکال دیجئے کہ کوئی آتنک واد کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ ارے، آتنک واد تو ہم نے گجرات میں نہیں پنپنے دیا۔ مجھے یاد ہے، میں اور کلدیپ نیر جی جمشید پور گئے تھے۔ جمشید پور میں دنگا ہوا تھا۔ ایک ایمبولینس کے اندر سوا سو لوگ زندہ جلا دئے گئے تھے، جس میں بچے اور عورتیں تھیں۔ ایمبولینس کو بند کر کے، پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی اور کلدیپ نیر صاحب نے وہاں کے مسلمانوں نے پوچھا تھا کہ ان حالات میں کیا تم پاکستان جانا چاہو گے، یہاں سے کہیں محفوظ جگہ جانا چاہو گے؟ تب وہاں کے مسلمانوں کا جواب یہ تھا کہ کیوں جانا چاہیں گے پاکستان، یہ ہمارا وطن ہے، ہم یہیں مریں گے، اسی مٹی کے اندر دفن ہوں گے۔ میں نے آج تک کسی دنگا پیڑت علاقے میں کسی ایک مسلمان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میں دیش چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس کے دیش پریم میں کوئی کمی نہیں آتی۔ گجرات کے باوجود، جمشید پور کے باوجود، بھونڈی اور جل گاؤں کے باوجود تو ہم یہ کالج کھول کر، یونیورسٹی کھول کر کیسے آتنک واد کی طرف جا سکتے ہیں؟ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا ایک ایک مسلمان ملک پر مرنے کو تیار ہے۔ اسے شکشا دے دیجئے، اسے آگے بڑھنے کا موقع دے دیجئے۔ وہ اس طرح سے سیوا کرے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ ہندوستان کے مسلمان نے اس دیش کی کس طرح سے سیوا کی ہے۔ بہت بہت دھنیواد۔

"ختم شد"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Malaisamy, Mr. Ravi Shankar Prasad has made a request because he has to go to hospital for some urgent thing. So, I am calling him.

DR. K. MALAISAMY (Tamil Nadu): I do not mind.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I am extremely grateful to you for the kind indulgence you have given.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: To him also.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I am speaking only because my dissenting note has become the object of discussion. Sir, let me begin by seeking two queries from the hon. Minister. The original National Commission for Minority Education Act came into force on 6th January, 2005. 6 जनवरी 2005 को आपका ओरिजनल एक्ट बना और आप अमैंडमेंट ला रहे हैं, अगस्त 2005 में। पहला बुनियादी सवाल यह उठता है कि कोई भी नया एक्ट बनता है तो उसको कुछ समय आप काम करने के लिए देते हैं, उसके ऐक्सपीरिएंस को देखते हैं और देखने के बाद अगर लगता है कि दिक्कत हो रही है तो आप उसमें संशोधन करते हैं। यही हम लोगों का अनुभव भी है, यही इस सदन का अधिकार भी है। माननीय मंत्री जी, मेरी पहली परेशानी यह है, जिसके बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि सिर्फ सात महीने में ऐसा क्या हो गया कि इस पूरे मूल अधिनियम में इतने बड़े परिवर्तन की आवश्यकता हुई? मैं, जब आपके संशोधन बिल को देखता हूं, तो उसके ''स्टेटमेंट ऑफ ऑबजेक्ट्स ऐंड रीज़ंस'' से इसकी तीन लाइनें कहना चाहता हूं।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन) पीठासीन हुए।]

शाहिद भाई, आपने अभी बहुत जोरदार भाषण दिया है, यह सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं आपकी बात से शुरू करूंगा।

"The majority of the representations received by the Commission have drawn attention to the problem faced by minority communities in obtaining no objection certificate for establishment of educational institutions, and for such eligible institutions from obtaining the status of being the minority institutions.

अगर आप कोई नया इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, आपने उसके लिए apply किया, आपने बिल्डिंग बनाई, आपने कुछ काम किया, तो इसके लिए आप साल-डेढ़ साल-दो साल का वक्त देंगे या नहीं देंगे? सिर्फ सात महीने में ऐसा क्या आ गया, कि इतने representations आ गए कि हम लोगों

ने दरख्वास्त दी कि बहुत डिफिकल्टी हो रही है No Objection Certificate लेने में? I wish to make it very clear hon. Minister that this is your statement in the Bill of the Government और यहां पर मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे दोस्त शाहिद सिद्दिकी ने कहा कि इसका purpose जो है, हम सभी एक राय के हैं, बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने कि अकल्लियत आगे बढ़ें, पढ़ें। पढ़ाई में कमजोरी किसकी है, हम सभी जानते हैं। जो उसमें बैकवर्ड हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनके यहां पढ़ाई की बहुत कमी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे अमेंडमेंट का purpose ऐसा है कि हमें कॉलेज स्थापित करने का बिल्कुल अनलिमिटेड अधिकार मिले, जिसमें हम जैसा चाहे, वैसा करें–इसको मैं आगे explain करूंगा। आपके original Act के दफा 10 में लिखा था कि आप सरकार से कंसल्ट करेंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं पढ़ना चाहता हूं 10(2) को and 10 (2) says, "The Scheduled University shall consult the Government of the State in which the minority education institution seeking affiliation under sub-section (1) is situated and views of such Government shall be taken into consideration before granting affiliation."

अपना संविधान है। उसमें राज्यों का एक अधिकार है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता भी है, राज्य का अपना एक अधिकारी भी है और संविधान की एक संघीय परम्परा को भी हम सभी समझते हैं। अब जो आपने परिवर्तन किया है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट लूप में कहीं नहीं है, यह मैं कहना चाहता हूं। मेरे मित्रों ने इसको पहले जरूर पढ़ा होगा, आपने एक कंपीटेंट अथॉरिटी बना दी। उसमें आपने कहा कि उनको No Objection देने का अधिकार होगा और उसके बाद आपने कहा, मैं अमेंडमेंट का 10(3) पढ़ रहा हूं–

10 (3) says, "Where within a period of sixty days from the receipt of the application under sub-section (1) for the grant of no objection certificate,—

the Competent authority does not grant such certificate; or where an application has been rejected and the same has not been communicated to the person who has applied for the grant of such certificate,

It shall be deemed that the Competent authority has granted a no objection certificate to the applicant."

माननीय मंत्री जी, इसका मतलब यह हुआ कि किसी एक शख्स ने आवेदन-पत्र दिया। वह आवेदन-पत्र निचले स्तर पर क्लर्क के यहां दब गया, साठ दिन की मियाद पूरी हो गई और No Objection दिया हुआ माना जाएगा। राज्य सरकार लूप में नहीं है, आपने एक कंपीटेंट अथॉरिटी बना दी और साठ दिन में डीमिंग फिक्शन देकर permission दे दिया। इसका क्या मतलब है और

मैं यह कहना चाहता हूं, मैंने dissenting नोट में कहा था कि जिस समय में हम रह रहे हैं, वह टेररिज्म का समय है और माइनॉरिटीज़ का पूरा विकास होना चाहिए, लेकिन कुछ में फंड कहां से आ रहे हैं, यह मालूम कैसे होगा? कल अगर दाऊद इब्राहिम कोई फ्रंट खोलना चाहते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का, तो यूनिवर्सिटी के पास मशीनरी नहीं है जांच करने की, क्षमा करें मंत्री जी। हम जानते हैं, इस मुल्क में–आज संसद में मेरा सवाल था, साउथ के टेररिज्म पर। सात-आठ ऐसे फ्रंट्स हैं, जो टेररिज्म के फ्रंट के रूप में काम करते हैं। क्या उस सच्चाई से हम मुंह मोड़ सकते हैं? मैं शाहिद भाई की बात का बिलकुल इकरार करता हूं कि मेजॉरिटी मुसलमान नहीं हैं ऐसे, देशभक्त हैं, लेकिन कुछ लोग इस फ्रंट का दुरुपयोग करेंगे, उस फ्रंट की जांच का क्या प्रावधान है? स्टेट गवर्नमेंट लूप में नहीं है, साठ दिन में डीमिंग फिक्शन हो गया, यूनिवर्सिटी के पास कोई infrastructure नहीं है, वह सिर्फ affiliation देगी। माननीय मंत्री जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम सभी देश की सबसे बड़े पंचायत में बैठे हुए हैं और यह पंचायत जब कानून बनाती है, तो आने वाली नस्लों के लिए बनाती है। हम कानून रोज़ नहीं बदलते, लेकिन एक कानून ऐसा जरूर बनाना चाहिए, जिसमें इन संभावनाओं की चिंता करने की जरूरत हो और मैं बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं कि यह पूरा जो संशोधन आया है, जो मैंने पहली बात कही, बिना किसी application of mind के आया है। सात महीने बहुत छोटा समय होता है, किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के संबंध में नियम के काम करने का। कोई empirical evidence नहीं है। एक आपने कह दिया कि कुछ लोग चाहते हैं, हमें दिक्कत होगी और हमने कर दिया, तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही गंभीर विषय है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं यहां पर अपने दोस्त शाहिद सिद्दिकी की बात का समर्थन करके, अपनी बात खत्म करूंगा। हम सभी समझते हैं कि माइनोरिटी का विकास तो होना चाहिए। मैं यह भी मानता हूं कि इस देश का विकास शिक्षा के क्षेत्र में तब तक नहीं होगा जब तक इस देश की अक्लियत का विकास नहीं होगा। मैं आपकी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर जोर से कहना चाहता हूं, लेकिन अक्लियत का कौन सा स्टैंडर्ड, which standard of minorities, I would like to know. मैं यह चाहूंगा कि मंत्री जी कभी हमारे सामने इस बात को कहें कि क्या उन्होंने कोई व्हाइट पेपर बनाया है कि अभी तक जितने माइनोरिटीज इंस्टीट्यूशन्स खुले हैं, उनमें किस स्तर के लोगों को एडमिशन दिया गया है? उनमें क्या-क्या मार्केटिंग ऑरिएंटेशन प्रोफिट था? कहीं पर तो इस की सबसे बड़ी पंचायत को बताया जाना चाहिए। हमारे वामपंथी मित्र केरल के अनुभव से बोल रहे थे, With their experience, they are also supporting. Shahid bhai, what were you speaking? What I am speaking is that there is a serious apprehension that the realy rights of the needy among the minorities who want exposure to education would be negated and, again, this may become a money shop. इसका आपके पास क्या रास्ता है? माननीय डा॰ जोशी जी ने बहुत विस्तार से

कहा है कि जो कमीशन इसके अंदर बना है, वह माइनोरिटीज कमीशन के ऊपर हो गया है। डा॰ जोशी जी ने इस पर चर्चा भी की है संघीय व्यवस्था का किस प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है, उसको विस्तार से रखेंगे। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप इस संशोधित बिल की धारा-12 (c) को देखें, जिसमें कमीशन को इस बात का अधिकार दिया गया है, कमीशन जांचे कि यह कॉलेज माइनोरिटीज इंस्टीट्यूशन है या नहीं? उसमें उसको क्या देखना है। शाहिद भाई, आपको इस प्रावधान को देखना चाहिए। 12(C)(b) says, 'If, on verification of the records during the inspection or investigation, it is found that the Minority Educational Institution has failed to admit students belonging to the minority community in the institution as per rules....' तो उनका निबंधन कैंसल हो सकता है। वहां पर माइनोरिटीज के किस स्तर के बच्चे आ रहे हैं? वहां पर कितने उपेक्षित बच्चे आ रहे हैं, कितने सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे आ रहे हैं, कम से कम यह भी तो देना चाहिए था। यह बिल्कुल ठीक है कि माइनोरिटीज इंस्टीट्यूशन्स में गैर माइनोरिटीज न जाएं, लेकिन आज इस मुल्क में जुलाहे हैं, अंसारी हैं और कितने अन्य पिछड़े हुए हैं, जिनका मैं नाम लेने की जरूरत नहीं समझता हूं, जिनको शिक्षा की सबसे बड़ी जरूरत है। आपने इस पूरे एक्ट में इतना बड़ा कमीशन बनाया और आपने इस कमीशन को इतनी बड़ी ताकत दे दी कि वह संघीय संविधान से बड़ा है, वह भारत के माइनोरिटीज कमीशन से बड़ा है। जो आपने एक नया माइनोरिटीज विभाग बनाया है, शायद इससे भी बड़ी ताकत है। इस कमीशन को, इस बात को जांचने का कोई अधिकारी नहीं है कि माइनोरिटीज में जिनको शिक्षा की जरूरत है, उनकी इंस्टीट्यूशन्स में क्या चिंता हो रही है? शाहिद भाई, बड़ी विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माफ करना ये सारी दुकानें खुलेंगी। ये दुकानें खलने वाली हैं। इसलिए संशोधन में, प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है कि बार-बार रेप्रेजेंटशन आया कि नो-आब्जेक्शन मिलने में कठिनाई हो रही है, तो साढ़े 6 महीने में क्या कठिनाई हो गई? जबकि एकेडेमिक ईयर एक साल का होता है। नए इंस्टीटयूशन को स्थापित करने में दो साल लगते हैं तो साढ़े 6 महीने में ऐसी कौन सी बाढ़ आ गई कि इतना बड़ा संशोधन करने की नौबत आई। आनरेबल वाइस चेयरमैन सर, I do not want to speak for long. But, I only say that this whole amendment raises a very serious concern.

Then, I come to my last point. And, what is that? All of us want minorities to grow. Unfortunately, what happens is, इसकी आड़ में हमेशा कुछ न कुछ काम हो जाता है, माफ करना जिससे तफरकात बढ़ता है, जो उपेक्षित हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जिनको शिक्षा भी जरूर है, वे फिर हाशिये पर चले जाते हैं। मुझे इस बात की पूरी आशंका है कि यह पूरा संशोधन वहीं होने वाला है। मंत्री जी, अंत में मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि जो मैंने मुद्दे उठाए हैं, ये बुनियादी मुद्दे हैं, ये बनें, अच्छे चलें और भविष्य में रहें, लेकिन सारे यही अनुभव आ रहे हैं कि यह ठीक नहीं चल रहा है,.इसकी चिंता करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. K. MALAISAMY: Thank you very much Mr. Vice-Chairman, Sir. I have been given the last minute choice and chance by my Party to speak on the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): But, remember, your time is only 11 minutes. You have to limit your speech within that time.

DR. K. MALAISAMY: Okay. I did not have much time to prepare myself and do the homework, which I, usually, do. But, however, I have made a hop, step and jump strategy to go through the Bill, and to cut out a few points by way of my observation. ...(*Interruptions*)... Sir, at the outset ...(*Interruptions*)... Sir, if Mr. V. Narayasamy interferes, I will take more time.

THE VICE-CHAIRMAN (Prof. P.J. Kurian): Please don't interfere, ...(*Interruptions*)...

DR. K. MALAISAMY: Sir, at the outset, I am inclined to support the Bill. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Go ahead.

DR. K. MALAISAMY: ...on behalf of the AIADMK, which is very keen to protect and promote the interest of the minorities and our hon. Chief Minister, Ms. J. Jayalalitha, who has taken personal interest to protect the interest of these minorities. As such, I am very much concerned to support the Bill.

I would like to observe that it is a right Bill in the right direction. It is a milestone in the history of minorities. Sir, according to Gandhiji, the civilization of society very much depends upon the treatment given or extended to the minorities. Sir, we are dreaming that we will be a developed nation by 2020 wen all the minorities in the country should realize and feel that they have got enough security and confidence among themselves. Under these circumstances, the Bill has come. This is not a new idea. On the other hand, it was envisaged even earlier in our Constitution, under article 46, how the economic interest and educational interest of the minorities and weaker sections could be safeguarded, with special reference to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. All these things were there. Ever since independence, several legislations,

notifications, institutions have come to implement this objective envisaged in the Constitution.

Even as early as 2004, they issued an ordinance contituting a National Commission to take care of the educational institutions, of minorities and the ordinance which became an Act; and now an amendment has come. What exactly does the Bill say. The Bill has got a wider scope and a purposeful appreciation of the reality of the situation.Whatever may be the background or the controversy which has provoked them to bring the Bill, whether Aligarh Muslim University or the reservation by the Andhra Pradesh Government, I don't want to go into the details, whatever be the background, they have brought the Bill now. I could see that between the earlier ordinance, which became an Act, and the present Bill, a lot of improvements have been made. It has spoken about the time frame. They have fixed up the time frame as 60 days for the issue of the NOC, failing which, it will be taken as if the NOC is given. Okay. Then, once an order is issued the aggrieved party can have the power of appeal?

Sir, there are other features also—the status and misuse. I mean, the Commission can go into the misuse.

Leaving apart the special, good features of the Bill, I have got one or two major points for which I need the clarification from the hon. Minister. I will take a few minutes. Generally, I am very brief and very, very quick.

I now come to the first point. The scope has been widened. The purpose has been given. I would like to know whether there is an institution to implement all these things. Whatever may be their system, whatever may be their objective, for achieving anything, there should be an objective, there should be an organization, there should be right people for the right task, and there should be an operation. If all these things go together, then, only the purpose will be achieved. I would like to ask a specific question. You have already given an ordinance, replaced by an enactment, now you have come for an amendment. I would like to know whether you are capable of implementing the Act in its letter and spirit. This is my first point. I would like to, specifically, as the hon. Minister—Mr. Narayanasamy and Mr. Jairam Ramesh, the hon. Minister are here, they will always be pitching upon whether I am using the word system failure or human failure—

whether there could be a system failure or human failure in implementing the amendment... *(Interruptions)*...

Coming to the second point, this Bill empowers the Commission to proceed against the minority institutions. This Bill, when it becomes an Act, will empower the Commission to take action against those institutions, which are misusing the power. Here, I would like to ask the hon. Minister whether you have got enough safeguards and parameters to see that those misuses are booked correctly.

Sir, my third point, which is very, very important, relevant is this. I would like the hon. Minister to clarify what the minority status is. Will it be linked with religion, or, will it be linked with minority of students or past precedents? Under the Act, only five communities have been recognised as minorities, namely, Muslims, Christians, Buddhists, Parsis and Sikhs. What I am trying to ask is, other than these five communities, which are the other minorities? What about the linguistic minorities? This is my specific question to the hon. Minister.

Coming to the next point, what is the definition of mirorities? Normally, when there are two groups, a small group is known as minority. In South Africa, the minority group is not recognised as minority. They don't like at all to be recognised as minority. On the other hand, the power, authority and domination are only with the minority. In a situation where the minority community has got all the authority and powers, do you mean to say that they are going to be recognised as minority? What I am trying to say is, not only in numerical numbers, but also in domination, in power, authority, are relevant to decide minority. There are some minority communities. They want to preserve their own identity. They don't like to be treated as minority at all. In such a situation, what are you going to do? I need a specific definition, and want to know how they are going to impelment that.

Coming to the most important point, which is regarding reservation. Many of our friends have spoken about it, that is, reservation of seats in the educational institutions. Now, beyond 50 per cent has been struck down by the highest court of law. In Tamil Nadu, we are giving 69 per cent reservation, which is more than 50 per cent. We are able to implement this all these years. So, these are the situations. What is this Commission going to do in such a situation?

Sir, in your new Act, you have said about the court jurisdiction. You have barred the civil courts, etc. Okay. It is well understandable, but what I am trying to ask is, the High Court and the Supreme Court have got writ jurisdiction, and other inherent powers. Can you prevent them from interfering in that? ...*(Interruptions)*.

SHRI B.S. GNANADESIKAN: (Tamil Nadu) Normally, in an enactment, there will be a section. It applies only to civil courts. It will not apply to article 226 or Supreme Court's special powers.

DR. K. MALAISAMY: That is what I am trying to say. You have barred only the civil court, not the other courts. What is the use? When the civil courts are barred, the other courts will come in. In other words, your process will get delayed in High Court/Supreme Court through. The civil court may not have jurisdiction...*(Interruptions)*...

SHRI B.S. GNANADESIKAN: You cannot bar by an Act.

DR. K. MALAISAMY: The point is whether an aggrieved party can go to a court of law. He cannot go to a civil court, but, he can go to a High Court, or, Supreme Court. Again, process can be delayed like anything. That is what I am trying to highlight.

Finally, Sir, Mr. Vijayaraghavan also spoke on this ...*(Interruptions)*....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Please conclude.

DR. K. MALAISAMY: Sir, this is the last point. If you say so, I will abide by it. The last point is this. Sir, the State Government has been prevented. This Act empowers the Minority Commission, whereas the State has no jurisdiction in certain matters. Will it be in order to say that when the State is there—without the consultation, without the concurrence and without the consent of the State Government, you are doing so many things— can you implement anything without the approval, without the support, without the concurrence, without the consent of a State Government? Sir, particularly, States like West Bengal or others which are bordering the other countries have got numerous problems. This has already been highlighted. I am not going into that.

In such a situation, preventing the State from interfering and giving their views, and empowering only the National Commission, is not at all in order. They have to think over twice before doing anything. Thank you.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI (Kerala): Sir, I am thankful to all the hon. Members who have already spoken. I am not going into the details of the subject under discussion due to time constraint and also because many of the points have already been explained by other Members. But, Sir, I would definitely like to refer to some of the issues which have been raised by some hon. Members.

Sir, whenever something comes about the educational advancement or the social progress of the minorities, then, many, many issues are being brought into the arena of discussion. I, very humbly, would like to comment there, Sir, that that is very unfortunate. This is regarding education, and everybody agrees—it is an established national reality—that the minorities are backward. Many, many Commissions have brought forth the very pathetic conditions which are faced by the minorities at the social level, at the educational level, at the economic level, and at all levels of life. But, Sir, when some move is made for their advancement, then, I feel that there must be some kind of a consensus among the different parties of our country, political parties in the House, at least, to the aspect of the minority communities' advancement.

Sir, instead of that, it is made an issue of propaganda, and there is a systematic propaganda going against the minorities. Sir, I would like to congratulate the hon. Prime Minister because he, the UPA Government, has come forward with some concrete moves to take the minorities to progress, to undo their backwardness. That has to be seen in the positive sense instead of making it a tool for unnecessary propaganda. For example, I would not understand one thing. Our hon. Member, Joshiji, started the discussion. Afterwards, some hon. Members who were speaking from the other side of the House and one senior Member were referring to the Constitution's article No. 14. I would like to ask them what about the Constitution's articles 25-30. The Constitution has got very clear-cut provisions with regard to the condition of the minorities. Even under the Fundamental Rights, every person is entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practise and propagate religion. All these things are very much known to us. The allegation or the criticism made by some hon. Member was that this legislation is to misuse law. I would like to emphasise here that the Government wants to use the law. This amendment is for using the law, for protecting the law because this is as per the Constitution. It is to establish the constitutional standards that

the Government has come forward with this kind of an amemdment. Sir, even the Shah Bano case has been referred to. I can't understand what is the relation of this Minority educational Institutions Bill with the Shah Bano case. This is the kind of propaganda which is going on. I think, Sir, we have to get rid of this kind of politicisation of the issue. Even in the morning, when we were discussing the issue related to massacre of *Adivasis*,—actually, it is a national calamity—there was a consensus not to misuse it for political ends. Among all political parties, I think there is a consensus that this kind of serious issues, tragedies could not be made an issue of propaganda.

Sir, I have immense respect for Shri Ravi Shankar Prasad, and indeed, for all the hon. Members sitting in the other side. He made the comment that some people, some terrorists, are spoiling the name of minorities. He even mentioned some name here. Sir, I don't understand this. How could we connect some person with a community? This is meaningless. If somebody is spoiling the integrity of the country, they are the enemies of this country. We have to stand united against them, whether they belong to this community or that community. It is not the problem of a minority or a majority; it is a national problem. They are enemies of the nation and we should not link them with any community. I think this old disease needs to be treated well. It is very bad and unfortunate. It is an injustice against humanity to connect, to link, some kind of a religious group with terrorism. Terrorism has nothing to do with religion. Which religion, which social group, has encouraged terrorism in this world? If some Hindu is making some kind of a mistake, is Hinduism responsible for that?

अयं निजः परोवेति गणनां लघुचेतसाम्।
उदारचरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।

Hinduism is a religion of Vedas and Upanishads, which says that the world is one single family. How can Hinduism be linked with some kind of terrorism? If somebody is committing some kind of violent act, it is an attack. His act is an attack against humanity. But, to connect terrorism with religion is also a mistake.

Sir, I believe that every religion believes in peace. Every religious group, whether it is Hinduism, Christianity, Buddhism, Islam or any other, believes

in peace. The very breath of Hinduism, the inner spirit of Hinduism, is linked with the great mantra of "Om Shanti", for peace. Christianity always celbrates peace in the heavens, and peace on the Earth. It was taught by the holy Prophet to the Muslims that they have to always chant this praye: 'O God, O Allah, you are peace; lead us to peace.' So, religion is nothing but peace. Wherever we are, religion, is for peace. Religion is peace. Even the world 'Islam' is derived from 'Slim' in Arabic language, which means 'peace'. So, it is a great mistake to connect terrorism to this group or that group, or to some religion. That will be an injustice against humanity.

Sir, I am referring to this because this kind of an issue has been raised, which has nothing to do with our Bill. It has nothing to do with the present amendment. This Bill is for the educational advancement of a backward section of our society; they are our citizens. They have to be brought into the mainstream.

Sir, many unnecessary issues have been raised here. Even the issue of Aligarh Muslim University was raised. I cannot understand this. Aligarh Muslim University was started by a minority and run by a minority. Aligarh is a great centre of national renaissance. I am not here to raise such an issue; I am not bringing this issue up for discussion. But once it has been raised, we need to respond to it.

Sir, we were told that the Government is going to take some concrete steps to reestablish the minority character of the Aligarh Muslim University. Is it not the duty of the Government to protect the character of a great institution run by the minorities, which was started by the minorities as part of the national renaissance?

Sir, please don't connect this with vote bank. Whenever there is something about minorities, *vote bank, appeasement, minoritism,* are the kind of words that are brought in. This is diluting the subject in a way. It is in the interest of civilization that minorities rights are to be protected.

Sir, there are many resolutions of the United Nations Organization saying that every country has to take its minorities into protection; they have to safeguard their interest; they have to protect their rights. There have been many resolutions of the UNO, UNESCO, etc. because it is nothing but they duty of a civilized society to protect them. We have to protect our minorities.

Sir, India has had a great tradition, a historical tradition. India always stood for the protection of minorities. It is nothig new. It is not a new initiative of the UPA Government. We follow that great tradition. Our history, our great cultural heritage, and our traditions speak vehemently about the pluralistic nature of our society, and our protection of other religious groups. India, which is a land of Vedas and Upanishads, was always thirsty for religions. Even after that, our spiritual thrust was remaining and we used to welcome other religions. India gave birth to major religions in this country. Instead of that, India welcomed three great world religons from abroad. Sir, I am referring to these things because it is the duty of all of us. When the Holy Prophet was there in Madina, when he established a society there, he gave a Charter to the minorities there 1400 or 1500 years ago. It is known as the Charter of Madina and it is still available. In that Charter, the Prophet says to the Jews minority community, 'you are here as a part of the society; we are here to protect you; if anybody comes from outside to fight against you, we will be there to protect you.' These were the words given by the Prophet to the Jews community 1500 years ago. Everywhere civilisation means protection of the minority. Sir, here in India, minorities, representation is not very appropriate due to many historic reasons whether it is in higher profession, education or whether it is in social or economic condition. It is not the time to enter into such a debate. The minorities are backward and it is social phenomenon rather than an economic phenomenon. I am reminded of the great ideas of Ram Manohar Lohia who was successful in actually analying the social situation of India, its backwardness and the backwardness of many sections of our society. It is not economic; it is social. Babu Jagjivan Ram, who was considered as a great leader of the country, whose name was even considered for the Prime Ministership of this country, went to a function relating to unveilling of a statue. I remember, it was the statue of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi. Some people desired to wash the statue with the water of the Ganga. It was not the problem of Jagjivan's birth; it was not the problem of Jagjivan's economic condition, it is something connected with the social backwardness, the age-old divisions of our society and that has to be fought by the Government and all those backward sections are to be served and they are to be brought

into the national mainstream and it is a national necessity of the country. Sir, it is an established fact ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Please conclude.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: I am concluding, Sir. When Rajinder Sachchar Committee was appointed, the same hue and cry was made. It is not a new Commission. Many commissions were constituted by the previous Governments. Gopal Singh Panel Report is there; Reports of the Forty-Third and the Fifty-fifth Round of the National Sample Survey are there and Programme of Action of the New Education Policy of 1986 is there. All these reports unanimously speak fo the backwardness of the minorities, and facts and figures are there. So, Sir, no country can progress, no country can be stable and no country can be taken into progress when a section of the society is alienated; when they are marginalized and when they are away from the mainstream. Sir, the Muslims are the largest minority. I think the hon. Member, Joshiji, will agree with me—he was running the Ministry of HRD very effectively for a long time—that their representation in Class-I service in the Central Government is 1.6 per cent. This is the backwardness. This is the condition of backwardness that they represent 1.6 per cent of a pupulation which comes to about 12 per cent. But, Sir, it is a talented community. All the minority communities of this country are talented. They are backward due to many other reasons, but they are talented. Every backward section, every talented community has to be utilised by the Government. It is a human resource. It is a national asset.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Please conclude.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: So, Sir, this national asset has to be utilised. For that, they want inclusion instead of exclusion. I think, this amendment is a real step forward for such a positive inclusion. I once again congratulate hon. Prime Minister and the hon. Minister for Human Resource Development, Shri Arjun Singhji, whose bold step and whose great secular credentials have been very much responsible for his kind of a very positive move. I once again support this amendment.

SHRIMATI N.P. DURGA (Andhra Pradesh): Sir, I rise to support the Bill moved by the hon. Minister. This move definitely helps the minorities, because if you look at the literacy rate amongst the minorities, it is, on

an average, ten per cent less than the national average. And, the progressive decline in the enrolment rate of children in schools is making matters worse. If this trend goes on, the purpose of setting up this Commission and the aim behind giving more powers to this Commission will get defeated. So, this is a step in the right direction and I am sure this would help in improving the literacy rate, and the number of minorities with higher qualifications will also go up. Sir, my Party welcomes it.

Sir, merely making legislations or giving powers to the Commissions such as this does not solve the inherent and orthodox beliefs that the minorities have. Even at a time when the country is repidly becoming a world power, I am sorry to say that many Muslim families do not get their children enrolled in schools. Orthodox parents do not send their daughters to co-educational academic institutions and some adults do not realise the benefits of education with regard to the welfare of their children, particularly girls. Of course, now, the situation is changing, but not as per the expectations.

The Bill speaks about various powers and functions of the Commission such as right to establish a minority educational institution, right to seek affiliation to any University, to enquire and investigate into complaints, etc. But, nowhere it has been mentioned as to what would be the principle to get a minority status under Article 30 of the Constitution. Would it be on the basis of minority students enrolled in that institution or the person who established it or is there any other norm? I request the Minister to clarify this point. The proposed amendment allows the minority institutions to seek affiliation to any university of their choice. This is a laudable step. Otherwise, the existing Act restricts affiliation to only selected six universities in the country. Earlier, the minority institutions were running from pillar to post for their affiliation. Some time back, Gopal Singh Panel revealed that even well-endowed and well-equipped minority educational institutions were facing discrimination such as refusal for getting recognition by various institutions and other statutory bodies. I am sure the proposed amendment solves this problem.

At the same time, what the Government is doing is only a drop in the ocean. And, a lot more needs to be done for the welfare of minorities. Sir, it is not out of place to mention that when TDP was in power in Andhra Pradesh, our leader, Shri N. Chandrababu Naidu, did a lot for the welfare and upliftment of minorities in Andhra Pradesh. We declared Urdu as

second official language of the State. We started *Roshni,* that is, self-help groups for minority women to empower them. We had one more scheme called *Dukan-aur-Makan* for minorities, under which our Government provided shops and houses to minorities and this Scheme was a stunning success. We constructed Haj House and also gave concessions to Muslims who go to Haj. We also constructed *Shadi Mahals* in almost all Mandals of the State, apart from various other measures for the welfare of minorities in the State.

The next point I wish to make is that under clause 4 of the Bill, the Commission has been given a free hand to intervene in any proceedings of a court. I am not a legal expert, but with the limited knowledge that I have, I would like to ask if it would not amount to tresspassing into the affairs of court proceedings. Even the Standing Committee is of the same view. So, I would suggest for the consideration of hon. Minister that the Commission's intervention should be restricted to only those cases where the courts request for assistance or help of the Commission. Otherwise, it may lead to a lot of complications and ultimately, the purpose of this amendment would be defeated.

Sir, sub-clause 10(A) speaks about the right of the minority educational institutions to seek affiliation to any university of its choice. It is good that you have enlarged the scope of affiliation of the minority institutions to any university from the existing six scheduled universities. If an institution is set up at Kanyakumari and wishes to affiliate itself with the Aligarh Muslim University, how can the Aligarh Muslim University monitor the performance of the institution, how can the University ensure that the institution is running as per the standards of this university and that the institution is following the guidelines issued to it from time to time? So, Sir, I would suggest for the consideration of the hon. Minister that if a minority educational institution proposes to affiliate itself with some university—naturally, it would wish to affiliate itself only with a reputed university—it has to be limited, or, some kind of geographical contiguity or State boundary must be there. This will smoothen the functioning of the institution.

Finally, Sir, nowhere in the Bill it has been mentioned that the National Minorities Commission is empowered by the Central Government to collect information, to conduct a scientific basic survey and to obtain accurate baseline information for use in planning the education of Muslim minority.

Here, I would suggest for giving special preference to localities populated predominantly with minorities while establishing educational institutions.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIAN): Please conclude.

SHRIMATI N.P. DURGA: I am concluding, Sir. I would also like to suggest that this Commission be empowered by the Union Government to collect information and report on the educational, social and economic conditions of minorities across the country.

With these words, I, once again, support the move of the Government. Thank You.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIAN): Now, Shri Motiur Rahman.

श्री मोतिउर रहमान (बिहार): आपने तो मेरा नाम ही सही नहीं बोला है, एक तो आपको पहले ही मुझे समय देना चाहिए था। ऐसा कैसे चलेगा?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIAN): I said, Motiur Rahman. I said it.

श्री मोतिउर रहमान: मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): मेरे खयाल में मैंने आपका नाम सही बोला I said, Motiur Rahman.

श्री मोतिउर रहमान: मैं तो सही नहीं सुन पाया, लेकिन अब आप उसे सही कर दीजिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं और इस बात के लिए यूपीए गवर्नमेंट को बधाई देता हूं कि जिस हिम्मत के साथ वे इतने बड़े बिल को लेकर आए हैं, वही व्यक्ति या वहीं इंस्टीट्यूशन इस प्रकार की हिम्मत कर सकता है, जिसका दिल एवं दिमाग साफ हों। पिछले 50 वर्ष में इस मुल्क में जितना नुक़सान माइनॉरिटीज़ को हुआ, उन्हें न तो सामाजिक तौर पर आगे बढ़ने का मौका मिला और न ही वे तालीमी तौर पर आगे बढ़ सके। दूसरे मामलों में भी जब कभी भी मौका मिला, इन भगवाकरण करने वाले लोगों ने, भाजपा के लोगों ने हमारे पैर खींचने का काम किया है। आज भी ऐसे एक बिल की मुखाल्फत करने की कोशिश की गई, जिस बिल के ज़रिए इस मुल्क के मुसलमानों को, माइनारिटीज़ को तालीमी तौर पर एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जब भी मौका आता है, ये आतंकवाद या आईएसआई के नाम पर मुसलमानों को बांटने की कोशिश करते हैं। जब इनकी हुकूमत थी एवं श्री जोशी जी एजुकेशनमिनिस्टर थे, तब इन्होंने एक सर्कुलर जारी करने का काम भी किया कि बिहार एवं दूसरी जगहों के मदरसों में

आईएसआई का अड्डा है। हमें इस बात का अफसोस है। उस जमाने में श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थें, उन्होंने साफ इन्कार कर दिया ...(व्यवधान)

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): उस समय वह कहां मुख्यमंत्री थे?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF P. J. KURIAN): Mr. Pany...(*Interruptions*)... Please do not interrupt. (*Interruptions*)

श्री मोतिउर रहमान: उन्होंने साफ इन्कार कर दिया कि इस देश में कहीं पर भी मदरसों में आईएसआई का अड्डा नहीं है। मैं इस बात को चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इस देश, इस देश के प्रति आपसे भी ज्यादा ईमानदार और वफादार कोई है तो वह माइनॉरिटी है। आपने हर मौके पर मेरा इम्तिहान लिया है, लेकिन जब भी आपने मेरा इम्तिहान लिया है, मैंने उसे पास किया है और आपके पास यही एक पूंजी है। आपके पास न तो कोई कार्यक्रम है, न कोई सिद्धांत है और न ही कोई उसूल है। न उसूल हैं। आपके पास एक कार्यक्रम है कि जब भी मॉयनोरिटी का नाम आएगा। आप उसका किसी न किसी जरिए से विरोध करेंगे। अभी दाउद इब्राहिम का नाम आपने लिया। दाउद इब्राहिम की वजह से इस मुल्क में कितने आदमियों की हत्याएं हुई हैं। नरेन्द्र मोदी की वजह से गुजरात में दंगे हुए, कितनी मौतें हुई हैं वहां। और बाल ठाकरे की वजह से महाराष्ट्र और हिन्दुस्तान में कितनी हत्याए और दंगे हुए। इस बात की समीक्षा होनी चाहिए। ...(व्यवधान)... इस मुल्क में आतंकवाद किसकी वजह से बढ़ा है। और कौन आतंकवादी हैं।

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, हम इसका...(व्यवधान)...

THE VICE- CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Please sit down (*Interruptions*) आप लोग बैठिए, बैठिए। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, इन लोगों को सच्चाई सुनने की हिम्मत करनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIAN) Mr. Rahman, I will not.....(*Interruptions*). Please, sit down (*Interruptions*). That is all (*Interruptions*).

आप लोग बैठिए। ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, he is being interrupted while speaking. (*interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIAN): There is no more time (*Interruptions*). You have seven minutes. (*Interruptions*).

आप इस बिल के बारे में बात करें।...(व्यवधान)...

श्री मोतिउर रहमान: मैं बिल के बारे में बात करूं और वे दाउद इब्राहिम के बारे में बात करें। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Please proceed. (*Interruptions*). Mr. Pany, don't do this. (*Interruptions*). You have to show some discipline. (*Interruptions*). I will handle. (*Interruptions*)

श्री मोतिउर रहमान: क्या इनके अंदर कोई ईमानदारी नाम की चीज है।...(**व्यवधान**) अगर इनमें ईमानदारी आ जाए तो इस मुल्क का कायाकल्प हो जाएगा। ...(**व्यवधान**) देखिए, आपके 7 मिनट थे, 5 मिनट हो गए हैं....(**व्यवधान**)

श्री मोतिउर रहमान: इन लोगों ने शिक्षा का भगवाकरण करने का काम किया था। डा॰ मनमोहन सिंह जी, अर्जुन सिंह जी और अली अशरूफ फातमी जी ने मेहनत से इस भगवाकरण को जितना खत्म करने का काम किया, जिस सेक्युलरिज्म को इस देश में संविधान के मुताबिक काम करने का मौका मिला, ऐसे मौके पर यह बिल लाकर के, मैं जानता हूं तीन-तीन वर्षों से नो ऑब्जेक्शान के लिए पड़ा हुआ है, इनके मिजाज के लोग अक्सर बैठे हुए हैं देश के कोने-कोने में, वे नहीं चलने देते हैं, हार मानकर मजबूरी में इस बिल को लाना पड़ा। ...(**व्यवधान**)

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात): इतने साल कांग्रेस का शासन रहा ...(**व्यवधान**)

श्री मोतिउर रहमान: मॉयनोरिटीज़ के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अगर बिल लाए हैं तो इसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए, यू॰पी॰ए॰ गवर्नमेंट की, वह कम है। मैं पूरे देश के मुसलमानों की तरफ से मॉयनोरिटी की तरफ से मुबारकबाद देता हूं, लेकिन हिम्मत आपने की इन लोगों के विरोध के बाद भी। मैं रवि शंकर प्रसाद जी के बारे में अच्छी ऑपिनियन रखता था, लेकिन इनके भी खून में वही चीज है जो डा॰ जोशी के खून में है। ऐसे हालात में अगर इस मुल्क में जिस प्रकार से इस बिल को लाकर के अकलियतों के मान-सम्मान और शिक्षा-दीक्षा के बारे में सोचा जा रहा है, यह बहुत अच्छी बात है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है।

उपसभाध्यक्ष (**प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन**): प्लीज़ कंक्लूड कीजिए। Please, try to conclude it now.

श्री मोतिउर रहमान: अभी तो मुझको पांच मिनट बोलना है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में इन लोगों ने जिक्र कर दिया। मैं समझता हूं कि इनके दिमाग का जो फितूर है, ऐसे ही मौके पर हम लोगों को समझने का मौका मिलता है।

इस बिल की जो मुखालफत करते हैं, वैसे लोगों की बात माननीय मंत्री जी को नहीं माननी चाहिए। बेखौफ और हिम्मत के साथ मैं कहता हूं कि

''मुझको मिटा सके, यह जमाने में दम नहीं
हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं।''

4.00 P.M.

इसलिए यह लोग गलतफहमी में हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी है, इस देश के प्रति सबसे वफादार कोई कौम है, तो हम किसी से भी पीछे नहीं हैं, हम हर मोड़ पर इस मुल्क के लिए एक-एक कतरा खून का देने के लिए तैयार रहते हैं। उस पर अंगुली उठाकर के इस मुल्क को कमजोर करने का काम, अगर किसी ने आज तक किया है, तो यह भाजपा और आरएसएस के लोग हैं। ...(व्यवधान)... इनके द्वारा संचालित स्कूलों में क्या हो रहा है? ...(व्यवधान)... इन्होंने कभी सोचा है।

श्री कृपाल परमार (हिमाचल प्रदेश): बिहार को किसने बर्बाद कर दिया? ...(व्यवधान)...

श्री मोतिउर रहमान: इनके स्कूल में क्या हो रहा है? ...(व्यवधान)... आर एस एस के स्कूल जहां-जहां खुले हैं, वहां पर फिरकापरस्ती की बात होती है। ...(व्यवधान)... वहां देश को तोड़ने की बात होती है, लेकिन हमारे यहां माइनॉरिटी स्कूल में हिन्दी की पढ़ाई होती है ...(व्यवधान)... क्या इनके स्कूल में उर्दू की पढ़ाई होती है? ...(व्यवधान)... फिर कैसे ये सेक्युलर हैं? ...(व्यवधान)... हम सेक्युलर हैं। कांग्रेस के लोग, राजद के लोग, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और यूपीए के लोगों ने इस देश को बचाने का संकल्प लिया है।

ऐसे हालात में, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अशरफ फातमी साहब से कहता हूं कि आप आगे बढ़कर चलिए, इस देश की जनता, हिन्दू और मुसलमान, इन चंद फिरकापरस्तों के अलावा, तमाम के तमाम आपके साथ हैं। जय-हिन्द।

DR. RADHAKANT NAYAK (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to you for having given me this opportunity. I believe in some kind of a self-imposed limitation, and, therefore, I just don't want to discuss some procedural matters which perhaps are engaging the attention of the House. I would concentrate on certain substantial issues that concern this Bill, and support it.

Sir, most of the issues that have arisen and discussed by the Opposition relate to Article 30 of the Indian Constitution. Sir, this article has been debated in extenso in the Constituent Assembly debates; and most of the issues, most of the apprehensions that have been raised today also, have been discussed there and, thereafter, the Article has been adopted. This article has also been tested, from time to time, not only by different

political parties, but also by the Judiciary itself, and finally by the people themselves. Therefore, this forms part of the basic structure of the Constitution which now, more or less, is not being agreed to by the Opposition. Sir, the implementation of this Article is a mandate given to all the Governments which are being democratically elected in this country. Sir, therefore, instead of procedures, I would go into the substance of this Article.

Sir, the first thing this Article enjoins on the Government is the protection of minorities. Sir, the phenomenon of minorities is not limited to this country alone. One of the Members of the Opposition has said that in no other Constitution, in no other country such a protective provision is found. It is not correct.

A reference was made to Canada for example, Sir, Canada is like us, a multi-ethnic country and there the Catholics are considered in some parts of the French-Quebec as minorities. In many other countries, such kind of situation exists and the law also exists for the protection of the minorities. I would not take long to discuss the various naunces of this Article, nor other provisions in the Constition. But I would read it out to you as a reminder to this august House an extract from, one of the most important landmark judgements of the Supreme Court *viz* the T.M.A. Pai Foundation *Vs.* the State of Karnataka. Now, Sir, I will read out to you the judgement. I will take only 3-4 minutes. I quote, "Our country is often depicted as a person in the form of 'Bharat Mata, Mother India'. The people of India are regarded as her children with their welfare being in her heart. Like any loving mother, the welfare of the family is of paramount importance for her. For a healthy family, it is important that each member is strong and healthy." Unquote Sir, this is an eleven-member judgement of the Supreme Court which, quote. Then, "But then, all members do not have the same constition, whether physical and/or mental. For harmonious and healthy growth, it is but natural for the parents, and the mother in particular, to give more attention and food to the weaker child so as to help him/her become stronger. Giving extra food and attention and ensuring private tution to help in his/her studies will, in a sense, amount to giving the weaker child preferential treatment." Un quote Somebody said of reverse discrimination, which it is not. It is a positive treatment; it's a preferential treatment. I quote again, "Just as lending physical support to the aged and the infirm, or providing a special diet, cannot be regarded as

unfair or unjust, similarly, conferring certain rights on a special class, for good reasons, cannot be considered inequitable. All the people of India are not alike, and that is why preferential treatment to a special section of the society is not frowned upon. Article 30 is a special right conferred on the religious and linguistic minorities because of their numerical handicap and to instil in them a sense of security and confidence, even through the minorities cannot be *per se* regarded as weaker sections or underprivileged segments of the society," Sir, I will continue, to quote" The one billion population of India consists of six main ethnic groups and fifty two major tribes; six major religions and 6,400 castes and sub-castes; eighteen major languages and 1,600 minor languages and dialects. The essence of secularism in India can best be depicted if a relief map of India is made in mosaic, where the aforesaid one billion people are the small pieces of marble that go into the making of a map. Each person, whatever his/her language, caste, religion has his/her individual identity, which has to be preserved, so that when pieced together it goes to form a depiction with the different geographical features of India. These small pieces of marble, in the form of human beings, which may individually be dissimilar to each other, when placed together in a systematic manner, produce the beautiful map of India. Each piece, like a citizen of India, plays an important part in making of the whole. The variations of the colours as well as different shades of the same colour in a map is the result of these small pieces of different shades and colours of marble, but even when one small piece of marble is removed, the whole map of India would be scattered, and the beauty would be lost. Each of the people of India has an important place in the formation of the nation. Each piece has to retain its own colour. By itself, it may be an insignificant stone, but when placed in a proper manner, goes into the making of a full picture of India, in all its different colours and hues.

A citizen of India stands in a similar position. The Constitution recognizes the differences among the people of India, but it gives equal importance to each of them, their differences notwithstanding, for only then can there be a unified secular nation. Recognizing the need for the preservation and retention of different pieces that go into the making of a whole nation, the constitution, while maintaining, *inter alia*, the basic principle of equality, contains adequate provisions that ensure the preservation of these different pieces. "Unquote Sir, it is a very potetic judgement.

I quote "The essence of secularism in India is the recognition and preservation of the different types of people, with diverse languages and different beliefs, and placing them together so as to form a whole and united India. Articles 29 and 30 do not seek more than to preserve the diffences that exist, and at the same time, unite the people to form one strong nation." unquote

Sir, with this kind of philosophy on which the Indian Constitution is based, I do not think we should get lost in small procedural, miniscule matters. We cannot measure the ocean in terms of a coffee spoon or in terms of a short meter. Therefore, Sir, I will conclude, without taking much of the time of the House, with what the former Chief Justice of India, Justice S.M. Sikri, said. I quote. "In fact, one may well compare our nation to a big Jumbo jet flying through turbulent weather to a golden destination. For this fight, every section of the people must be galvanized together as firmly as the various parts of the frame. The strength of the frame is equal only to the strength of the weakest section of the frame. One little crack, *i.e.* a disgruntled minority, would force the jet to the ground till the crack is repaired." Unquote, therefore, Sir, we cannot afford to dilute the provisions of the law, the provisions of the Constitution in terms of procedure. Thank you.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. Sir, I remember that we had a long debate in the month of December 2004 before passing the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004, and now the National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill, 2005, has been brought forward by the Government. And I still remember that I had also participated in the debate, and I expressed so many apprehensions and sought so many clarifications regarding the implementation of this Bill. Now, after one year of passing the Bill, the Government has again come forward with an Ordinance, and subsequent to the Ordinance, this Bill has been brought in before the House. First of all, I would like to know from the Government as to what has been the experience during the last 12 or 13 months as far as the implementation of the National Commission for Minority Educational institutions Act 2004 is concerned. How many minority institutions have been affiliated to a particular university, and what experience has been gathered by the Government during the last 12 months of the implementation of the National

Commission for Minority Educational Institutions Act? How many minorities have been notified by the Central Government or how many communities have been notified by the Central Government as minority communities? What is the criterion which has been adopted by the Government in determining a particular community as a minority community? I would like to seek these clarifications from the Government.

Coming to the second point, the intention of the Government, I think, is lacking *bonafides*.

As regards the spirit of the Bill, we are definitely supporting the Bill because it is a social obligation on the part of the majority to protect the welfare and interests of the minority communities in our country. That is why the framers of the Indian Constitution have given a lot of thrust to the protection of the minority interests in various parts of the Constitution, especially, in the Fundamental Rights. Their educational, social and cultural rights are well protected in our Constitution. It is absolutely a social obligation on the part of the country to see that the interests of the minority communities are well protected in our country and that their welfare is taken care of. But in this case, we are supporting the intention of the Government in this Bill, in the sense, one way or the other, it is supporting the cause of the minorities as they are educationally backward because of historical and social reasons. They are deprived of better education; they are deprived of so many other facilities during the past decades. So, they should be given more privileges.

But, as far as the original Act is concerned, it was brought forward in the year 2004 by way of an Ordinance. Subsequently, this House passed the Bill. This time also an Ordinance was promulgated on 23rd January, 2006. The Parliament was to be convened or summoned on 16th February. I can't understand the necessity or the urgency for promulgating an Ordinance and then coming to the House for ratification. Unnecessary haste is shown in order to appease some sections of the society to show that they are the champions in protecting the interests of the minorities. We are fully supporting the minority interests. No doubt about it. But why is this Ordinance route? The original Bill and this Amendment Bill were brought before the House through an Ordinance. This could have been well avoided. They should have come with a clean hand and said, "We have to protect the interests of the minority communities". The authority which is being vested, as the per the original Act, in the National

Commission for Minority Educational Institutions is not sufficient for protecting the interest of the minority communities. Therefore, an amendment to the original Act is sought. Empowering the National Commission for Minority Education Institutions is the need of the hour. That has to be done. But it should have been brought to this House by way of a legislation, or, a Bill. That is my second point.

Coming to the third point, which has been raised by many other hon. Members, it relates to the definitions in the Bill. This Bill is for providing adequate educational facilities, especially in higher education, to the minority communities. But still it is vague on who or which is a minority community. I am not going into the details of the judgement of the Supreme Court. In the *T.M.A. Pai, case* also it is a well-established position that the minority status has to be determined by the particular unit of the particular State. That is the well-settled position now. According to this Bill, it is very specific. The Central Government will determine who is a minority. That is why the federal structure or the federal character of the constitution should be considered. The point is whether it is being kept in mind or whether it is being respected.

Coming to the definition in section 2(b) of the Act, "college" means a college or a teaching institution other than a university established or maintained by a person or group of persons from amongst a minority community. Suppose "A" or a particular person belonging to a minority community, as notified by the Central Government, starts an educational institution or an engineering college and provides all the seats to the students belonging to other communities on capitation fees or on some other things, that would also, according to the definition in section 2(b), come under the purview of the minority educational institution or minority college. This is the precaution which we are asking for.Commercialisation of education by misusing the term "minority" should never be allowed. I would like to know whether the Government has taken any precautionary measure to see that education is not being commercialised or educational institutions are not being misused by using the minority status. What is the precaution? What is the safeguard? What measures has the Government taken? What is its experience during the last 12 months? According to our experience, which Mr. Vijayaraghavan has well explained in this House, in most of the cases it is being misused. So, what care and caution have to be taken, is not explained in this Bill.

This is not only in respect of definition of 'college', but also in respect of 'minority'. According to clause 2(f), minority for the purpose of this Act means a community notified as such by the Central Government. Then what is the role of the State Government? What is the verdict of the Supreme Court? I would like to know whether any consultation with the State Government has been done so as to determine whether a particular community is a minority community or not. I would like to know whether any such consultation or discussion has taken place. You are sitting in Delhi and determining and deciding that this community is a minority community. What is the criterion? What are the norms which are to be followed? Is there any idea about it? Sir, in the last discussion on this subject, I raised the same point. According to clause 2(g), minority educational institution means a college or an institution other than a university established or maintained by a person or group of persons from among the minorities. Why am I again emphasising on this point? Now we are empowering the National Commission. We are giving it more authority. Suppose, a particular State Government, as per the State Education Policy, is not giving N.O.C. only because of the reason that this is misuse of the minority status. Now the appellate authoity is the National Commission. The aggrieved party will appeal to the appellate authority. Who is the appellate authority? Now the appropriate authority's decision can be challenged before the appellate authority. The appellate authority is the National Commission. When there is a dispute between the university and a particular individual, when there is a dispute between the appropriate authority and an individual or a minority community, as defined in the statute, then the dispute will be resolved by the National Commission. That means the decision of the National Commission—I am not going into the provisions because of paucity of time--will be just like that of a civil decree. Against that decree, appeal can be made only to the High Court or the Supreme Court. That means you are bypassing the federal characters of our Constitution. What is the role of the State Government? We have amended article 15 of the Constitution. We have incorporated clause 5 into article 15. We are giving an enabling provision to the State Government. We are giving an enabling provision to the State Government to determine it. We are giving an enabling provision so that the interest of the socially and educationally backward people, SCs and STs and the minority communities can be protected by reserving seats for them. That is an enabling provision in the form of

article 15 (5) of the Constitution. This is something else. The State's education policy is not being given much respect. Therefore, this matter should be considered. Sir, this Bill is intended for the protection of educational interests of minorities. We support this Bill.As Shri Vijayaraghavan submitted, we are having so many suggestions in regard to this Bill. Any misuse by taking advantage of the position of minority status has to be dealt with very seriously for which provisions, amendments and other rules have to be framed, so that the real minority people are given adequate relief and better education. Such amendments and proposals have to be taken into account. I hope the Government will come forward with those amendments and proposals. With this hope and expectation that the Government will look further, I support this Bill. Thank you.

SHRIMATI SYEDA ANWARA TAIMUR (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill, 2005. I support this Bill. At the same time, I congratulate the Prime Minister for taking some concrete steps for the advancement of educational, social and economic conditions of minorities. The National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill also seeks to plug loopholes, which hindered the functioning of the Commission since its inception in 2004. It proposes to relax the provision, which restricted minority institutions seek affiliation to any of the six listed scheduled universities, that is, Delhi University, North-Eastern Hill University, Pondicherry University, Assam University, Nagaland University and Mizoram University. This Bill has broadened its scope. Now the Bill allows these minority institutions to seek affiliation to any university of their choice subject to its rules. By another provision, if a no-objection certificate (NOC) is not granted within a period of 60 days or where a decision in this regard is not communicated within such period, the applicant can go ahead and start an institution. It is a very good step because some of these institutions do not grant the NOC.

During the last Session of Parliament, both the Houses of Parliament passed the Constitution (Ninety-Third) Amendment Bill, 2005. According to this Amendment, "The State can, by law, make special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in so far as

such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30." Because of the Constitutional Amendment, the State Legislatures are now competent to make reservations for the weaker sections for admission in aided or unaided educational institutions falling in each State's domain except those declared by the relevant authorities in each State as minority educational institutions. It has, therefore, become necessary that eligible minority educational institutions in each State enjoy the exemption under article 15 (5) while ineligible institutions do not do so. I would like to say that it would depend on the States as to how they implement it.

Sir, I support some of the points raised by Shri Vijayaraghavan and Shri Azmi because we must see to it that the interests of the poorer students are taken into consideration. As Azmiji says, the poorer sections are always neglected and they do not get the benefit. It is only the privileged people who get the advantage. So, we must see to it that the Bill is implemented effectively in the States. I would like to ask the Minister as to how it is that even after passing legislation, it is not implemented in the States. Now, with the present Amendment, more minority educational institutions can seek affiliation, and it has made the Commission more effective and pro-active in protecting the educational rights of minorities in the matter of either granting affiliation to universities seeking a No Objection Certificate for setting up minority institutions, or for obtaining a minority status, without any harassment.

Some hon. Members were asking why we needed to bring this Bill again when we are a secular State. I think that through this Bill, we will be able to strengthen the secular character of our country. We have seen what happened in Gujarat. The minorities were massacred there. The whole world was looking at India and wondering how such a thing could happen in a secular country. Arjun Singhji has brought this Bill and I congratulate, the Prime Minister of India and I congratulate Arjun Singhji for bringing this Bill for taking concrete steps for giving protection to the minorities. That, I think, will send a signal to the whole world that India is a secular state. Otherwise, it will remain in letter only. It is in the Constitution. But it has to be implemented. We have all been of the same opinion that minorities are educationally, economically and socially backward in India.

With these words, I support the Bill.

SHRI RAM JETHMALANI (Maharashtra): Sir, I will not abuse your kind indulgence. I wish to point out that there is something terribly wrong with this amendment Bill. History seems to be repeating itself. I mentioned the other day in my speech on the Motion of Thanks that, in 1980, I had pointed out to the august House—I am sorry I was, at that time, in the Lok Sabha—that something was wrong with this Bill and that this Bill required to be properly amended and properly changed. Nobody listened and, ultimately, we have got into trouble with the Allahabad High Court; the Bill has been declared *ultra vires*. The same thing is happening here.

Now, first of all, your major error is in the Statement of Objects and Reasons itself. "The salient features of the Bill are as follows:- " —this is what you say on page 6—" (i) it provides for the right to establish a minority educational institution...". Now, Sir, the right to establish a minority educational institution is created by article 30 of the Constitution. Article 30 of the Constitution is totally unconditional; it is not subject to any law made by Parliament; it cannot even be regulated by a law made by Parliament. Secondly, the right extends to all religious and linguistic minorites. You cannot restrict it by saying that minorities shall be those which shall be notified by any particular Government. I mean, you are very long on honourable intentions, which I accept, but you are very short on how to translate those intentions into a valid law. So, why should you make the unqualified right granted by the Constitution dependent upon some authority issuing a No Objection Certificate? Who is this authority? No authority can be created for the purpose of obstructing the exercise of that right. Nor can this right be denied to other minorities who are minorities in fact. Therefore, I would request you, for God's sake, if you want to carry out your honourable intentions—for which you deserve a compliment and gratitude—please take better legal advice and frame this law properly and carry out your wishes.

Now, the main problem that the most prolific minority, the Muslim minority, is facing, is about the Aligarh Muslim University and I have been requesting that you should extend to them two assurances—that you will fight the litigation in the Supreme Court and, if the Supreme Court commits the same mistake as the Allahabad High Court has done, you will produce

necessary, effective legislation to restore the character of the university as the minority institution. You have not done it. But, on the contrary, you seem to be perpetuating that by this Bill. If you say in this Bill that a minority institution is that which is certified by a No Objection Certificate, then, that university certainly is not an institution which has been set up after securing a No Objection Certificate. You have to make a provision that notwithstanding any judgement of any court, notwithstanding the fact that the final incorporation is done by an Act of Parliament, in substance, this is an institution which was originally set up by the Muslims of this country with the laudable object of spreading the gospel of Indianness and the message of science and scientific knowledge, which was the vision of Sir Syed Ahmed. Unless you do that, you are not going to remedy the greatest injustice, which has been done as a result of your bad drafting and as a result of an incorrect judgement of the Allahabad High Court. If you want to do good to the minorities, and in this case, I am speaking on behalf of the Muslim minority, please do the right thing, and produce, in this Bill, at least, a provision that that University, notwithstanding the Allahabad High Court judgement, is a minority institution under article 30 of the Constitution. I repeat, and I warn today, that your Bill will ultimately be set aside as *ultra vires* by either some High Court or by the Supreme Court.

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, माननीय श्री राम जेठमलानी जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में जो बात कही है, मैं उससे सहमत हूं।

श्री तरलोचन सिंह (हरियाणा): धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष जी। हम पिछले चार घंटे से इस बिल के बारे में यह बहस सुन रहे हैं। इसमें ऑनरेबल मैम्बर साहेबान ने बहुत अच्छे- अच्छे आइडियाज़ दिए हैं। मैं यह समझता हूं कि यह जो बिल लाया गया है, इसका एक उद्देश्य यह है कि माइनॉरिटीज़ को कैसे एजुकेट किया जाए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी ने यह बात नहीं बताई कि इस कमीशन को बने हुए एक साल हो गया, क्या इस कमीशन के आने के बाद माइनॉरिटी ने पांच स्कूल भी खोले हैं? एक साल में कितने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को स्टेट्स दिया है? कितने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को उनकी च्वायस के मुताबिक यूनिवर्सिटी एफिलिएशन मिली है? अगर एक साल में यह नहीं कर पाए, तो हम यह सोचें कि क्या इस अमेंडमेंट बिल के बाद माइनॉरिटी का काम होने वाला है?

सवाल यह है कि माइनॉरिटीज़ को एजुकेट करना है। अगर यह हाऊस इस सारे बिल को as it is यूनैनिमसली पास कर दे, तो मैं इस हाऊस में यह कहने वाला हूं कि पांच साल भी लग

जाएं, तो इस उद्देश्य का एक परसेंट भी एचीव नहीं होगा, क्यों? सवाल यह है कि एजुकेशन देना सरकार का काम है। कंस्टीट्यूशन में लिखा है कि हिन्दुस्तान के सारे लोगों को एजुकेशन देनी है। क्या यह बिल आने के बाद वह ताकत बढ़ाने जा रहे हैं? इश्यू क्या है? इश्यू यह है कि माइनॉरिटी वाले किसी की गलती से पीछे रह गए, वह छोड़ो। उनको देने के लिए ऐसा बिल लाओ, कहो कि आज हम एक हजार करोड़ रुपया रखते हैं, जो स्कूलों को दिया जाएगा, जहां माइनॉरिटी के बच्चों को इन्सेंटिव मिलेगा, ताकि चाइल्ड लेबर न हो, ताकि ड्रॉप आऊट न हो। इस तरह जो बच्चा स्कूल जाएगा, उसके पैरेंट को दो सौ या तीन सौ रुपया मिलेगा। तो वह है-incentive to minorities. अब इसमें यह बिल बैठा है। इस बिल में क्या है? 90 परसेंट जरूरत है, स्कूलों की। सारा बिल जाता है, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। आप बताइये, यहां हैल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हैं। आज मैं कोई मेडिकल कॉलेज खोलने की दरख्वास्त देता हूं, तो क्या 60 डेज़ में इंडिया की कोई मेडिकल काउन्सिल या हैल्थ डिपार्टमेंट इसकी इजाजत दे देगी? आप कह रहे है कि अगर किसी को 60 दिनों में 'No Objection' नहीं मिलता, तो वे ऑटोमैटिकली खुद ही खोल सकते हैं। जरा बताइए कि कौन-सी स्टेट गवर्नमेंट या कौन-सा डिपार्टमेंट किसी स्कूल को 60 डेज़ में इजाजत देता है? So, we are trying to create a clash between the minorities and the State Government. उसके बाद आप कहते हैं-यूनिवर्सिटीज़। इंडिया में आज एक सौ के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को यूनिवर्सिटी की च्वायस दे दो। क्यों दे दो? इसमें माइनॉरिटी को क्या फायदा है? First of all, मैं पंजाब में हूं और मैं अपनी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कहूं कि मुझे वह यूनिवर्सिटी पसन्द नहीं है। माइनॉरिटी वाले अपनी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कहें कि मुझे तो यहां से चेन्नई में जाना है। क्यों जाना है? क्या अपनी यूनिवर्सिटी में विश्वास नहीं है? You are unnecessarily creating a clash between the minorities and the university. फिर यूनिवर्सिटी का भी एक्ट है। यूनिवर्सिटी एक्ट में यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी है। मुझे याद है कि पिछली बार एजुकेशन मिनिस्टर, जो पिछली सरकार के थे, उन्होंने फीस के बारे में कुछ बात की थी, तो सारा इंडिया खड़ा हो गया, ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी की बात करने लग गया। अब इस एक्ट में यह प्रोविज़न है कि अगर यूनिवर्सिटी किसी माइनॉरिटी वाले को एफिलिएशन नहीं देती, तो यह कमीशन का आर्डर यूनिवर्सिटी में भी लागू होगा it means कि यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी भी खत्म होगी। पहले स्टेट की ऑटोनॉमी खत्म हो, जैसा ऑनरेबल मैम्बर ने कहा है, फिर यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी खत्म हो और माइनॉरिटी को क्या मिला?

भाइयो, बात बड़ी क्लियर है कि क्रिश्चियन भी एक माइनॉरिटी है। मैंने पिछले छः साल माइनॉरिटी कमीशन में काम किया है। एक भी दरख्वास्त नहीं आई कि इंडिया में कहीं क्रिश्चन स्कूल्स को एफिलिएशन न मिली हो या स्टेटस न मिला हो। आज देश की 19 परसेंट एजुकेशन

क्रिश्चियन कम्युनिटी देती है। उनको कोई शिकायत नहीं है, सिखों को कोई शिकायत नहीं हैं। जब हमारे लोग अपने कॉलेज चेन्नई में, मुम्बई में, कोलकाता में लोगों के लिए खोलते हैं, तो मुसलमान भाइयों के लिए जो इतने बड़े लैक्चर हुए, इसमें सोचना चाहिए कि आपका इश्यू क्या है और यह बिल क्या करेगा। हम तो मांगते हैं, रोटी और केक की बात होती है। आप इसमें यह देखें कि इस बिल से क्या मिलने वाला है? सरकार इस पर बड़ी क्लीयर होकर सोचे और माइनोरिटी को क्लेश में न डलवाए। इस बिल से क्लेश बढ़ेगा और हर रोज शिकायतें आएंगी। जैसी जेठमलानी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, आप उसको रोको। माइनोरिटी के लिए अगर करना है, तो एक ऐसा बिल लेकर आएं, सारे हिंदुस्तान की माइनोरिटीज के लिए एक ऐसा crash प्रोग्राम बनाएं, हजारों करोड़ रुपया उसके लिए रखें और खासतौर से नॉर्थ इंडिया के लिए, क्योंकि साऊथ में तो केरल में, कर्नाटक में बहुत बड़े बड़े मुसलमानों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स हैं। जो यह भावना है कि हम इस बिल से उनको आगे बढ़ाएंगे, मेरे ख्याल से यह एक गलत रास्ते आप जा रहे हैं। सारा हाऊस यूनेनिमस इस बात पर वचनबद्ध हो कि हम माइनोरिटी को पूरी तौर पर एजुकेट करें और उसके लिए सही रास्ता निकालें। यह बिल पास करने से तो हम बिना मतलब क्लेश बढ़ाएंगे और क्लेश बढ़ने से फायदा भी नहीं होगा।

वाइस चेयरमैन साहब, मैं बहुत लंबा नहीं कहना चाहता, क्योंकि आपने कहा था कि मुझे चार मिनट बोलना है। आखिरी बात, मैं यह कहता हूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले नेशनल माइनोरिटी कमीशन बना रखा है, इसको सरकार अब कंस्टीट्यूशनल स्टेटस देने जा रही है, क्या वह कमीशन यह काम नहीं कर सकता? सरकार ने आज तक यह फिगर नहीं दी कि कितनी पेंडिंग एप्लीकेशन माइनोरिटीज की पड़ी हैं, जिनको राज्यों ने रोक रखा है? सरकार ने यह फिगर भी नहीं दी कि कितने माइनोरिटी कमीशन के पास एप्लीकेशन स्टेटस के लिए पेंडिंग हैं? जब आपके पास वह फिगर ही नहीं है, तो आप बिल बिना मतलब के बना रहे हैं। This work could have been done by the Minority Commission without burdening the exchequer and without this slogan कि हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। मैं इसी बात के साथ हाऊस से अपील करता हूं कि Let us resolve कि माइनोरिटी के लिए क्या करना है और वह सही तौर पर करे। जस्ट ऐसे बिलों से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। शुक्रिया, सर।

श्री अबू आसिम आज़मी: वाइस चेयरमैन साहब, मैं आभारी हूं, जो आपने मुझे "द नेशनल कमीशन फोर माइनोरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (अमेंडमेंट) बिल, 2005" की डिबेट में हिस्सा लेने के लिए परमीशन दी। मुझे हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि वह कौम, जिसने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए आज हम एजुकेशन के लिए भीख मांगने के लिए खड़े हुए हैं। कहते हैं:—

जिन्होंने जान देकर मेकदे की आबरू रख दी।
वही अब कतरे कतरे के लिए तरसाए जाते हैं।

सर, कांग्रेस सरकार ने आजादी के 58 सालों में मुसलमानों के लिए कोई ठोस काम तो किया नहीं, अलबत्ता मुख्तलिफ कमेटियां, कमीशन बनाएं। इस तरह महज मुसलमानों को रिझाने की कोशिशें कीं और उनके हाथों में खोखले कानून और कमीशन के खिलौने थमा दिए। अब यह जो कमीशन कानून के तहत बनाया जा रहा है, इससे मुसलमानों के ठोस मसायल का हल तो होगा नहीं, अलबत्ता सरकार यह राग अलापेगी कि इसने मुसलमानों और अकलियतों के लिए बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। आपने पचास सालों में बहुत कुछ किया है। पचास सालों में 30-35 आपने फसादात किए हैं, पचास सालों में मुसलमानों को भिखमंगा बना दिया है और क्या दिया है आपने पचास सालों में? ...(व्यवधान)

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश): आप भिखमंगे हैं क्या? अपने आपको आप भिखमंगा क्यों कह रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री अबू आसिम आज़मी: क्या ...(व्यवधान)... अरे, आप इतना परेशान क्यों है? मुझे बोलने दीजिए, मुझे थोड़ा समय मिला है।

श्री राजीव शुक्ल: आप भिखमंगा क्यों कह रहे हैं अपने आपको?

श्री अबू आसिम आज़मी: सिर्फ कमेटियां बनाना, कमीशन बनाना, बनाकर दे देना और मुसलमानों को बोलेंगे कि यह झुनझुना लेकर फिरते रहो। अगर आपकी नीयत सही होती, तो 1981 में पार्लियामेंट में जो बिल पास किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनोरिटी स्टेटस है, वह बिल जो आपने पास किया था ...(व्यवधान)... जुडिशियरी बड़ी नहीं होती, पार्लियामेंट बड़ी होती है। पार्लियामेंट ने कानून बनाया था। ...(व्यवधान)... जरा सुन लो। कलेजा क्यों फट रहा है सच्चाई सुनने में? ...(व्यवधान)

(श्री उपसभापति महोदय पीठासीन हुए)

श्री राजीव शुक्ल: हमने राष्ट्रपति दिया है, आप मुख्यमंत्री बना दें उत्तरप्रदेश में मुसलमान को। ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: शुक्ल जी, आप उन्हें बोलने दो। ...(व्यवधान)... आज़मी जी, आप बिल पर बोलिए।

श्री राजीव शुक्ल: उत्तर प्रदेश में आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: आज़मी जी को बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)... डा॰ फागुनी राम जी आप

क्यों बीच में खड़े हो रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री अमर सिंह: राष्ट्रपति इन्होंने नहीं बनाया है, हम लोगों ने भी मत दिया था। ...(व्यवधान)

श्री राजीव शुक्ल: एक नहीं, लंबी फेहरिस्त है हमारे पास। ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: देखिए, राजीव जी, बिल फिनिश करना है। ...(व्यवधान)

श्री अमर सिंह: कलाम साहब का विरोध किया था कांग्रेस पार्टी ने। अनावश्यक श्रेय ले रहे हैं आप। ...(व्यवधान)... कलाम साहब का विरोध किया था कांग्रेस ने।

श्री उपसभापति: अरे, बैठिए आप लोग। ...(व्यवधान) देखिए, बैठिए। ...(व्यवधान)... बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह: कलाम साहब का विरोध किया था इन्होंने। ...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल: एक कलाम साहब नहीं, जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब ...(व्यवधान)...

श्री अबू आसिम आज़मी: भाई, आपका नम्बर आएगा तो आप कह लेना, अभी मेरा नम्बर है तो मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have to pass this Bill. Aren't you interested that the Bill should be passed? We have to take up some Special Mentions also and he is the last speaker.

श्री अबू आसिम आज़मी: सर, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया।

श्री उपसभापति: आज़मी जी, देखिए आप इस बिल पर बात कीजिए।

श्री अबू आसिम आज़मी: मैं बिल पर ही कह रहा हूं, मैंने कोई दूसरी बात नहीं की है।

श्री उपसभापति: बिल में खामियां क्या हैं, वे बताइए।

श्री अबू आसिम आज़मी: सर, मैं वही कह रहा था। मैं वही कह रहा था कि इस बिल के रूप में एक झुनझुना देकर हमको बहकाओ मत। मैं कह रहा था कि 58 साल हो गए, 58 साल में वह कौम जो आजादी के बाद 28 से 50 फीसदी तक अच्छी अच्छी नज़ीरों में थी, आज डेढ़ परसैंट पर क्यों आ गई? अब यह अगर इनसे कहें तो इनको बुरा लगता है। मैं यह कह रहा था कि आज एक तरफ तो यह बहुत बड़ा एहसान जताएंगे कि हम बिल लाए हैं और दूसरी तरफ बी॰जे॰पी॰ के लोग माइनॉरिटी में अपीज़मेंट का राग अलापना शुरू कर देंगे, लेकिन मुसलमानों को मिलेगा कुछ नहीं। सर, मैं इस बिल के बारे में यह कह रहा था कि अकलियतों के बनाए जाने वाला यह कमीशन महज़

एक सरकारी कमीशन होगा क्योंकि इसके चेयरमैन और दो मैम्बरों का इंतिखाब इलेक्शन या सिलेक्शन के बजाए नामिनेशन से होगा, सैंट्रल गवर्नमेंट ने इस कानून में नामिनेशन की गुंजाइश रखी है। सैक्शन 3(ii) के तहत सैंट्रल गवर्नमेंट कमीशन के चेयरमैन और दो मैम्बरों को नॉमिनेट करेगी, जो जम्हूरी उसूलों के खिलाफ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग भी कमेटी में लाए जाएंगे, वे सरकारी चापलूसी करेंगे और सच्चाई नहीं लाएंगे, इसलिए इसमें इलेक्शन का प्रावधान होना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं।

दूसरा मेरा कहना यह है कि इस कमीशन के ओहदेदारान सिर्फ अकलियती फिरके के इफराद ही रह सकते हैं, ऐसा सैक्शन 4 में बताया गया है, लेकिन अकलियती फिरके के बारे में नज़रीयात में इख्तिलाफात हैं। कांस्टिट्यूशन में अकलियतों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है–रिलीजस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लेकिन, हमें इस नेशनल कमीशन के ओहदे के लिए नेशनल माइनॉरिटी और रीजनल माइनॉरिटी में तफरीक करनी होगी। महाराष्ट्र में अगर एक बंगाली अकलियती फिरके का फरद बन जाता है, पंजाब में एक गुजराती अकलियती फरद बन जाता है और मराठी हाऊस में अकलियती फरद बन जाता है, तो नेशनल लैवल पर किसी पंजाबी, मराठी या गुजराती को अकलियती फरद नहीं कहा जा सकता। लेकिन, एक मुसलमान या एक सिख, एक बुद्धिस्ट या एक ईसाई बतौर मज़हबी अकलियती फरद के नेशनल माइनॉरिटी का हिस्सा है। माइनॉरिटी फिरका नेशनल लैवल पर क्या है, इसकी तज़वीज़ कानून में बराबर नहीं की गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको कमीशन बनाना चाहिए, नहीं तो लोग जाकर हाई कोर्ट में पेटिशन डालकर स्टे ले आएंगे। ...**(समय की घंटी)**... सर, मुझे दो मिनट और बोलने दीजिए। मैं श्री राम जेठमलानी साहब की बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं।

श्री उपसभापति: देखिए, आपकी पार्टी में 11 मिनट थे, 18 मिनट हो गए हैं।

श्री अबू आसिम आज़मी: सर, मेरे को अभी दो-तीन मिनट ही हुए हैं।

श्री अमर सिंह: सर, पांच मिनट तो इन लोगों ने इंटरप्शन में ले लिए हैं।

श्री उपसभापति: मैं वह समय निकालकर बोल रहा हूं।

श्री अबू आसिम आज़मी: सर, एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि 1981 में इसी हाऊस में एक कानून पास हुआ था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी करैक्टर है, लेकिन हाई कोर्ट के एक बैंच ने उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के करैक्टर को, जिसके लिए सर सैयद अहमद खान ने एक-एक गांव में जाकर भीख मांगी थी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसका नाम है, आप ही की

सरकार थी, आपने कानून बनाया, लेकिन वह युनिवर्सिटी आज मुसलमानों की नहीं है। इस तरह से आप * बनाने का काम बंद कीजिए। जैसे राम जेठमलानी जी ने कहा है, आप ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: * वर्ड निकाल दीजिए। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, आप यह वर्ड बहुत यूज़ करते हैं और उसको बार-बार निकाला जाता है।

श्री अबू आसिम आज़मी: सर, मैं नया मैम्बर हूं, भूल जाता हूं।

सर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर वाकई आपकी नीयत सही है, वाकई आप मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, खाली वोट नहीं लेना चाहते, सिर्फ वोट बैंक के लिए कुछ नहीं करना चाहते, तो पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी करैक्टर डिक्लेअर करो।

श्री उपसभापति: ठीक है, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री अबू आसिम आज़मी: इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पहले अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी का माइनॉरिटी करैक्टर डिक्लेअर करो। यह सिर्फ * बनाने का काम बंद करो।

श्री उपसभापति: * वर्ड फिर आप यूज़ कर रहे हैं। इसे निकाल दीजिए।

श्री अबू आसिम आज़मी: सॉरी सर। जब हाऊस में कुछ डिस्कशन होता है तो इस साइड वाले खड़े हो जाते हैं-दाउद इब्राहिम। ये क्या * की बातें हैं।

श्री उपसभापति: आपको दूसरा कोई वर्ड नहीं आता?

श्री अबू आसिम आज़मी: इसमें दाउद इब्राहिम कितना फंड भेज रहा है? आपको दाउद इब्राहिम की बहुत पहचान है क्या कि दाउद इब्राहिम बहुत सारे माइनॉरिटीज़ इंस्टिट्यूशन्स को पैसे भेज रहा है।

श्री उपसभापति: आपकी बात हो गई, अब बैठिए।

श्री अबू आसिम आज़मी: ये सब चीजें करके जो आप मुसलमानों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, वह बंद कीजिए।

श्री उपसभापति: ठीक है।

श्री अबू आसिम आज़मी: मुसलमान इस देश का वफादार नागरिक हैं।

श्री उपसभापति: आप खत्म कीजिए।

श्री अबू आसिम आज़मी: मैं तो खत्म ही कर रहा हूं, सर, आप ही एक-एक मिनट पर मुझे रोकते जा रहे हैं।

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री उपसभापति: आप अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री अबू आसिम आज़मी: सर, मैं तो खत्म ही कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे एक-एक मिनट में रोकते जा रहे हैं।

श्री उपसभापति: आप खत्म कीजिए।

श्री अबू आसिम आज़मी: इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर आज सत्ता में आए हैं तो मुसलमानों की मेहरबानी पर आए हैं, इन्हीं की मरहून-ए-मिन्नत पर आए हैं, इसलिए आप जरा * बनाना बंद कीजिए। आप सचमुच कुछ काम करना शुरू कीजिए। सर, क्या करूं ये लोग यही कर रहे हैं, इसलिए बार-बार इनके लिए यही लफ्ज़ मुंह में आता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो यह बिल आया है, जैसाकि श्री राम जेठमलानी साहब ने अभी कहा कि फिर से इस पर पैटीशन होगा और काम रोका जाएगा, इसलिए आप इस बिल को ज़रा अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि इस मुल्क में वाकई मुसलमानों को उनका हिस्सा मिल सके। आपने मुझे बोलने दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

†شری ابو عاصم اعظمی ''اتر پردیش'' : وائس چیئرمین صاحب، میں آبھاری ہوں، جو آپ نے مجھے ''دا نیشنل کمیشن فور مائنارٹی ایجوکیشنل انسٹی ٹیوشنس (امینڈمنٹ) بل، ۲۰۰۵ کی ڈیبیٹ میں حصہ لینے کے لئے پرمشن دی۔ مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ قوم، جس نے اس ملک کے لئے بہت کچھ کیا، اس کے لئے آج ہم ایجوکیشن کے لئے بھیک مانگنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ۔

جنہوں نے جان دیکر مہ کدے کی آبرو رکھ دی
وہی اب قطرے قطرے کے لئے ترسائے جاتے ہیں

سر، کانگریس سرکار نے آزادی کے ۵۸ سالوں میں مسلمانوں کے لئے کوئی ٹھوس کام تو کیا نہیں، البتہ مختلف کمیٹیاں، کمیشن بنائے۔ اس طرح محض مسلمانوں کو رجھانے کی کوششیں کیں اور ان کے ہاتھوں میں کھوکھلے قانون اور کمیشن کے کھلونے تھمادئے۔ اب یہ جو کمیشن قانون کے تحت بنایا جارہا ہے، اس سے

*Not recorded.
†[ ] Transliteration in Urdu Script.

مسلمانوں کے ٹھوس مسائل کا حل تو ہوگا نہیں، البتہ سرکار یہ راگ الاپے گی کہ اس نے مسلمانوں اور اقلیتوں کے لئے بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ آپ نے پچاس سالوں میں بہت کچھ کیا ہے۔ پچاس سالوں میں ۳۵۔۳۰ آپ نے فسادات کئے ہیں، پچاس سالوں میں مسلمانوں کو بھیک منگا بنا دیا ہے اور کیا دیا ہے آپ نے پچاس سالوں میں؟.....مداخلت.....

شری راجیو شکلا : آپ بھیک منگے ہیں کیا؟ آپنے آپ کو آپ بھیک منگا کیوں کہہ رہے ہیں؟ .....مداخلت.....

شری ابو عاصم اعظمی : کیا؟ .....مداخلت..... ارے آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ مجھے بولنے دیجئے، مجھے تھوڑا وقت ملا ہے۔

شری راجیو شکلا : آپ بھیک منگا کیوں کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو۔

شری ابو عاصم اعظمی : صرف کمیٹیاں بنانا، کمیشن بنانا، بنا کر دے دینا اور مسلمانوں کو بولیں گے کہ یہ جھنجنا لیکر پھرتے رہو۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہوتی، تو ۱۹۸۱ میں پارلیمنٹ میں جو بل پاس کیا تھا علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کو مائنارٹی اسٹیٹس ہے، وہ بل جو آپ نے پاس کیا تھا .....مداخلت...جیوڈیشری بڑی نہیں ہوتی، پارلیمنٹ بڑی ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ نے قانون بنایا تھا .....مداخلت.....ذرا سن لو۔کلیجہ کیوں پھٹ رہا ہے سچائی سننے میں؟ .....مداخلت.....

.....(شری اُپ سبھاپتی پیٹھاسین ہوئے).....

شری راجیو شکلا: ہم نے راشٹرپتی دیا ہے، آپ مکھیہ منتری بنا دیں مسلمان کو.....مداخلت.....

شری اُپ سبھاپتی : شکلا جی، آپ انہیں بولنے دو.....مداخلت..... اعظمی جی، آپ بل پر بولئے۔

شری راجیو شکلا : اتر پردیش میں آپ مکھیہ منتری جی بنا دیجئے .....مداخلت.....

شری اپ سبھاپتی : اعظمی جی کو بولنے دیجئے۔ .....مداخلت..... ڈاکٹر فاگنی رام جی آپ کیوں بیچ میں کھڑے ہو رہے ہیں .....مداخلت.....

شری امر سنگھ : راشٹرپتی انہوں نے نہیں بنایا ہے، ہم لوگوں نے بھی مت دیا تھا .....مداخلت.....

†[ ] Transliteration in Urdu Script.

شری راجیو شکلا : ایک نہیں، لمبی فہرست ہے ہمارے پاس .....مداخلت.....

اُپس سبھاپتی : دیکھئے، راجیو جی، بل فنش کرنا ہے .....مداخلت.....

شری امر سنگھ : کلام صاحب کا ودروھ کیا تھا کانگریس پارٹی نے۔ اَن آوشیک شرے لے رہے ہیں آپ .....مداخلت.... کلام صاحب کا ورودھ کیا تھا کانگریس نے۔

شری اُپ سبھاپتی : ارے، بیٹھئے آپ لوگ...مداخلت....دیکھئے.....مداخلت.....

شری امر سنگھ : کلام صاحب کا ورودھ کیا تھا انہوں .....مداخلت.....

شری راجیو شکلہ :ایک کلام صاحب نہیں، ذاکر حسین صاحب، فخر الدین علی احمد صاحب.....مداخلت.....

شری ابو عاصم اعظمی : بھائی، آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کہہ لینا، ابھی میرا نمبر ہے تو مجھے بولنے دیجئے .....مداخلت.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have to pass this Bill. Aren't you interested that the Bill should be passed? We have to take up some Special Mentions also and he is the last speaker.

†شری ابو عاصم اعظمی : سر، ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا۔

شری اُپ سبھاپتی: اعظمی جی، دیکھئے آپ اس بل پر بات کیجئے۔

شری ابو عاصم اعظمی: میں بل پر ہی بول رہا ہوں، میں نے کوئی دوسری بات نہیں کی ہے۔

شری اُپ سبھاپتی: بل میں خامیاں کیا ہیں وہ بتائیے۔

شری ابو عاصم اعظمی : سر، میں وہی کہہ رہا تھا۔ میں وہی کہہ رہا تھا کہ اس بل روپ میں ایک جھنجھناد یکر ہم کو بہکاؤ مت۔ میں کہہ رہا تھا کہ ۵۸ سال ہو گئے، ۵۸ سال میں وہ قوم جو آزادی کے بعد ۲۸ سے ۵۰ فیصد تک اچھی اچھی نظیروں میں تھی، آج ڈیڑھ پرسینٹ پر کیوں آ گئی؟ اب یہ اگر ان سے کہیں تو ان کو برا لگتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ایک طرف تو یہ بہت بڑا احسان جتائیں گے کے ہم بل لائے ہیں اور دوسری طرف بی جے پی کے لوگ مائنارٹی میں اپیزمنٹ کا راگ الاپنا شروع کر دیں گے۔ لیکن مسلمانوں کو ملیگا کچھ نہیں۔

†[ ] Transliteration in Urdu Script.

سر، میں اس بل کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اقلیتوں کے بنائے جانے والا یہ کمیشن محض ایک سرکاری کمیشن ہوگا کیونکہ اس کے چیئرمین اور دو ممبروں کا انتخاب الیکشن یا سلیکشن کے بجائے نامنیشن سے ہوگا، سینٹرل گورنمنٹ نے اس قانون میں نامنیشن کی گنجائش رکھی ہے۔ سیکشن ۳(۲) کے تحت سینٹرل گورنمنٹ کمیشن کے چیئرمین اور دو ممبروں کو نامنیٹ کریگی، جو جمہوری اصولوں کے خلاف ہے۔ اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی کمیٹی میں لائے جائیں گے، وہ سرکاری چاپلوسی کریں گے اور سچائی نہیں لائیں گے، اس لئے اس میں الیکشن کا پراوٴدھان ہونا چاہئے، ایسا میں کہنا چاہتا ہوں۔

دوسرا میرا کہنا یہ ہے کہ اس کمیشن کے عہدیداران صرف اقلیتی فرقے کے افراد ہی رہ سکتے ہیں، ایسا سیکشن ۴ میں بتایا گیا ہے، لیکن اقلیتی فرقے کے بارے میں نظریات میں اختلافات ہیں۔ کانسٹی ٹیوشن میں اقلیتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ریلیجئس مائنارٹی اور لنگوسٹک مائنارٹی۔ لیکن ہمیں اس نیشنل کمیشن کے عہدے کے لئے نیشنل مائنارٹی اور ریجنل مائنارٹی میں تفریق کرنی ہوگی۔ مہاراشٹر میں اگر ایک بنگالی اقلیتی فرقے کا فرد بن جاتا ہے، پنجاب میں ایک گجراتی اقلیتی فرد بن جاتا ہے اور مراٹھی ہاؤس میں اقلیتی فرد بن جاتا ہے، تو نیشنل لیول پر کسی پنجابی، مراٹھی یا گجراتی کو اقلیتی فرد نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن، ایک مسلمان یا ایک سکھ، ایک بدھشٹ یا ایک عیسائی بطور مذہبی اقلیتی فرد کے نیشنل مائنارٹی کا حصہ ہے۔ مائنارٹی فرقہ نیشنل لیول پر کیا ہے، اس کی تجویز قانون میں برابر نہیں کی گئی ہے۔ اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو کمیشن بنانا چاہئے، نہیں تو لوگ جا کر ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالکر اسٹے لے آئیں گے۔

.....(وقت کی گھنٹی).....

سر، مجھے دو منٹ اور بولنے دیجئے، میں شری رام جیٹھ ملانی جی کی بات کا بالکل سمرتھن کرتا ہوں۔

شری اُپ سبھاپتی: دیکھئے، آپ کی پارٹی کے ۱۱ منٹ تھے، ۱۸ منٹ ہوگئے ہیں۔

شری ابوعاصم اعظمی : سر، میرے کو ابھی دو تین منٹ ہی ہوئے ہیں۔

شری امر سنگھ : سر، پانچ منٹ تو ان لوگوں نے انٹرپشن میں لے لئے ہیں۔

†[ ] Transliteration in Urdu Script.

شری اُپ سبھاپتی: میں وہ وقت نکال کر بول رہا ہوں۔

شری ابوعاصم اعظمی : سر، ایک چیز میں بولنا چاہتا ہوں کہ ۱۹۸۱ میں اسی ہاؤس میں ایک قانون پاس ہوا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مائنارٹی کریکٹر ہے، لیکن ہائی کورٹ کے ایک بنچ نے اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کریکٹر کو، جس کے لئے سرسید احمد خاں نے ایک ایک گاؤں میں جا کر بھیک مانگی تھی۔ مسلم یونیورسٹی اس کا نام ہے، آپ ہی کی سرکار تھی، آپ نے قانون بنایا، لیکن وہ یونیورسٹی آج مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ * بنانے کا کام بند کیجئے۔ جیسے رام جیٹھ ملانی جی نے کہا ہے، آپ.....مداخلت....

شری اُپ سبھاپتی: * لفظ نکال دیجئے۔ دیکھئے، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ یہ الفاظ بہت استعمال کرتے ہیں اور اس کو بار بار نکالا جاتا ہے۔

شری ابوعاصم اعظمی : سر، میں نیا ممبر ہوں، بھول جاتا ہوں۔

سر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی آپ کی نیت صحیح ہے، واقعی آپ مسلمانوں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں، خالی ووٹ نہیں لینا چاہتے، صرف ووٹ بینک کے لئے کچھ نہیں کرنا چاہتے، تو پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مائنارٹی کریکٹر ڈکلیئر کرو۔

شری اُپ سبھاپتی: ٹھیک ہے، آپ کا وقت سماپت ہو گیا ہے۔

شری ابوعاصم اعظمی : اسلئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مائنارٹی کریکٹر ڈکلیئر کرو۔ یہ صرف * بنانے کا کام بند کرو۔

شری اُپ سبھاپتی: * لفظ پھر آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اسے نکال دیجئے۔

شری ابوعاصم اعظمی : سوری سر، جب ہاؤس میں کچھ ڈسکشن ہوتا ہے تو اس سائیڈ والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ داؤد ابراہیم، داؤد ابراہم۔ یہ کیا * کی باتیں ہیں۔

شری اُپ سبھاپتی: آپ کو دوسرا کوئی لفظ نہیں آتا؟

†[ ] Transliteration in Urdu Script.

شری ابو عاصم اعظمی : اس میں داؤد ابراہیم کتنا فنڈ بھیج رہا ہے؟ آپ کو داؤد ابراہیم کی بہت پہچان ہے کیا کہ داؤد ابراہیم بہت سارے مائنارٹی انسٹی ٹیوشن کو پیسے بھیج رہا ہے۔

شری اُپ سبھاپتی: آپ کی بات ہوگئی، اب بیٹھئے۔

شری ابو عاصم اعظمی : یہ سب چیزیں کر کے جو آپ مسلمانوں کو چڑانے کا کام کر رہے ہیں، وہ بند کیجئے۔

شری اُپ سبھاپتی: ٹھیک ہے۔

شری ابو عاصم اعظمی : مسلمانوں اس دیش کا وفادار ناگرک ہے۔

شری اُپ سبھاپتی: آپ ختم کیجئے۔

شری ابو عاصم اعظمی : میں تو ختم ہی کر رہا ہوں، سر، آپ ہی ایک ایک منٹ پر مجھے روکتے جا رہے ہیں۔

شری اُپ سبھاپتی: آپ اپنی بات ختم کیجئے۔

شری ابو عاصم اعظمی : اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر آج ستہ میں آئے ہیں تو مسلمانوں کی مہربانی پر آئے ہیں، انہیں کی مرہون منت پر آئے ہیں، اس لئے آپ ذرا * بنانا بند کیجئے۔ آپ سچ مچ کچھ کام کرنا شروع کیجئے۔ سر، کیا کروں یہ لوگ یہی کر رہے ہیں، اس لئے بار بار ان کے لئے یہی لفظ منہ میں آتا ہے۔ اس لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو یہ بل آیا ہے، جیسا کہ شری رام جیٹھ ملانی صاحب نے ابھی کہا کہ پھر سے اس پر پٹیشن ہوگا اور کام روکا جائے گا، اس لئے آپ اس بل کو ذرا اچھی طرح سے دیکھ لیجئے، تاکہ اس ملک میں واقعی مسلمانوں کو ان کا حصہ مل سکے۔ آپ نے مجھے بولنے دیا، اس کے لئے بہت بہت شکریہ۔

"ختم شد"

†[ ] Transliteration in Urdu Script.

एक माननीय सदस्य: सर,

श्री उपसभापति: अब आप बैठ जाइए, आपने पहले ही बहुत वक्त ले लिया है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: उपसभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि जब सारे सदन में जो कुछ विचार प्रस्तुत किए गए, उनके बारे में आपने मुझे फिर से अपने विचार रखने की इजाजत दी है। मुझे खुशी हुई होती, बीच में अगर सरकारी पक्ष की ओर से मंत्री महोदय ने यह बताया होता कि इस संशोधन को लाने के पीछे सरकार की नीयत क्या है, मंशा क्या है और साथ ही इससे क्या फायदा होने वाला है। जहां तक मैंने इनका स्टेटमेंट पढ़ा है और इसमें इसका एक कारण जो इन्होंने बताया कि क्यों इस संशोधन को लाया गया, वह यह है, "because of the Constitution (Ninety-third Amendment) Bill, 2005, passed by Parliament, it became necessary to determine which are minority institutions as the State has been empowered to stipulate quota for admission in aided or unaided educational institutions, except those declared as minority educational institutions. Since new academic session is likely to commence and admission process is in full swing, it became necessary to promulgate the Ordinance to empower the National Commission for minority educational institutions to decide minority status of institutions." इसका अर्थ यह है कि नई संस्थाओं को खोलने के बारे में और उसमें आने वाली किसी दिक्कत के बारे में, इस बिल का, इस संशोधन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि आज जो संस्थाएं हैं, उनमें से किसे माइनॉरिटी बताया जाए, ताकि उन संस्थाओं के अन्दर बैक्वर्ड और वीकर सैक्शन्स का जो आरक्षण अन्य संस्थाओं में है, उससे उनको वंचित किया जा सके। इसलिए एक हिसाब से जो यह बिल या यह संशोधन लाया गया है, यह पिछड़े, दलित एवं अन्य दुर्बल सैक्शन्स को आरक्षण से वंचित करने के लिए लाया गया है। यह मुसलमान भाइयों या माइनॉरिटीज के फायदे की दृष्टि से नहीं लाया गया है।

उपसभापति महोदय, जब मेरे पास यह मंत्रालय था, मैंने इस प्रश्न पर काफी गहराई से सोचा था। मेरे पास इस प्रश्न का कोई एक भी आवेदन नहीं आया जिसमें कि यह कहा जाए कि हमें एफिलिएशन में कोई दिक्कत हो रही है या माइनॉरिटी स्टेटस में कोई दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत होती थी तो एनओसी में होती थी और उसे हमने तरह-तरह से सुलझाने की कोशिश की और आज भी मैं इस बात को मानता हूं कि एनओसी के सवाल पर गहराई से विचार होना चाहिए, सिर्फ माइनॉरिटी संस्थाओं के लिए ही नहीं बल्कि हर संस्था के बारे में विचार होना चाहिए कि उनको एनओसी आसानी से मिल सके। इस प्रकार एक चीज तो यह है कि इस बिल का जो उद्देश्य इसमें लिखा है, उससे साफ जाहिर है कि यह किसी खास माइनॉरिटी को या विशेषकर मुसलमान भाइयों को फायदा पहुंचाने के हिसाब से नहीं लिखा गया है।

दूसरी बात, अगर मंत्री महोदय बता सकें तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर इस वक्त जो माइनॉरिटी संस्थाएं हैं, उनको कौन-कौन सी माइनॉरिटीज़ चला रही हैं? किसके पास कितनी माइनॉरिटी संस्थाएं हैं? आखिर इस बात का फैसला भी हो कि वहां क्या असुविधा है, इसके लिए तो पहले यह पता लगना चाहिए कि कौन सी माइनॉरिटीज़ कौन-कौन सी संस्थाएं चला रही हैं। फिर सवाल यह भी उठता है कि माइनॉरिटी किसे कहा जाएगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सवाल को हल नहीं किया है और संविधान में भी स्पष्ट रूप से इस बात को नहीं लिखा गया है। कोई भी प्रावधान आपको इस बात का अधिकार नहीं देता है कि आप रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को डिफाइन करें। लिग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ तो पहले से ही डिफाइन्ड हैं। अब इस सेकुलर डेमोक्रेसी में इस रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के सवाल को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है कि माइनॉरिटी करेक्टर को किस तरह से डिटर्मिन करें। आज मुझे आप मैजॉरिटी कहते हैं, लेकिन कल सवेरे अगर मैं चर्च में जाकर बैप्टिज्म ले लूं या मस्जिद में जाकर कलमा शरीफ पढ़ लूं, तब क्या मैं ओवर नाइट माइनॉरिटी हो जाऊंगा? और क्या अगर मुझे अपने स्कूल में यह वंचित कराना है रिजर्वेशन दलितों के लिए, तो सुबह मैं एक रास्ता नहीं खोल सकता कि अपना धर्म बदल लूं और कल कह दूं कि मैं मॉयनोरिटी हूं। आप इन सवालों को किन सतही नजर से देख रहे हैं इस पर विचार करना चाहिए। इस देश में जब मुसलमान भाई यह कहते हैं कि वे मॉयनोरिटी हैं तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने जितना काम किया उसके बाद तमाम मुसलमान भाइयों ने मुझसे आकर यह कहा कि आपने अकलियत के लिए बहुत काम किया। मैंने कहा कि भाईयों, मैं आपको अकलियत नहीं मानता और मैं हाथ जोड़कर यह गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मॉयनारिटिज्म की इस अल्पसंख्यक वाद की मानसिकता से इस देश को मुक्त कराइए, इसको और बढ़ाइए मत। इसको बढ़ाने के बहुत खराब नतीजे होंगे। मैं इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे तमाम कानून, चाहे वे रिजर्वेशन के हों, चाहे वे एजुकेशन के मॉयनोरिटी करेक्टर को लाने के लिए हों, वे देश में अलगाव को बढ़ाएंगे और वह अलगाव बहुत अच्छा नहीं होगा। आज भी जो परिस्थिति है देश में, सेपरेटिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, एक माइंड सेट जिस तरह से पैदा हो रहा है, मैं सदन से, देश से हाथ जोड़कर यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि उस बढ़ाने की तरफ न बढ़े उसको एक करें। हमने भी किया था मॉयनोरिटी एजुकेशन के लिए। हमने कहा था कि हर मदरसे को भी हम एक साइंस टीजर और एक मैथमेटिक्स टीचर देंगे। मुझे खुशी होती अगर आज यह बताया जाता कि हमारी तुलना में दोगुने, तीन गुने मदरसों को आपने साइंस टीचर्स दिए हैं। हमने कम्प्यूटर सेंटर दिए थे। हमें खुशी होती अगर यह बताया जाता कि मॉयनोरिटीज के लिए इतने और कम्प्यूटर सेंटर खोले गए हैं। खत्ताति के लिए हमने कम्प्यूटर सेंटर दिया था उसे आपने बंद कर दिया। बड़े जोर से कहा जा रहा है कि उर्दू के लिए दस करोड़ से तेरह करोड़ कर दिया।

मैंने एक करोड़ से दस करोड़ किया था। उर्दू यूनिवर्सिटी हम लोगों के जमाने में बनी थी। तो यह सवाल कहना कि मॉयनोरिटी के हित के लिए आप ला रहे हैं, आप हाथ न हिलाएं, जस्टीकुलेट न करें, मैं जानता हूं जयराम जी आपको इससे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आप मॉयनोरिटी के लिए कुछ काम करें, वहां शिक्षा को फैलाएं, उसका इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। मैं मुसलमान भाइयों से तो साफ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि जरा गौर करके देखें कि इससे इनको मिलेगा क्या। जो तमाम भाइयों ने बात कही है बिल्कुल सही बात कही है। इससे कुछ नहीं मिलने वाला। और उनके लिए यह एक धोखे की टट्टी साबित होगा। इसलिए इस बात को गहराई से समझ लें। और इस बात पर भी गौर करें कि मुसलमान भाई के नाम पर अगर आप समझते हैं कि आप मुस्लिम मॉयनोरिटी के तौर पर कुछ उसके लिए ऐसे कानून बनाकर उनकी तरक्की कर सकेंगे, यह बिल्कुल गलत होगा। यह तो महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि धर्मान्तरण होने से किसी आदमी की मॉयनोरिटी और मैजॉरिटी नहीं बदलती और मैं समझता हूं बिल्कुल सही बात कहते थे। इस देश में इस आधार पर कोई मॉयनोरिटी आज तय नहीं की जा सकती कि वह मस्जिद में जाता है या मंदिर में जाता है। फिर तो तरह-तरह की रिलिजियस मॉयनारिटीज निकलेंगी। दूसरे, लिंग्वेस्टेक मॉयनारिटी का इसमें कोई किसी तरह से जिक्र नहीं। कैसे डिटरमिन करेंगे? लिंग्वेस्टेक मॉयनारिटी के मामलों के लिए भी क्या यही कमीशन तय करेगा? इस कमीशन के अंदर जो आपने लोगों को रखा है उसमें कोई भी लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं है, एक हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और दूसरे हैं, एमिनेंट पर्सन भी हो सकता है, वह कोई व्यापारी भी हो सकता है, उद्योगपति भी हो सकता है, फिल्म का कलाकार भी हो सकता है। लेकिन उसमें एजुकेशनली क्वालिफाइड आदमी कौन हैं, यह भी समझ में नहीं आता। आपने स्टेट गवर्नमेंट के राइट को इम्पीड किया है, इसके अंदर। यह फेडरेल करेक्टर के ऊपर आघात करता है। इस बात को गहराई से सोचना चाहिए कि आप कैसा कानून बना रहे हैं। मॉयनोरिटीज कमीशन के अध्यक्ष ने अभी यहां पर बात की, उनके अधिकारों पर भी आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता से गुजारिश करना चाहता हूं कि यह नहीं होना चाहिए, इससे बहुत झगड़े बढ़ेंगे। मॉयनोरिटी का करेक्टर तय होगा यह जैसा अभी बताया ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: जोशी जी, अभी स्पेशल मेंशन भी लेने हैं, लोग इंतजार में हैं।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: मैं जल्दी खत्म करूंगा। मुझे अफसोस यह है कि जब मैं बोलता हूं तभी चेयर ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: नहीं-नहीं, ऐसा न कहें ...(व्यवधान)

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है मैं इसके खतरों से आपको कॉसन देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी निगाह में जो आज देश में अलगाववाद बढ़ रहा है, जो साम्प्रदायिक जहनियत बढ़ रही है, उसको और आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। अभी यह बताया गया और आजमी साहब ने बहुत सही बात उठाई कि मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए आगे बढ़ने की एजुकेशन के तौर पर बहुत मुश्किलात हैं और वे एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। उसके लिए ...(व्यवधान)

श्री वी॰ नारायणसामी: सर, ...(व्यवधान)

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: कृपया करके आप चुप रहें। मुझे उसके लिए यह निवेदन करना है कि यहां जितने हमारे मुसलमान मेम्बरान हैं, वे सब मिलकर जरा इस पर गौर भी तो करें कि यह क्यों हो रहा है। उसके जो कारण हैं, सही कारण हैं, उन पर भी सोचें। आप अपने यहां अवेयरनेस फैलायें और यह कहें कि भाई आपको माडर्न स्ट्रीम आफ एजुकेशन में आना है और सरकार से मैं यह कहूंगा कि उस माडर्न स्ट्रीम आफ एजुकेशन में लाने के लिए व्यवस्थाएं करे। वहां स्कूलों में बच्चे साइंस पढ़ें, विश्वविद्यालयों में जितने भी लोग हैं, उनको स्पेशल कोचिंग दी जाये, उनको स्कालरशिप दिये जायें, वे कम्पटीशन में बैठ सकें, इसके लिए आप कोचिंग की व्यवस्था करें। इस बिल से कुछ मिलने वाला नहीं है। एफिलिएशन कोई प्राब्लम नहीं है, प्राब्लम यह है कि उनको अवसर दिये जाने चाहिए। सब पिछड़े वर्गों को अवसर दिये जाने चाहिए, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, चाहे मुसलमान हो और चाहे कोई हो। आप उन तबको को, जिनका प्रतिनिधित्व समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नहीं है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रबन्ध क्या कर रहे हैं? वे प्रबन्ध ज्यादा जरूरी हैं और इस बिल में उन प्रबन्धों का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और जैसा राम जेठमलानी जी ने कहा कि यह कांस्टीट्यूशनल प्रावीजन्स का भी एक तरह से विरोध करता है। बेहतर यह हो, आज आप इस विधेयक को वापिस करें, बहुत संजीदगी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, एक कम्प्रेहेंसिव बिल लायें, तब उस पर विचार होगा कि भाई किस तरह से आप इन पिछड़े समुदायों की, वे चाहे किसी भी जाति में हों, शिक्षा में कैसे वृद्धि कर सकते हैं। मुझे इस बारे में आपसे फिर बार-बार यह कहना है कि किसी भी तरह से, कोई काम जो अल्पसंख्यकवाद को बढ़ाये और देश को विभिन्न जातियों, धर्मों, सम्प्रदायों में बांटे और भाषाओं में बांटे, वह खतरनाक होगा। हम एक बार पहले भी इस मुल्क में उस खतरे को भुगत चुके हैं, वह खतरा दुबारा नहीं आना चाहिए। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं और इसलिए इस बिल का विरोध करता हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इन तमाम बातों को जो यहां सामने रखी गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, इस बिल को वापिस करें। और एक बात, जब आप किसी माइनारिटी इंस्टीट्युशन को इतने अधिकार दे रहे हैं, तो उसका स्टैंडर्ड कौन तय करेगा? वह एआईसीटीई के परव्यु से बाहर हो गया, वह आई एम सी के परव्यु से बाहर हो गया, वह यूनिवर्सिटीज़ के परव्यु से

5-00 P.M.

बाहर हो गया, अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको हम एफिलिएशन नहीं दे रहे हैं, कुछ कारण बताती है, फिर कोई अपील करता है और कमीशन की राय में यह आया कि हां, इसको देना है, इसको तो देना ही है, तो फिर ये सारे स्टैंडर्ड खत्म हो गये। आप क्यों यह बात करना चाहते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्युशन का स्टैंडर्ड अलग है, अंतर है और वहां से पढ़ा हुआ लड़का या लड़की नेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं आता, तो आप इन तमाम बातों पर गौर करें, संविधान की भावना पर गौर करें। ये बेसिक फीचर थ्यौरी के खिलाफ जाता है, ये सेक्युलर कैरेक्टर के खिलाफ जाता है, ये अलगाववाद को बढ़ावा देता है, ये राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है, ये उन तमाम संस्थाओं के, जैसे-यूजीसी वगैरह हैं, उनके परव्यु से आपको बाहर कर देता है और वे सिर्फ जनरल इंस्टीट्युशन्स को देखने के लिए रह जायेंगे। यह क्या बात हो रही है? वर्षों से जो संस्थाएं चल रही हैं, जो इस काम को अंजाम दे रही हैं, आपने फैसला कर दिया कि सब निकम्मी हो गई, ये सब नाकाबिल हैं, यह इस देश में शिक्षा की व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकतीं, यह क्या बात हो रही है? ...(समय की घंटी)... हम अपनी सारी संस्थाओं के प्रति इस तरह से अविश्वास पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह देश-हित में बिल्कुल नहीं है और मैं फिर यह अपील करूंगा कि इस अलगाववादी मानसिकता को, जिसमें खासतौर पर अल्पसंख्यकों को अलग करने की कोशिश की जाती है, इसको आप वापिस करें। मैं इसके निरनुमोदन करने के प्रस्ताव का फिर से जोरदार अपील करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इस बात पर गहराई से विचार करेगा और इस विधेयक को वापिस लेगा।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: उपसभापति महोदय, आज विस्तार से सभी संसद सदस्यों ने यहां बात रखी, जिनमें श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे साहब, मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी साहब, श्री विजय राघवन साहब, श्री शाहिद सिद्दिकी साहब, श्री रवि शंकर प्रसाद जी, डा॰ के॰ मलयसामी साहब, श्री एम॰ पी॰ ए॰ समद समदानी साहब, श्री मोतिउर रहमान साहब, डा॰ राधाकांत नायक साहब, श्री प्रेमचन्द्रन साहब, श्रीमती सईदा अनवर तैमूर साहिबा, श्री राम जेठमलानी साहब, श्री तरलोचन सिंह साहब, श्री अबू असिम आजमी साहब और आखिर में हमारे सीनियर लीडर डा॰ मुरली मनोहर जोशी साहब ने अपनी बातें रखीं। मैं अब सभी, जितने संसद सदस्यों ने यहां सवाल उठाये हैं, सबका अलग-अलग जबाब देना मुश्किल है और मैं नहीं चाहूंगा कि यहां पर, जो इधर से खासतौर पर उठाये गये, वोट बैंक की बात कही गई, शाहबानों केस का मामला उठाया गया...। अंडर वर्ल्ड से इस बिल को जोड़ा गया, टेररिज्म की बात आई और इधर से कुछ साथियों ने अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी को भी इस बिल से जोड़ा। यहां तक कि सर्व शिक्षा अभियान का भी मसला इस बिल के साथ जोड़ा गया। मैं इन सवालों के जवाब में न जाते हुए यह बताना चाहूंगा कि इस बिल की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। बाकी जो सजेशंश आए हैं, चाहे वह माइनॉरिटीज की डेफीनेशन का मामला हो कि माइनॉरिटीज

कौन होंगे, सेंटर-स्टेट के रिलेशन के बारे में सवाल उठे, बहुत सारे संसद सदस्यों ने, खास तौर से अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बन जाएगा तो उसका मिसयूज होगा, उसके बारे में भी बात आई। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जब या बिल पास हुआ था, 11 नवम्बर 2004 में, उसके बाद जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आयी तो उसमें यह महसूस किया गया कि कुछ कमियां उस एक्ट में रह गयी थीं और तकरीबन 350 एम्लीकेशंस मुख्तलिफ जगहों से कमीशन के पास आयीं। जब उसके अंदर चीजों को देखा गया और जब जानकारी ली गयी तो जो दो-तीन मुश्किलें आयीं, उनमें सबसे बड़ी मुश्किल थी - ''नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट'' जो स्टेट ईश्यू करती है। अब हो सकता है कि कुछ राज्यों के अंदर आसान हो, दे देते हों लेकिन कई राज्य ऐसे हैं, जहां पर ज्यादा मुश्किलें हैं। एक तो ''नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट'' सबसे बड़ा मसला था। जो पहला एक्ट था, उसके अंदर हमने लिमिट की थी कि 6 यूनिवर्सिटीज के अंदर ही जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एफिलिएशन होगा। अब केरल का कोई कॉलेज अगर दिल्ली में एफिलिएशन लेगा तो उसको मुश्किलें होंगी। उस दायरे को बढ़ाने के लिए भी यह बिल लाया गया है। मेरे ख्याल से ये दो बड़े रीजन्स थे जिनकी वजह से इस बिल को दोबारा लाना पड़ा है। सर, सह बात दुरुस्त है कि 13 अगस्त को यह बिल हम लोग अमैंडमेंट के लिए इसी राज्य सभा के अंदर लाए थे। बाद में इसको स्टैंडिग कमेटी को भेज दिया गया था और उसकी भी कुछ रिकमेंडेशंस आयी। उन पर भी मंत्रालय ने कंसिडर किया और उसके बाद यह कंप्रीहेंसिव बिल आज सदन के सामने है। हमारे एक साथी ने उधर से कहा कि जब स्टैंडिग कमेटी की रिकमेंडेशन हुई तो उससे पहले आर्डिनेस कैसे आ गया? ऑर्डिनेंस उसके बाद आया है और आज जो बिल है, उस ऑर्डिनेंस के बाद है, सभी लोगों को मालूम है। मैं यहां पर सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब यूपीए की सरकार बनी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बनी तो एक कमिटमैंट इस सरकार का, यूपीए सरकार का था कि सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म के लिए जो कुछ करना होगा, किया जाएगा, उसमें न किसी से दबने का मामला है, न किसी से समझौते का मामला है। वह कमिटमैंट आज भी है। सिर्फ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन ही नहीं, और भी कई इकदामात उठाए गए है, जो आप लोगों के सामने हैं। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें जो भी मामले एनओसी के आएंगे - ऐसा नहीं है कि स्टेट से नहीं पूछा जाएगा - लेकिन अगर कोई राज्य के पास जाता है, अपनी दरख्वास्त देता है और दरख्वास्त देने के बाद उसको कूड़ेदान में डाल दिया जाता है, उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती, ऐसे मामलों में 60 दिन के बाद - वह अगर जवाब दे दे, मना करे तो एक पोजीशन हो सकती है, नहीं दे तो दूसरी पोजीशन है- इन दोनों हालात में यह कमीशन के पास आ सकता है, अपनी दरख्वास्त दे सकता है।

जहां तक सवाल पैदा होता है कि इस बिल का फायदा होगा या नहीं होगा, तो अभी तो बिल पास होगा? एक्ट बनेगा और उसके बाद इसके जो नतीजे आएंगे, उनको भी हम देखेंगे। उसके बाद भी

अगर जरूरत पड़ेगी, तो फिर हम आपके सामने आएंगे और क्लीयर कट इसके अंदर सीधे-सीधे यह है कि इसके एक्ट बन जाने के बाद माइनॉरिटी को फायदा होने वाला है। इसमें हम सिर्फ मंत्रालय में बैठकर नहीं, माइनॉरिटी कम्युनिटी - इसमें सभी लोग आते हैं - इनसे बातचीत करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं।

महोदय, कई जगहों से सवाल उठा कि आखिर माइनॉरिटी होगा कौन? तो अभी तक जो हमारा पिछला बिल था, उसमें हमने पांच कम्युनिटीज को माइनॉरिटी कम्युनिटी माना था - मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट and Zoroastrian, पारसी, लेकिन अब अगर किसी राज्य में, मानो पंजाब में अगर हिन्दू माइनॉरिटी में हैं, तो उसको भी हम देख लेंगे और इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन करके जिस राज्य में, जैसे कश्मीर में, हिंदू माइनॉरिटी में हैं, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में हैं, इसी तरह से नागालैंड में हिंदू माइनॉरिटी में हैं, जिस राज्य में जो माइनॉरिटी में होगा, उसको भी हम कंसिडर करके, उसका अलग से नोटिफिकेशन करके उसको मान्यता देंगे।

जहां तक सवाल पैदा होता है स्टेट्स से रिलेशन्स का, राघवन साहब ने जो बात वहां पर रखी थी, उसको हमने कंसिडर किया है और अमेंडमेंट के रूप में हमने इस बात को रखा है कि स्टेट्स से भी जब कमीशन में बात आएगी, NOC के सिलसिले में या affiliation के सिलसिले में, तो स्टेट की बात भी हम लोग सुनेंगे और तभी किसी फैसले पर हम लोग जाएंगे, उसको भी हमने अमेंडमेंट में शामिल किया है।

अब कुछ सवाल इधर से उठा था और कई लोगों ने उठाया कि माइनॉरिटी इंस्टीटयूशन में गरीब लोगों के लिए या जो मुसलमानों में बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए - यह सब इस बिल के अंदर नहीं आता है। यह तो अलग से डिसकशन की चीज है। वक्त आने पर, जरूरत पड़ने पर उसको भी हम लोग बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करेंगे।

तो कुल मिलाकर, मैं सदन से यही अपील करना चाहूंगा कि यह जो बिल आज सदन के सामने लाया गया है, उसका सीधा मकसद है कि जो कमिटमेंट है यू॰पी॰ए॰ का और इस सरकार का, कि सामाजिक न्याय, सामाजिक इंसाफ और सेक्युलरिज्म के लिए जो भी कदम उठाने हैं, ये हम उठाएंगे और माइनॉरिटी education के लिए, अकल्लियत को आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम मुमकिन है, वे हम करेंगे और उसी दिशा में यह एक और कदम है और मुझे उम्मीद है कि पूरा सदन, मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस बिल को एक खास अच्छी इंटेंशन के लिए लाया गया है, इसलिए सभी मिलकर इस बिल को समर्थन दें, मदद दें और इसको पास करें, बहुत-बहुत शुक्रिया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put the Resolution moved by Dr. Murli Manohar Joshi to vote. The question is:

"That this House disapproves the National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Ordinance, 2006 (No. 1 of 2006) promulgated by the President on the 23rd January, 2006."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Motion moved by Shri Md. Ali Ashraf Fatmi to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall not take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause 3. In clause 3, there are two amendments (Nos. 3 and 4) by the hon. Minister.

Clause 3 - Substitution of new Chapter for Chapter III

SHRI MD. ALI ASHRAF FATMI: Sir, I move:

(5) That at Page 2, line 26, for the word "sixty", the word "ninety" be substituted.

(6) That at page 3, after line 7, the following proviso be inserted, namely:-

"Provided that such authorised person shall have right to know the status of such application after the expiry of sixty days from the date of filing of such application."

The questions were put and motions were adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 4, there is one amendment (No. 6) by the hon. Minister.

Clause 4 - Amendment of section 11

SHRI MD. ALI ASHRAF FATMI: Sir, I move:

(6) That at page 4, line 25, ***after*** the words "opportunity of being

heard", the words "in consultation with the State Government" be inserted

The question was put and the motion was adopted

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

Clauses 5 to 9 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have a new clause 10. Hon. Minister to move.

Insertion of New Clause 10 - Repeal of Ordinance 1 of 2006 and saving.

SHRI MD. ALI ASHRAF FATMI: Sir, I move:

5. That at Page 5, *after* line 44, the following new clause be *inserted*, namely:-

"10. (1) The National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Ordinance, 2006, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act."

The question was put and the motion was adopted.

New Clause 10 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we shall take up clause 1. In clause 1, there is one amendment (No. 2) by the hon. Minister.

Clause 1 - Short title and commencement

SHRI MD. ALI ASHRAF FATMI: Sir, I move:

2. That at page 1, *for* lines 3 and 4, the following be *substituted* namely,-

"1. (1) This Act may be called the National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Act, 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 23rd day of January, 2006."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN. We shall now take up the Enacting Formula for consideration. There is one amendment (No. 1) by the Minister.

Enacting formula

SHRI MD. ALI ASHRAF FATMI: Sir, I move:

1. That at page 1, line 1, *for* the word "Fifty-sixth", the word "Fifty-seventh" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI MD. ALI ASHRAF FATMI: Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Government of Union Territories and the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2006

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha.

> "In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 1st March, 2006, agreed without any amendment to the Government of Union Territories and the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2006 which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 24th February, 2006."